राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का चौथा दिवस** **संख्या: 2**

सोमवार,

03 फरवरी 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल। पहले प्रश्न काल।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ज्ञान के चाणक्य से कब दोस्ती करायेंगे? आप हमें बता दें।

श्री अध्यक्षः वह भी करते हैं। श्री चेतन पटेल कोलाना।

पीपल्दा में अतिवृष्टि के कारण फसल खराबे का मुआवजा

1. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ष 2024 में अतिवृष्टि से फसल में 50 प्रतिशत का खराबा हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशासन द्वारा मुआवजा हेतु प्रस्ताव विभाग को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने किसानों को मुआवजा दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज) (कृषि मंत्री के स्थान पर): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ष 2024 (संवत् 2081) में बाढ़ से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है।

(2) जी हां। जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7डी रिपोर्ट के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों में कुल 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ है तथा 24,801 प्रभावित काश्तकारों हेतु एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रभावित काश्तकारों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान

किये जाने हेतु दिनांक 27.01.2025 को दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। प्रभावित काश्तकारों के डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड कर, उनको शीघ्र कृषि आदान अनुदान भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब मेरे पास पहुंच चुका है। मैं दो पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा परन्तु उससे पहले आपके संरक्षण की अति आवश्यकता है। मेरे पहले प्रश्न में विभाग से पूछा गया था कि क्या पीपल्दा क्षेत्र में पचास प्रतिशत से ज्यादा अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है? विभाग ने बताया है कि 33 प्रतिशत या उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है, उस 33 प्रतिशत पर जोर दिया गया है ताकि 33 संख्या में कम लगे जबकि वास्तविक रिपोर्ट यह है कि 60 प्रतिशत ओन एंड एवरेज पीपल्दा क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, जिस रिपोर्ट की प्रति मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहूंगा।

इसी प्रकार मेरे दूसरे प्रश्न में विभाग ने खुद उत्तर में बताया है कि 24,801 किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक...।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अभी तक सरकार द्वारा राहत के रूप में एक फूटी कौड़ी भी किसानों को नहीं दी गई है। और तो और बड़ी चतुराई के साथ....।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह तो आपने कहा कि मेरे पास है, आप प्रश्न पूछो न जो पूछना है। आप जो चाहते हो, प्रश्न पूछो।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है ...(व्यवधान)... प्रश्न का औचित्य ही नहीं है, डांवाडोल करके जवाब दिया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ये सक्षम हैं। अभी उनका नम्बर होने दो। माननीय मंत्री जी देंगे जवाब।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): मैं प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। बैठिये।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): प्रश्न पूछूंगा पर जो गलत जवाब दिया है बड़ी चतुराई के साथ, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। बैठिये। पहले प्रश्न में व्यवधान नहीं। बैठिये। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के न इधर से लोग बोलेंगे न उधर से। उत्तर आ रहा है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी चतुराई के साथ मेरे प्रश्न पूछने के बाद 27.01.2025 को...।

श्री अध्यक्ष: आप क्या पूछना चाहते हो? यह बताओ।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): किसानों के कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिये। यह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि लॉटरी में मेरा प्रश्न लग गया। क्या किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न पूछो।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इतना सा है...।

श्री अध्यक्ष: हां, वह पूछो।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा पर जो जवाब डांवाडोल करके चतुराई के साथ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): उसका तो जवाब कोई न कोई देगा सदन में।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो न उसमें, आपको मना थोड़े ही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछें किससे?

श्री अध्यक्ष: यह काम मेरा है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न किससे पूछें?

श्री अध्यक्ष: उत्तर दिलाना मेरा काम है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): किसानों के प्रति सरकार कितनी गम्भीर है इसका प्रमाण यह है कि माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रश्न पूछना भी नहीं आता, प्रश्न पूछना तो पहले शुरू करें।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे को...।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, संसदीय मंत्री यहां पर हैं उसके पहले आप खड़े नहीं होंगे। यह काम आपका नहीं है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): मेरा पहला प्रश्न यह है कि समय-सीमा बताने का कष्ट करें कि किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहूंगा, पहला इनका प्रश्न है उसमें हमने कहा जी, हां। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले मंत्री की छुट्टी तो स्वीकृत कराओ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: ये मेरी अनुमति से दे रहे हैं। बार-बार खड़े नहीं हों। मेरी अनुमति से हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह हर बात में खड़े हो रहे हैं। यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो गये, आप बैठो। यह काम मेरा है। माननीय सदस्य, यह मेरा काम है, मेरा काम आपको नहीं मिला है। यह काम मेरा है। सदन हैंडल करना मेरा काम

है।

मैं माननीय सदस्यों से, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं और उनसे भी कर रहा हूं, दोनों बिना अनुमति के खड़े न हों। कोई कहीं व्यवधान आयेगा तो मैं बैठा हूं। किससे उत्तर दिलवाना है यह मेरा काम है। चलिये।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं, मैंने पहले प्रश्न में कहा है कि जी हां। जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7डी रिपोर्ट के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों में...।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): यह जवाब तो मिल चुका है जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर तो सुन लो फिर जवाब न मिले तो दुबारा आप पूछना।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): हां, उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ है, मैं यह पढ़ रहा हूं। आपने जो पूछा कि हमारे वहां खराबा कितना हुआ है तो मैंने बताया है 25,458 हेक्टेयर में आपके फसलों का खराबा हुआ है, उसमें 24,801 प्रभावित किसान हैं जिनको नुकसान हुआ है, उसके एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): किस तारीख को?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है। आपको जवाब भी दूंगा मैं। प्रभावित काश्तकारों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान किये जाने हेतु दिनांक 27.01.2025 को दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। ...(व्यवधान)... पहले बात तो सुनिये। आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर सुन लीजिये बाद में कोई रह गया हो तो दूसरा प्रश्न पूछिये बीच में नहीं।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): प्रभावित काश्तकारों के डॉटा डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं, उनको शीघ्र ही आदान अनुदान भुगतान करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। दूसरा आपका प्रश्न था कि आने वाले समय में हमारे पीपल्दा में 175 गांवों व दीगोद में 85 गांवों में बाढ़ से कुल 25,400 हेक्टेयर में 33 प्रतिशत नुकसान हुआ था, उसमें यह जो किसान प्रभावित हुए 24,801 उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जायेगा।

दूसरा, आपने जो पूछा, 27.01.2025 को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न और पूछ लो।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसमें लिखा हुआ था वह का वही पढ़ दिया। गम्भीर विषय है मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि

किसानों के प्रति यह सरकार कितनी गम्भीर है माननीय मंत्री जी ही उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिये। प्रश्न पूछो, भाषण नहीं।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो वह का वही पढ़ दिया।

श्री अध्यक्षः उत्तर तो आपने कहा किमैंने पढ़ लिया है। प्रश्न पूछो।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): ठीक है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है तो यह तो आपने फसलों का किया है निश्चित रूप से मकान भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। क्या मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसका मुआवजा भी सरकार देने का विचार रखती है क्या? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यों? मैं मकानों की बात कर रहा हूं जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, बैठिये।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मकानों का इस प्रश्न में कहीं उल्लेख ही नहीं किया परन्तु फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कलेक्टर के माध्यम से कोई आयेगा तो उसका भुगतान भी कर दिया जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अभी जवाब तो आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से पचास प्रतिशत खराबा हुआ था या नहीं हुआ था? मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि 33 प्रतिशत या इससे अधिक तो वह 33 का नहीं पूछ रहे हैं माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहे हैं तो आप बता दें कि 50 प्रतिशत कहां खराबा हुआ है? प्रश्न नं.एक।

दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया? संख्यात्मक विवरण रखिये। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ जब माननीय सदस्य का प्रश्न लग गया तो आपने कहा कि 27 जनवरी, 2025 को 6 दिन पहले जब प्रश्न लगा है तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिये। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी, यह बताइये आप मुआवजा कब तक दोगे?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान करता हूं पर जिस तरह से इन्होंने जो विधान सभा में प्रश्न लगाया है वह पीपल्दा का लगाया है और उससे भी आगे चल कर अगर आप...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं पीपल्दा का ही पूछ रहा हूं। मैं बाहर का नहीं पूंछ रहा हूं।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): सुनिये। मैं पीपल्दा का ही जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्षः केवल पीपल्दा का उत्तर दीजिये बाकी का नहीं।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): हां, मैं पीपल्दा का ही उत्तर दूंगा और

इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः नहीं, आप केवल पीपल्दा का दो, माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पीपल्दा का ही बता दो, साहब।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मेरे पास सभी जवाब है तो जैसा कि आपने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में बीस जिलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत नुकसान हुआ था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हैं हम। पीपल्दा का बता दो आप।

श्री अध्यक्षः आप विराजिये न। उत्तर सुन लो। हां, बता देंगे आप सुनो तो सही। एक ही प्रश्न पर पूरा समय कराना चाह रहे हो क्या आज? तय कर लो।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं आपको बताना चाहता हूं पीपल्दा का, पीपल्दा तहसील में 175 गांवों में, दीगोद में 85 गांव और कुल मिला कर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था उसमें 33 प्रतिशत फसलों का खराबा हुआ है उसका हमने तुरन्त कलेक्टर के माध्यम से हाथोंहाथ ही आदान-प्रदान करके उसका अनुदान देने की प्रक्रिया चालू कर दी है और जल्दी ही हम उसका भुगतान करेंगे।

msk/rtm/03.02.25/1110/1b

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री यूनुस खान। ..(व्यवधान).. हो गया, एक क्वेश्चन पर दस मिनट हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये यह बता दें कि क्वेश्चन नंबर एक में पूछा कि 50 परसेंट जो खराबा हुआ है, वह संख्या दे दें। ..(व्यवधान).. ऐसे नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 33 से ज्यादा होता है, 50 हो या 75 हो, कितना ही हो।..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय, बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हो गया, बहुत हो गया, +++ बैठ जाइये। ..(व्यवधान).. आप बैठिये।

श्री अध्यक्षः बैठिये। अगला प्रश्न। श्री यूनुस खान।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जो बता रहे हैं, मैं 50 परसेंट का भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। जो भी बात करेंगे, उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः हो गया। श्री युनुस खान।

डीडवाना औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा भू-खण्ड का आवंटन

2. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डीडवाना में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कब व कितने क्षेत्रफल में की गई है?

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में कितने भू-खण्ड कब-कब आवंटित किए गये? आंवटितों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रीको द्वारा भू-खण्ड आवंटन करने के क्या नियम हैं? क्या उक्त क्षेत्र में नियमानुसार भू-खण्ड आंवटित किये गये हैं? क्या नियमानुसार उद्योग प्रारम्भ हो गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में रिक्त भू-खण्डों पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब जवाब नहीं आया ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, यह काम मेरा है। मेरा काम करने की कोशिश मत करो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये खड़े क्या हुए? ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: जरूरी थोड़े ही है, न ये होंगे, न आप होंगे।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी हां। डीडवाना में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र, डीडवाना की स्थापना वर्ष 1998 में 31.38 हैक्टेयर भूमि पर की गयी है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में 124 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन वर्ष 2005-06 से शुरू किया गया था। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित सभी भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। आवंटित भूखण्डों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन रीको भू-निपटान नियम (रीको डिस्पोजल ऑफ़ लैंड रुल्स), 1979 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 3 के अनुसार किया जाता है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आवंटन तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र, डीडवाना को दिनांक 06.07.2017 को अर्द्धविकसित (सेमी डवलप्ड) घोषित किया गया था।

निगम नियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखण्डों पर आवंटन की तिथि अथवा विकसित/ अर्द्धविकसित घोषित करने की तिथि (जो भी बाद में हो) से 03 वर्ष में उद्यमियों को भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक है।

उक्त औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में 58 भूखण्ड उत्पादनरत हैं, 18 भूखण्ड निर्माणाधीन हैं, 1 भूखण्ड, भूमि की कीमत जमा न करवाने के कारण नियमानुसार निरस्त किया जा चुका है एवं 47 भूखण्ड रिक्त हैं। आवंटित भूखण्डों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में रिक्त पड़े भूखण्डों के आवंटियों को निगम नियमानुसार कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं। आवंटियों द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने एवं प्राप्त

जवाब संतोषप्रद होने पर रीको भू-निपटान नियम, 1979 के अन्तर्गत धारण प्रभार शुल्क (Retention Charges) के भुगतान पर सक्षम स्तर से समयावधि विस्तार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

आवंटी द्वारा जवाब नहीं दिये जाने अथवा असंतोषप्रद पाये जाने पर भूखण्डों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह 1998 का औद्योगिक क्षेत्र है और इन्होंने जो भूखण्डों की खाली संख्या बतायी है, वह तो काफी है, 50 परसेंट के करीब है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से क्वेश्चन यह है कि क्या इस इंडस्ट्रीयल एरिया में पीने के पानी, बिजली, चूंकि यहां पर बिजली ग्रामीण क्षेत्र से आती है, इसलिए इंडस्ट्रीज को बिजली नहीं मिलती है तो क्या डेडिकेटेड बिजली की अलग से व्यवस्था करेंगे? यहां इसके पास डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। क्या उसको हटाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी? यहां पर मरे हुए जानवर भी डालते हैं। मेरी ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं में पीने का पानी, बिजली और डंपिंग यार्ड, मरे हुए जानवरों को डालना है। जो टूटी हुई सड़कहै, क्या उसको ठीक करने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यूनुस खान साहब ने जो खाली भूखण्डों की बात की है और इस पर भी इंफेसाइस किया है कि 1998 से यह औद्योगिक क्षेत्र था। 2017 के अन्दर इसको सेमी-डवलप घोषित किया था। उसके बाद कोविड का समय भी आया और इस कारण से यहां पर आज की तारीख में, जैसे उन्होंने संख्या बतायी है, वे जानते हैं कि करीब 47 भूखण्ड खाली हैं और 58 भूखण्डों के ऊपर उत्पादन हो रहा है। हमने खाली भूखण्डों को नोटिस भी दे दिये हैं और उनका जब जवाब आयेगा, उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी यहां पर जो पानी की समस्या है, उसी कारण से इसको सेमी-डवलप्ड घोषित किया था। हमारी सरकारी, पीने का, सिंचाई, इंडस्ट्री के पानी की पूरी सुविधा कर रही है, जल्द ही यहां पर पानी भी उपलब्ध हो जायेगा। उसके साथ-साथ बिजली का और वहां पर जो डंपिंग यार्ड है, उसकी जो चर्चा की है, मैं उसको दिखवा लूंगा। निश्चित रूप से उसके ऊपर जो सोच-समझकर कार्यवाही होगी, उसको हम करवा देंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिखवा लेंगे। मेरा आग्रह है कि यह 1998 का एरिया है, उसको चलाना है तो ये सारी सुविधाएं अपने को देनी पड़ेंगी। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि उस पर माननीय मंत्री जी शीघ्र ही कोई टीम भेजकर उस पर कार्यवाही करायें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि हमारा मकराना, डीडवाना, परबतसर और राजास जो इंडस्ट्रीयल एरिया हैं, जब रिडकोर का मेगा-हाइवे बना था। उस समय बाहर के लोगों ने, मैं पर्टिक्यूलरली कहूंगा कि दिल्ली के लोगों ने प्लाट्स ले लिये। वे लोग बिजनस करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले लोग नहीं

हैं। उन पर अगर आप सख्ती से कानूनन कार्यवाही नहीं करेंगे, तबतक न तो मकराना का इंडस्ट्रीयल एरिया डवलप होगा, न डीडवाना का होगा, न परबतसर का होगा और न राजास का होगा। आप देखिये कि हमारे इस एरिये में 354 प्लाट खाली हैं, क्योंकि यह मेगा-हाइवे पर है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसके लिए एक टीम भेजकर मैंने जो समस्याएं बतायी हैं, उन पर कार्यवाही करवायें। ये जो खाली भूखण्ड हैं, इनके लिए शीघ्र कार्यवाही करें, जिससे दूसरे लोग आकर अपनी इंडस्ट्री लगा सकें।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि अक्सर यह बात होती है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर इंडस्ट्रीयल एरिया की जमीन ली गयी थी, इतने लंबे समय से। हम सब प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन हम प्लॉट खरीदते ही उसके ऊपर मकान नहीं बना लेते हैं। कई बार हम सही कीमत पर प्लॉट मिल रहा होता है तो आगे के लिए ले लेते हैं। आज की तारीख में इंडस्ट्री के लिए जमीन उपलब्ध कराना अत्यंत मुश्किल है। पहले के समय में जो जमीन ली हुई है। सही समय पर उसको डवलप करेंगे। आपके क्षेत्र के अन्दर अगर कोई इंडस्ट्री आ सकती है तो आपका स्वागत है। आप बताइये, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पर क्लस्टर के रूप में या इंडस्ट्रीयल प्लॉट के रूप में उसको डवलप करे। माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं वहां पर जरूर टीम भिजवाऊंगा और उसको पूरी तरह से दिखवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक। श्री घनश्याम।

आर.टी.ई. के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश

श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के उपरान्त निजी विद्यालयों में सामाजिक रूप से पिछड़े व कमजोर आय वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है? यदि हां, तो जिला करौली में विगत 3 वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं को उक्त कानून के तहत प्रवेश दिया गया? वर्षवार व विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला करौली में उक्त कानून के तहत विगत तीन वर्षों में प्रवेश देने वाले कितने विद्यालयों को कितना- कितना भुगतान किया गया? वर्षवार व विद्यालयवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त कानून के तहत प्रवेश नहीं देने वाले विद्यालयों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार को उक्त कानून के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से शुल्क वसूली के प्रकरण प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। करौली जिले में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विगत 3 वर्षों में दिये गये प्रवेश का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	सत्र	आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश
1.	2021-22	2523
2.	2022-23	4740
3.	2023-24	7024

उक्त का वर्षवार व विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) करौली जिले में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विगत 3 वर्षों में प्रवेश देने वाले विद्यालयों को किये गए भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	सत्र	आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश देने वाले विद्यालयों की संख्या	पुनर्भरण की गई राशि (करोड़ों में)
1.	2021-22	552	14.33
2.	2022-23	534	14.84
3.	2023-24	517	15.51

उक्त का वर्षवार व विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में बालकों के आवेदन से लेकर प्रवेश प्रक्रिया तक सम्पूर्ण कार्य ऑनलाइन है। कोई भी गैर सरकारी विद्यालय किसी भी बालक का आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश होने पर प्रवेश को रोक नहीं सकता है।

(4) प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक शुल्क वसूली के प्रकरण विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों के आरटीई पुनर्भरण के संबंध में याचिका संख्या 792/2023 न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त याचिका के निर्णय अनुसार पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों के शुल्क वसूली के संबंध में परिवेदना का निस्तारण किया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षान्तर्गत उक्त कानून के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से शुल्क वसूली के प्रकरण विभाग को प्राप्त हुए है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्राप्त शिकायतों के क्रम में विभाग स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि अभी ऐसे बहुत सार प्राइवेट स्कूल हैं, जिनको पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट के अभाव में उन्होंने बच्चों का एडमिशन लेना बंद कर दिया है। मेरे पास इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन रहा है कि जिन विद्यालयों ने बच्चों का एडमिशन नहीं लिया है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान राजस्थान सरकार ने 900 करोड़ आरटीई के तहत दिये हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने यह भुगतान नहीं किया था। 2018-19 का नहीं किया था, 2019-20 का नहीं किया था, 2020-21 का नहीं किया था,

2022-22 का नहीं किया था, 2022-23 का नहीं किया था। हमने वह भुगतान किया है। इन्होंने नहीं किया और अभी भी 800 करोड़ के आसपास बकाया है। उनका भी हम शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न पूछना है?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह रहेगा कि उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? दूसरा प्रश्न यह है कि आपने बच्चों के एडमिशन के आंकड़े दर्शा दिये हैं। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि वे बच्चे कौन-कौनसे हैं, जिनका प्राइवेट स्कूलों ने आंकड़े दिये हैं कि इतने बच्चे लिये। उन बच्चों की संख्या और नाम भी आप सदन को बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: क्या इतने नाम बता सकते हैं? आप बतायें। माननीय सदस्य, यह अव्यावहारिक है कि नाम बताये जाएं, आप संख्या पूछ सकते हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, अव्यावहारिक नहीं है, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिन बच्चों का नाम ये दर्शा रहे हैं, वे बच्चे वहां पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: इस मुद्दे के लिए अलग से नियमों में आये, इस पर जरूर चर्चा करेंगे।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): शिक्षा विभाग में इसमें घपला हो रहा है, उस पैसे को खाने के लिए प्राइवेट स्कूल इस तरह के नाम दर्ज कर लेते हैं और वे बच्चे स्कूल में आते ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, भाषण नहीं। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं, उनकी निरन्तर समीक्षा होती है। इसकी जांच के लिए सीबीईओ होता है, वह उसको सत्यापित करता है, उसके बाद ही फाइनल एडमिशन होता है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। यह जरूर होता है कि वह कम परसेंट बच्चे ले ले। इसके कारण यह होता है कि जो ऑफलाइन आवेदन आते हैं, उनको एक तरफ रखते हैं और जब आरटीई का टाइम निकल जाता है, उसके बाद एडमिशन दे देते हैं। पर जैसा ये कह रहे हैं, वैसा होता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री विनोद कुमार।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित परिवार

4. श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वित्तीय वर्ष 2019 से 2023 तक उक्त योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितनों को लाभान्वित किया गया तथा कितने लम्बित हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लम्बित

आवेदकों को कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वित्तीय वर्ष 2019 से 2023 तक प्राप्त आवेदन पत्रों, लाभान्वितों एवं लम्बित आवेदनों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में उक्त योजना में सभी पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास क्वेश्चन का जवाब आ गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 2019-20 से लेकर 2023-24 तक कुल 541 आवेदन प्राप्त हुए। उसमें से 511 लाभान्वित हो गये। 30 लोगों का न तो इसके अन्दर कोई डाटा दिया गया कि निरस्त किये या किस तरीके से उनको निकाला गया, उस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष, पीलीबंगा से आने वाले मेरे मित्र माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कुल 541 आवेदन आये। उसमें से 511 को लाभान्वित कर दिया गया और जिन 30 के बारे में आपने कहा है कि जानकारी नहीं है। एक तो आप अपने घर का एड्रेस बता दें। पिछली बार मैं जूली जी के घर पर गया था, उत्तर देने के लिए आपके घर आ जाऊंगा। ये 30 लोगों के निरस्त की सूचना है, जो कि मैं आपको दे दूंगा और अगर आप कहें। ..(व्यवधान)..

Ans/rtm 11.20 1c 03.02.2025

श्री अध्यक्ष: इनका उत्तर पूरा हो जाए, फिर आप पूछना।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह 30 लोगों की सूची मेरे पास है जो आपके पीलीबंगा क्षेत्र के है। शोभाराम ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री सक्षम है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, इसमें क्या होता है शादी के 6 महीने तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। यह वह 30 लोग हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाए, या कुछ डाक्यूमेंट्स कम थे, तो जो अवधि निकल गई थी उसके कारण से इनका निरस्त कर दिया गया है। माननीय सदस्य, इसकी लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपकी जानकारी में रहे। आगे से इस कन्यादान योजना के लिए अभी हमने एक सर्कुलर 31.01.2025 को निकाला है जिसमें शादी की 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर हमने एक साल कर दिया है। कोई भी पात्र लाभार्थी है वह एक

साल में आवेदन कर सकता है। हमने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जल्दी ही यह 6 महीने की बाध्यता है वह एक साल हो जाएगी। आपके विधान सभा के यह 30 है उनकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है, उसको निरस्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्षः अगला कोई पूरक प्रश्न?

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): बस, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री गोपीचंद मीणा।

जनजाति वर्ग के पशुपालकों को टिनशैड निर्माण हेतु आर्थिक सहायता

5. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जनजाति वर्ग के पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन के रख-रखाव हेतु टिनशैड निर्माण के लिये नियम बनाकर आर्थिक स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि यहां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जी नहीं। सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन के एवं रख-रखाव हेतु टिनशैड निर्माण के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा नियम प्रावधान बनाकर आर्थिक स्वीकृति देने की वर्तमान में कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन के रख-रखाव हेतु टिनशैड निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव पशुपालन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने पर उनकी आवश्यकता, बजट की उपलब्धता एवं उपादेयता के आधार पर परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किसानों को, पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय व उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उन्नत करने के लिए टिनशैड निर्माण करने का आप पशुपालन विभाग से अनुदान दिलाने का अगर प्रस्ताव भिजवाते हैं तो मंत्री जी बताये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य की चिंता सही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी बी के तहत पशुपालन के लिए स्ट्रक्चर निर्माण यथा पशु आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, कुक्कुट आश्रय आदि के किए जाने का प्रावधान है। उक्त कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में लाभार्थी निजी भूमि पर किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित

है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से जनजाति वर्ग का सशक्तीकरण एवं दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित करना। योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत प्राप्त जनजाति पट्टा धारकों को भेड़, बकरी, मुर्गी एवं सुअर विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्राप्त गाइड लाइन के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: वह संतुष्ट है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय जनजाति मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि हमारे विभाग ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्वेश्चन में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं उत्तर दे रहा हूं, एक मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमें भी पता है भगवा पहन कर आये हो, आप में जोश है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में नहीं।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: जब माननीय सदस्य संतुष्ट है तो अगला प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट बोलने तो दीजिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह व्यवस्था का नहीं हुआ ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट बोलने तो दीजिए। जनजाति मंत्री जी ने जवाब दिया कि मेरे विभाग में नहीं है पशुपालन विभाग में है, तो यह जवाब पशुपालन विभाग के मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया। अगला प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह सरकार का जवाब है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको किसने कहा, आप बैठिये, आपके संसदीय मंत्री खड़े है ना। ऐसे थोड़े ही है कि हर प्रश्न में हम बोलेंगे। आपके मंत्री तय है। ...(व्यवधान)... मेरा काम है बैठाना, मैं बिठा रहा हूं ना। अगला प्रश्न, कांतिप्रसाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पशुपालन विभाग के मंत्री दें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। उत्तर हो गया। अगला प्रश्न।

प्रतापगढ़ (थानागाजी) तहसील के भवन का निर्माण

6. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में नव क्रमोन्नत तहसील प्रतापगढ़ का भवन निर्माण नहीं होने से कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है तथा ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार डीएमएफटी या अन्य मद से भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): तहसील प्रतापगढ़ का गठन राजस्व (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.07.2023 द्वारा किया गया।

नवक्रमोन्नत तहसील प्रतापगढ वर्तमान में रा.उ.प्रा.वि. प्रतापगढ़ संस्कृत विद्यालय प्रतापगढ़ में सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

तहसील कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास प्रश्न का उत्तर आ गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के अन्दर तहसील कार्यालय चला रखा है, वहां संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने तहसील भवन का निर्माण करवा दें, ताकि उन बच्चों का भविष्य सुधर सके।

श्री अध्यक्ष: हो गया प्रश्न?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब तो इनको मिल गया है। साथ में इन्होंने कहा है कि जो तहसील प्रतापगढ़ संस्कृत विद्यालय में चल रही है और वहां के उस विद्यालय की क्या स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासनिक दृष्टि से आने वाले समय में इस तहसील भवन के लिए जो भी राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा की दृष्टि में और संस्कृत विद्यालय की बात है वह दूसरी जगह व्यवस्था करके इसकी व्यवस्था करेंगे, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह विद्यालय चल रहा है उसमें मात्र चार कमरे हैं। सैकण्डरी स्कूल है, जर्जर स्थिति में है, कल को अगर कोई हादसा हो गया तो उन बच्चों की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। मैं आपके माध्यम से फिर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जगह स्कूल चल रही है उसमें चार कमरे हैं, पुरानी जगह है और हालत खराब है, इसलिए मेरा बार-बार आपसे निवेदन है कि उसकी बिल्डिंग स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इस पर गंभीरता से ध्यान दे। अगला प्रश्न। श्री ललित मीणा।

किशनगंज में किसानों की ऋण माफी

7. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2023- 24 में कोटा संभाग में कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2023 व 2024 में कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024) में कोटा संभाग में 55 किसानों का 53.76 लाख रूपये का ऋण माफ किया गया। विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2023 व 2024 में 23 किसानों का 13.97 लाख रूपये का ऋण माफ किया गया। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मेरे पास जवाब आ गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार सम्पूर्ण कर्जा माफी का वादा करके सरकार में आई। सरकार में आकर उन्होंने सम्पूर्ण कर्जा माफ नहीं करके दो लाख पर ही वह रुक गये। पिछले पांच साल में 2018 से 2024 तक मैंने उसमें पूछा, तो उसमें कोई ऋण दिया ही नहीं, तो कर्ज माफी कहां से। मेरा निवेदन है कि जब बारां सहकारी बैंक, हमारे केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, दोनों में से हम इनको सशक्त करना चाहते हैं क्या, ऋण देना चाहते हैं क्या? 2018 से 2023 तक कोई ऋण नहीं दिया। भूमि विकास बैंक में जो ऋण दिया जाता है वह काश्तकार के लिए ट्रोली, ट्रैक्टर के लिए दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मंत्री महोदय, वर्तमान स्थिति यह है कि वहां पर भूमि विकास बैंक में दो ही कर्मचारी है, तो क्या सरकार ऋण देने का विचार भी रखती है क्या? अगर रखती है तो हमारे बारां ज़िले में 2018 से 2024 तक नहीं दिया, उसमें देने का आश्वासन देती है क्या?

मैं दूसरा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, वर्तमान में सीसीबी में जो लिमिट है वह डेढ़ लाख तक की है। पिछले पांच साल में लिमिट में कितने किसानों को आपने उसमें डेढ़ लाख तक का ऋण दिया अभी? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक में इसको मर्ज करने का विचार रखते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो सीसीबी में इसको मर्ज करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य महोदय द्वारा नये ऋण के लक्ष्य की जो बात कही गई है, तो वहां के प्राथमिक भूमि विकास बैंक में जो वसूली है

वह 25 परसेंट से कम है तो इस वजह से वहां नये लक्ष्य, नाबार्ड की गाइड लाइन है, तो वहां नये टारगेट नहीं दिये जा सकते, इस वजह से वहां नहीं दिये जा रहे।

दूसरा, इन्होंने बताया कि वहां किसानों को डेढ़ लाख तक के ऋण उपलब्ध नहीं कराये जा रहे। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि वैसे तो बैंक अपनी वित्तीय तरलता एवं क्षेत्र के समस्त पात्र किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टिगत ऋण उपलब्ध करवाती है। बारां में 361 किसानों को हमने डेढ़ लाख तक का भी लोन दिया हुआ है।

इन्होंने मर्ज करने का पूछा, तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको को केन्द्रीय सहकारी बैंक के साथ मर्ज करने का जहां तक प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि यह एक नीतिगत निर्णय है। बैंकों की वित्तीय स्थिति, बैंकों की कार्यनीति, संसाधनों के मध्य नजर विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया?

ssy/rtm/03.02.2025/11.30/1d

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करुंगा कि जो बारां का हमारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है उसमें 2 एम्पलाई हैं। अभी सरकार ने एक सर्कूलर निकाला कम्प्यूटर खरीदने के लिए, जब कम्प्यूटर चलाने वाला ही नहीं है तो वहां कम्प्यूटर खरीदकर चलायेंगे कैसे? वहां आप बैंकों को या तो ऋण दें या काश्तकारों को ऋण दिलवायें, तब तो यह कम्प्यूटर खरीद सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वहां पर काम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसको सशक्त रखने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): निश्चित रूप से वहां पर ऋण वसूली का जो हमारा टारगेट है वह 25 परसेंट से कम है, उसको हम बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, अभी नाबार्ड ने हमें 60 करोड़ सैंक्शन किये हैं, तो हम जल्द से जल्द उस बैंक को भी मजबूत करके वहां और कर्मचारी भी उपलब्ध हों, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में विद्युत उत्पादन

8. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक प्लांट में कितना-कितना विद्युत उत्पादन हुआ? उत्पादन में गिरावट को रोकने के संबंध में क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में निगम के घाटे में रहने के मुख्य कारण क्या रहे तथा उसके निस्तारण बाबत निगम द्वारा क्या प्रयास किए?

(3) क्या राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का कार्य उत्पादन के क्षेत्र में संतोषजनक रहा है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उन पर क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सभी विद्युतगृहों में पिछले पांच वर्षों में हुए सकल विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सकल विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1.	2019-20	31387.88
2.	2020-21	28890.99
3.	2021-22	33991.95
4.	2022-23	39612.08
5.	2023-24	43372.10
6.	2024-25	46678.61 (अनुमानित)

विद्युतगृहवार विवरण परिशिष्ट 'अ' उपलब्ध है।

उत्पादन में गिरावट को रोकने के प्रयासः-

1. प्रत्येक विद्युतगृह स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग

2. आवश्यक कलपुर्जों का उचित प्रबन्धन,

3. संचालन संबन्धित खामियों का त्वरित निदान

4. चरणबद्ध तरीके से अपने विद्युतगृहों एवं इकाइयों के उचित रखरखाव एवं तकनीकी खामियों को दूर कर विद्युत उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कोल खपत में भी कमी दर्ज की।

5. सुपर क्रिटिकल इकाइयों का उचित रखरखाव एवं इनकी तकनीकी खामियों को दूर कर इन इकाइयों से आवश्यकतानुसार 250 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया गया है।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(2) उत्पादन निगम के घाटे में रहने के मुख्य कारण

(अ) गत सरकार के निर्णय

1. वर्ष 2020-21 के बाद गत सरकार के निर्णयानुसार निगम को प्राप्त होने वाली अंश पूंजी पर प्रत्याय (ROE) एवं राज्य डिस्कॉम्स को बिजली सप्लाई के पेटे बकाया राशि पर प्राप्त होने वाले Late Payment surcharge (LPS) को समाप्त कर 14968.70 करोड़ रुपए डिस्कॉम्स को वापस करना पड़ा जबकि निगम को बिजली वितरण कम्पनियों से बिजली सप्लाई के पेटे समय पर पूर्ण भुगतान नहीं मिलने के कारण अपने दिन प्रतिदिन के परिचालन खर्चों एवं कोयले के भुगतान हेतु नवीन अल्पकालीन ऋण लेने पड़े जिन पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान भी करना पड़ा।

(ब) परिचालन संबन्धित कठिनाइयाँ

1. गिरल लिग्नाइट प्लान्ट का लम्बे समय से बंद रहना,

2. धौलपुर गैस विद्युतगृह के संचालन हेतु उचित दर की गैस की अनुपलब्धता।

3. रामगढ़ गैस विद्युतगृह के संचालन हेतु पर्याप्त गैस की अनुपलब्धता।

4. सितम्बर, 2021 में छबड़ा 250 मेगावाट इकाई में तकनीकी खराबी के कारण लंबे समय तक बंद रहना।

5. छबड़ा एवं सूरतगढ़ में स्थापित सुपरक्रिटिकल इकाइयों से पूर्ण क्षमता पर विद्युत उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाना।

6. साथ ही गत राज्य सरकार एवं छतीसगढ़ राज्य सरकार में समन्वय में कमी के कारण देशव्यापी कोयला संकट के समय निगम को आवंटित कोयला खदानों से खनन में आई बाधाओं के कारण कोयला आपूर्ति बाधित हुई।

7. कोयला आपूर्ति में कमी के कारण कोल इण्डिया द्वारा ब्रिज लिंकेज के माध्यम से प्राप्त कम गुणवत्ता वाले कोयले को लेना पड़ा जिससे विद्युतगृहों को पूर्ण क्षमता पर संचालन संबन्धित परेशानिया उठानी पड़ी।

(स) घाटे के निस्तारण हेतु प्रयास-

1. कलपुर्जों का उचित प्रबन्धन करते हुए समयबद्ध पूर्व निर्धारित वार्षिक रखरखाव किया जा रहा है।

2. संचालन संबन्धित खामियों का त्वरित निदान किया जाता है।

3. विद्युतगृहों के विभिन्न स्तरो पर प्रभावी निगरानी एवं नियत्रंण हेतु विशेषज्ञों की टीम गठन कर प्रत्येक विद्युतगृह के परिचालन एवं संधारण से संबंधित कार्यों का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है।

4. साथ ही निगम को आवंटित केप्टिव कोल खदानों से सुचारु कोयला आपूर्ति प्रारंभ करवाई गई है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार सितंबर 2024 तक उत्पादन निगम का कुल संकलित घाटा 30812.48 करोड़ रूपये है।

(3) जी हां। उत्पादन निगम के विद्युतगृह प्रतिदिन बिजली उत्पादन एवं दक्षता में सुधार की और अग्रसर है।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर मिल गया है। आपकी इजाजत हो तो मैं पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड, यदि सभी सदस्य अपन यह स्वीकार कर लें कि उत्तर आ गया है तो शायद अधिक प्रश्नों के पूरक प्रश्न भी आ पायेंगे, चर्चा भी हो पायेगी। क्या इसको अपन तय कर सकते हैं? क्या सब चाहते हैं?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

श्री अध्यक्ष: तो प्रश्न का उत्तर पढ़ने का जो समय बचेगा उसमें अधिक प्रश्न आ पायेंगे। आगे से सीधा प्रश्न संख्या बुलाऊंगा, आप खड़े होकर के, उत्तर आ गया है, अगला पूरक प्रश्न

का उत्तर देना शुरू।

श्री रामकेश (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, 3 प्रश्न पूछे थे। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में पिछले 5 सालों में प्रत्येक प्लांट में कितना-कितना उत्पादन हुआ? यह आंकड़े मेरे पास आ गये। दूसरा प्रश्न था, उत्पादन निगम के घाटे में रहने के मुख्य कारण और क्या जो उत्पादन हो रहा है उससे अभी विभाग संतुष्ट है? 3 प्रश्न थे और तीनों का जवाब माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया है। लेकिन बहुत गोलमोल करके दिया है। बहुत घुमा-फिराकर दिया है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि 5 साल के जो आंकड़े दिये उसमें से सारी जो हमारी उत्पादन की इकाइयां हैं, उन उत्पादन इकाइयों की कुल केपेसिटी 75286 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष है और हम ऐवरेज पूरे 5 साल में केवल 35450 मिलियन यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। जो लगभग 50 परसेंट से भी कम क्षमता का उपयोग, हमारे जो प्लांट हैं वह कर रहे हैं। इससे उत्पादन निगम का जो घाटा है वह लगभग 30812 करोड़ को पार कर गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आरएसईबी का विघटन हुआ 2000 में और 5 कंपनियां बनी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करें। प्रश्न पूछें।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है। उत्पादन निगम उसी में से एक कंपनी है। भारत सरकार ने उत्पादन निगम को कोल ब्लॉक्स आवंटित किये। उन कोल ब्लॉक्स को 2007 में +++ की एक कंपनी है, उस +++ की कंपनी को कोल ब्लॉक्स दे दिये।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): उत्पादन निगम ने जोइंट वैंचर करके, उनको कोल सप्लाई का ठेका दिया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछे।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो कोल सप्लाई हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह चर्चा का विषय नहीं है। आप सीधा प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा। वहां से जो कोल सप्लाई हो रहा है, उस कोल सप्लाई, उसकी जीसीबी की कोई जांच नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो क्या चाहते हो। आप ही उत्तर दे रहे हो। आप प्रश्न पर आ जाओ।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं प्रश्न पर आता हूं। मैं यह जानना चाह रहा हूं मंत्री जी से कि 25 मार्च, 2013 से आज दिनांक तक जो +++ की कंपनी पीकेसीएल है, उनके द्वारा आपूर्ति किये गये कोल की औसत जीसीबी क्या रही है? एक प्रश्न। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो जीसीबी की जांच पहले सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद द्वारा की जा रही थी, किन कारणों से उस एजेंसी को बदला? आज की तारीख में जीसीबी की जांच कौन कर

रहा है? जीसीबी किस लेवल की आ रही है और भुगतान किस लेवल का हो रहा है? बहुत बड़ा घोटाला इसके माध्यम से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजो। उत्तर तो आने दो।

श्री रामकेश (गंगापुर): मेरे इन दोनों सवालों के जवाब दिलवा दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कोल प्लांटों में माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि उत्पादन कम क्यो हुआ? उसका मुख्य कारण, जिस कोल ब्लॉक्स की यह बात कर रहे हैं परसा कांता, वह 2013 से वहां पर उत्पादन हो रहा है। लेकिन बीच में कोल की कमी हुई। उस कमी के समय में जो उत्पादन हमारा अतिरिक्त होना चाहिए था, कोल की सप्लाई होनी चाहिए थी, वह कोल की सप्लाई तो हुई नहीं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के समन्वय के अभाव में हमारी व परसा कांता, जो हमारी खुद की माइंस है, कोल ब्लॉक है, उसको बंद करना पडा। क्योंकि वहां से पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाने के कारण वह माइंस बंद रही। जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रयास किया।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जीसीबी का सवाल पूछ रहा हूं। उत्तर दीजिये जीसीबी का।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वह भी बता रहा हूं ना।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये। आपको दूसरी बार पूछने देंगे। उत्तर तो सुनो। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर सुनना पड़ेगा। आपको जो पूछना है वह फिर पूछो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया और उसको चालू कराया।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, जो परसा कोल ब्लॉक के लिए यह माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह 2013 से उत्पादन निरंतर हो रहा था। 2022 में इसकी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 2023-24 में यह खनन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई। इससे 2022-23 में खनन कार्य हेतु 134 हेक्टेयर भूमि में से मात्र 43 हेक्टेयर ही हमें मिली। फिर हमने प्रयास किया और उसके बाद 36 हेक्टेयर और मिली। अभी 108 हेक्टेयर हमें और मिल गई है। जिसके लिए जो अभी आवश्यक स्वीकृतियां थी, उसकी सुनवाई कर ली गई है। उसके बाद हमें पर्यावरण स्वीकृति तथा अन्य स्वीकृतियां मिलने के बाद वह चालू होगी। उससे भी उत्पादन बढ़ेगा।

मैं आपको समझाऊं, घाटे का कारण रहा है, हमारी माइंस बंद हो गई जिससे हमें अतिरिक्त लिंकेज के माध्यम से कोल इंडिया से कोल लेना पडा। वह कोल हमें 40 परसेंट अधिक दामों पर मिलता है। जब हमारी माइंस हम नहीं चला पा रहे हैं तो 40 परसेंट अतिरिक्त दाम हम देकर के जब कोल लेंगे तो घाटा तो होना ही है। जो हमारा कोल ब्लॉक

था, वह छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के समन्वय के अभाव में नहीं चल पाया। जिससे हमें वह घाटा हुआ।

श्री रामकेश (गंगापुर): मंत्री जी, आप यह क्या ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप दूसरा प्रश्न, आपका एक प्रश्न और पूछ लेना।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आप यह जवाब ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं अगला प्रश्न पुकार लूंगा। माननीय सदस्य, आप उत्तर सुन लें। आपको एक अनुमति और दूंगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जीसीबी की 3 स्तरों पर जांच होती है। पहले प्लांट में भी जांच होती है। एक एजेंसी वहां होती है। वह एजेंसी इंडिपेंडेंट होती है। प्लांट में आने के बाद भी होती है। अगर माइंस पर जो जांच हुई है, उसमें और प्लांट में जो जांच हुई है, उसमें फर्क आता है तो हम उसको पेमेंट जो हमारी कम जीसीबी आई है, उसके आधार पर करते हैं, ना कि कंपनी के आधार पर करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता जांच में नहीं है। यह घाटे का कारण तो उस समय जब वह कोल ब्लॉक बंद हुए, आज हमें घाटा नहीं हो रहा है। आप जिस टाइम की बात कर रहे हो ना घाटे की, वह आपकी सरकार के समय की बात है। आज हमें घाटा नहीं हो रहा है।

श्री रामकेश (गंगापुर): आपकी बात ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपको अनुमति दूंगा ना।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): घोटाले इनके समय में हुए हैं। इनके समय में ही जांचों में घोटाले हुए हैं। जिस वजह से घाटा हुआ है।

श्री अध्यक्षः उत्तर तो आने दो।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आपका तो बतायें ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके समय के घोटालों की वजह से हुआ है। आप टाइम दे दो। पहले भी आपने समय मांगा था बिजली पर, एक दिन तय कर देना, पूरा चिट्ठा खोल दूंगा आपका।

श्री अध्यक्षः बिना अनुमति के कोई बोले तो अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कराओ, एक दिन आप चर्चा करा लेना।

श्री अध्यक्षः हो गया आपका?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): पूरा सुना देंगे आपको।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। हां, माननीय सदस्य। जिसका प्रश्न है उसको अनुमति दे दी। बैठिये।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री अध्यक्षः मैंने तीसरे की भी अनुमति दी है।

श्री रामकेश (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि माननीय मंत्री जी कह रहे

हैं, 2007 में तो हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी। उन्होंने जो कोल ब्लॉक दिये वह +++ को दिये।

spp/rtm/03.02.2025/11:40/1**e**

और +++ वहां पर कोल सप्लाई कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः नाम नहीं लें। जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लें।

श्री रामकेश (गंगापुर): और जी.सी.बी... (व्यवधान..) कोल कम्पनी, वह तो रिकार्ड पर है। कोयला आ रहा है 3600 जी सी बी का और भुगतान हो रहा है 4600 जी सी बी का और पूरा का पूरा घोटाला +++ के फेवर में किया जा रहा है। यह +++ की आप कब तक रक्षा करोगे? आप यह रक्षा कब तक करोगे? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो, भाषण नहीं। भाषण के लिये आप अलग से आइये। आप प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): अब तक जी सी बी का जितना भी कोयला आया है, क्या आप मंत्रीजी उसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं? अगर आप जांच कराने के लिये तैयार हैं तो मैं सारे क्वेश्चंस ड्रॉप कर देता हूं।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं यह जी सी बी की जांच निरन्तर हर रेट की होती है और इसमें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वह स्वयं जांच करते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी अलग जांच करती है। हमारे कोल प्लांट में अलग एजेंसी जांच करती है। तीन-तीन जगह जांच करने की प्रक्रिया है और उस जांच में जो भी घटिया मिलती है, कम जांच वाले आधार पर पेमेंट होता है, न कि किसी भी मैनिपुलेशन के आधार पर।

श्री अध्यक्षः बैठिये। अगला प्रश्न। श्री सुरेश गुर्जर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः कह दिया न जांच कराएंगे.

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जांच का आश्वासन नहीं दे रही सरकार। एक मिनट, सरकार सिर्फ जांच करा ले, यही तो हम चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्षः करा रही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं कह रहे। मंत्रीजी आश्वासन दे कि हम जांच कराएंगे।

श्री अध्यक्षः कह दिया जांच कराएंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोयले की क्वालिटी की और भुगतान की जांच कराने के आश्वासन देदें यह।

श्री अध्यक्षः दे दिया। ... (व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं दिया सर।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश गुर्जर। कह दिया न इन्होंने।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, मंत्री को बोलने दो।

श्री अध्यक्षः जांच के लिये कहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप कह रहे हो जांच के लिये। आप कह रहे हो जांच के लिये, सरकार ने कहा है। यह रिकार्ड पर है अध्यक्षजी। यह बाद में .. (व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः माननीय विपक्ष के नेता, इन्होंने कहा है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप जिस जांच की बात कर रहे हैं, वह जांच की कॉपी मंगवाकर सदन के पटल पर रखवा दूंगा। जो जांचें हुई हैं, उन्हें आप चैक कर लेना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो आपसे जांच चाह रहे हैं। पुरानी जांच नहीं चाहिए। सरकार जांच कराना चाहती है कि नहीं उन जांचों की? .. (व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः जांच की कॉपी दे रहे हैं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके टाइम के सब घोटाले सामने आ जायेंगे। .. (व्यवधान)... पूरे का पूरा पर्दा उठा जाएगा। .. (व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जांच कराओ आप।.. (व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सब आ जाएंगे पूरे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप जांच से क्यों डर रहे हो? आप पुरानी जांच दे रहे हो, आप जांच कराओ न।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य, जिस जांच के आधार पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं नेता प्रतिपक्षजी, आपके समय पर पी एल एफ कम था, 55 से 60-65 प्रतिशत तक उत्पादन होता था। आज हमने 19 संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाया है। आज इतिहास का सबसे ज्यादा उत्पादन पिछले आठ दिन में हुआ है। सात हजार के ऊपर हम लेकर गये हैं, जो आपके समय में साढ़े चार हजार तक होता था, पांच हजार होता था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारे समय में हो, इनके समय में हो, जांच कराने में क्या दिक्कत है?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और सुनो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जांच कराने के आदेश कराओ। आपके समय में, हमारे समय में क्या होता है?

श्री अध्यक्षः माननीय उत्तर आ गया न।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमने 2 हजार मेगावाट तक का उत्पादन

कराया है और उसकी लागत भी कम आयी है। अगर घटिया कोयले का.. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। ... (व्यवधान).. श्री सुरेश गुर्जर। माननीय मंत्रीजी, इनका आ गया। जांच की कॉपी दे देंगे। खत्म हुई बात। हो गया जवाब। .. (व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन यह था कि आपने एक व्यवस्था दी, वह हम सबको स्वीकार है। उसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्न आने के बाद प्रश्न और उत्तर हाउस की प्रोपर्टी होती है। हर सदस्य चाहता है कि उसका उत्तर क्या आया। क्योंकि अभी इसमें लोड हो जाये तो हम इसमें पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तक यह

इसमें लोड हुआ नहीं है। जब तक इस सॉफ्टवेयर में लोड नहीं हो जाये तब तक उत्तर पढ़ें ताकि सभी सदस्यों को जानकारी हो सके कि यह उत्तर आया है। .. (व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था को चेंज कर रहे हो। अध्यक्षजी ने व्यवस्था देदी, उसको चैलेंज मत करो। .. (व्यवधान).. आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं माननीय मंत्रीजी ।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी बैठिये। माननीय विपक्ष के नेता बैठिये। .. (व्यवधान)... माननीय मंत्रीजी, आसन पांवों पर है। इनको बिठा दिया। आप बैठिये। अगला प्रश्न पुकार लिया है। मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

खानपुर में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा

9. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2021 से 2024 में प्राकृतिक आपदा से रबी एवं खरीफ की फसल में नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसे वर्ष में कितना-कितना? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में हुए नुकसान की गिरदावरी करवाई गई है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसानों को उक्त वर्षों में हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितने किसानों को तथा कितनों का शेष है ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि भूमिहीन पशुपालकों के पशुओं की आकाशीय बिजली गिरने से हुई मृत्यु पर मुआवजा देय है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने आवेदन निरस्त किये गये ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री ओटाराम देवासी) (1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक की अवधि में प्राकृतिक आपदा से केवल खरीफ फसल (बाढ़) वर्ष 2021 (संवत् 2078) में 7डी खराबा रिपोर्ट अनुसार कुल 81822 हैक्टेयर एवं वर्ष 2022 (संवत् 2079) (बाढ़) में 82673 हैक्टेयर में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का फसल खराबा हुआ, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 (संवत् 2078 से 2080) तक की अवधि में रबी फसल में तथा खरीफ फसल वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 में काश्तकारों की बोई हुई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का फसल खराबा नहीं हुआ है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2021 एवं वर्ष 2024 (बाढ़) में गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर फसल खराबे का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-'अ' के अनुसार है।

(3) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर में खरीफ फसल वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 (बाढ़) में पात्र कुल 139377 (एक लाख उनतालीस हजार तीन सौ सतहत्तर) काश्तकारों को कुल राशि रु. 8208.91 लाख का एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया गया। उक्त वर्णित अवधि का कोई भी काश्तकार कृषि आदान अनुदान

भुगतान से अवशेष नहीं है।

(4) जी हां। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नॉर्म्स दिनांक 10.10.2022 में भूमिहीन पशुपालकों के पशुओं की आकाशीय बिजली गिरने से हुई मृत्यु पर मुआवजा/सहायता देय है।

विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत तीन वर्षों में भूमिहीन पशुपालकों के 02 आवेदन निरस्त किये गये, उक्त दोनों आवेदन दिनांक 10.10.2022 से पूर्व में घटित घटनाएं होने के कारण तात्कालिक नॉर्म्स दिनांक 08.04.2015 के अनुसार भूमिहीन पशुपालकों को पशु मृत्यु होने पर सहायता देय नहीं होने के कारण निरस्त किये गये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब तो सरकार से मिल गया। प्राकृतिक आपदा में किसानों का जो नुकसान हुआ था, वह मुआवजा तो आपने दे दिया है। पर प्राकृतिक आपदा में जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, जो जानवर मरे, उनका मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। क्या सरकार उनको मुआवजा देने का विचार रखती है?

श्री ओटा राम देवासी (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 2021 से 2024 तक प्राकृतिक आपदा व बाढ़ से खरीफ की फसल 7डी खराबे की रिपोर्ट के अनुसार 81 हजार 822 हैक्टेयर में जो नुकसान हुआ था, उसमें से 82 हजार 673 हैक्टेयर में 33 प्रतिशत जो नुकसान हुआ, उसका हमने भुगतान कर दिया है और पंचायतवार परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो मुझे मिल गया।

मेरा मंत्रीजी से प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा में जो बाढ़ आयी। भीमसागर बांध के जो गेट खोले गये थे खानपुर विधान सभा क्षेत्र में, उसमें फसलों के नुकसान के साथ-साथ कई लोगों के मकान और जानवर बह गये थे। उनको सरकार ने अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया?

श्री ओटा राम देवासी (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री): मैं आपसे निवेदन करना

चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आपने प्रश्न में मकानों का नहीं पूछा है।

श्री ओटा राम देवासी (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री): मकानों का इसमें नहीं पूछा।

श्री अध्यक्षः पूछा ही नहीं है इन्होंने।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): मंत्री महोदय, मेरा यह पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न में मकान थोड़े ही आते हैं। इसमें आपने जो प्रश्न किया है, उसी से रिलेटेड पूछो आप।

श्री ओटा राम देवासी (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री):आपने प्रश्न के माध्यम से इसमें मकानों का उल्लेख ही नहीं किया।

श्री अध्यक्षः चलिए, आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या फसल बीमा के प्रावधानों में फसल में आग लगने पर मुआवजा देने का प्रावधान है?

श्री ओटा राम देवासी (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री): मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह SDRF के नॉर्म्स के अनुसार जो भी आगजनी है या बाढ़ से नुकसान है, उसमें जो भी नुकसान होता है, उसका हम SDRF नॉर्म्स के अनुसार भुगतान करते हैं। दूसरा यह निवेदन था कि यह जो मकानों वाला है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रश्न में इस बात का उल्लेख नहीं किया है, परंतु सरकार हमेशा संवेदनशील सरकार है और हमेशा किसानों के लिये, गरीबों के लिये और पीड़ित परिवारों के लिये हमेशा तत्पर रहती है तो मैं कलेक्टर के माध्यम से कहकर तुरन्त मुआवजा दिलाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री सुखवंत सिंह।

रामगढ़ में नवीन खेल मैदान

10. श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में खेल मैदान कहां-कहां हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये खेल मैदान कहां-कहां व कब तक बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले और खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, अलवर में खेल मैदानों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर संलग्न है।

(2) शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ऐसे विद्यालय जिनमें खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें खेल मैदान हेतु भूमि उपलब्ध करवाये जाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन/जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा प्रदेश में स्टेडियम खेल मैदानों के निर्माण हेतु निम्नानुसार योजनाएँ संचालित की जा रही हैः-

(i) प्रदेश में खेलों को बढावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएँ) विकास कार्यक्रम-2015 के मापदंड निर्धारित किये गये हैं।

(ii) "मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना" के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम एवं आधार निर्धारित किये गये हैं।

(iii) ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At least one Outdoor Game का मैदान का निर्माण कार्य स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद के माध्यम से करवाया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक प.40(91) 08.07.2022 नियत है। ग्रावि/नरेगा/कन्वेजेन्स/खेल-विभाग/2015 दिनांक

(iv) बजट भाषण वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 65 (VIII) में ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से Open gyms व खेल मैदान बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में, 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ये सुविधायें विकसित की जायेंगी।

उपरोक्त के संबंध में उचित माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर नये खेल मैदान बनाने पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न श्री सुखवंत सिंह।

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदानों के बारे में सवाल था। मुझे लिखित में जवाब मिल गया है। उसमें मैंने डवलपमेंट के बारे में पूछा था कि खेल मैदानों में क्या डवलपमेंट हुआ या कहीं नये खेल मैदान बने हैं क्या? इस उत्तर में मुझे एक सूची उपलब्ध करायी गयी है और वह खाली स्कूलों में और कॉलेजों में खाली जमीन पड़ी हुई है उसमें कोई भी डवलपमेंट नहीं हुआ है। मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि उनको विकास के लिये आउटडोर गेम्स क्या थे, वह अभी तक नहीं बन पाये। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले बजट में हमने 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों का डवलपमेंट करने के लिये खेल मैदान बनाने को कहा था, लेकिन वह सारी नगरपालिकाएं बन गयीं। अब उसमें कुछ शिथिलता मिल सकती है क्या जो छोटी पंचायतें हैं, उनमें भी डवलपमेंट हों।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। आपका प्रश्न हो गया। माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। आप बिराजो तो उत्तर आये। आप बिराजो तो सही।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (युवा मामले और खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे नव-निर्वाचित सदस्य सुखवंत सिंहजी को भी और सदन को भी यह बताना चाहता हूं कि खेल की तैयारी के लिये केवल एक विभाग नहीं, बल्कि अनेक विभाग

जुड़ते हैं जिसके अन्दर शिक्षा विभाग है, पंचायती राज विभाग है, अनुसूचित जनजाति डवलपमेंट विभाग है, यह सब उसके अन्दर जुड़ते हैं। जो लिस्ट माननीय सदस्य को दी गयी है, वह शिक्षा विभाग ने 32 खेल मैदान वहां पर तैयार किये हुए हैं। जो बाकी बचे हुए स्कूल हैं जहां पर अभी भी ग्राउंड डवलप नहीं है। शिक्षा विभाग ने उसके लिये भूमि आवंटन करने के लिये निर्देश दे दिये हैं। इसी के साथ-साथ पंचायती राज विभाग ने माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 16 ग्राउंड तैयार करवा दिये हैं। अब मेरा आग्रह यह है, इन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यह है।

jyg/rtm/03.02.25/11.50/1f

2024-25 के बजट के अन्दर हमने घोषणा की थी कि हर ग्राम पंचायत के अन्दर हम ओपन जिम की सुविधा डवलप करेंगे। हम शुरूआती फेज के अन्दर 10 हजार से ज्यादा आबादी के जो क्षेत्र हैं वहां पर हम कर रहे हैं। माननीय सदस्य का जो विधान सभा क्षेत्र है उसके अन्दर तीन ग्राम पंचायत है जिनके अन्दर हम यह कार्यवाही कर रहे हैं। अब यह ग्राउण्ड का डवलपमेंट केवल इस टेबल से क्यों हो? यहां पर तीन मंत्री बैठे हुए हैं, आपकी टेबल से होना चाहिए, हर टेबल से होना चाहिए। हमारी मेजर ध्यानचन्द योजना है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उसका फायदा उठाये जिसके अन्दर सरकार मैचिंग ग्रांट देती है। आप युवाओं के लिए अपने पांच साल के बजट में से चार प्रतिशत तो कम से कम लगाइये। आप उसमें लगायेंगे तो मेजर ध्यानचन्द योजना के माध्यम से एक शानदार स्टेडियम तैयार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया माननीय सदस्य।

श्री रामनिवास गावड़िया।

परबतसर पंचायत समिति को बजट का आवंटन

11. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पंचायत समिति परबतसर को 1 जनवरी, 2024 से 1 जनवरी, 2025 तक कितना बजट आवंटन किया गया तथा उक्त बजट में से कितना बजट व्यय किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों द्वारा निविदाएं जारी की गई हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत द्वारा, किस प्रक्रिया के अंतर्गत, कौनसी फर्मों को, कितने बजट की निविदा जारी की गई? नाम सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी का एक विकास बार स्थानान्तरण करने के उपरांत उसी स्थान पर कितने समय पश्चात् स्थानान्तरण किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पंचायत समिति परबतसर को 1 जनवरी, 2024 से 1 जनवरी, 2025 तक आवंटित राशि व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

राशि रुपये लाखों में

1.	पन्द्रहवां वित्त आयोग	286.26	43.32
2.	राज्य वित्त आयोग षष्ठम	247.09	49.52

(2) जी हां। पंचायत समिति परबतसर के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में टेण्डर हुए है। टेण्डर हेतु समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन, SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN एवं E-PROC.RAJASTHAN.GOV.IN पोर्टल पर प्रकाशन एवं ई-निविदा की गई तथा संबंधित निविदा समितियों द्वारा प्राप्त निविदाओं को नियमानुसार (राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के तहत) खोलकर पंचायत समिति स्तर से अनुमोदित करने की प्रक्रिया अपनाई गई। स्वीकृत निविदा से संबंधित फर्मों का नाम व अनुमानित निविदा राशि की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(3) प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाने के उपरांत विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। विकास अधिकारी का एक बार स्थानान्तरण करने के उपरांत उसी स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई नियम/आदेश निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने जो आंकड़े मुझे दिये हैं उसके उपरांत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार को बने हुए 14 महीने हो गये हैं, इस दौरान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रेशराइज करके गांवों से बसें भरवाकर आप लोगों ने माननीय प्रधान मंत्रीजी का स्वागत भी कर दिया, एक साल का आपने जश्न भी मना लिया। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर आप लोगों ने वाहवाही लूटने का काम भी कर लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति परबतसर में माननीय मंत्रीजी ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें वर्तमान में लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि बजट आवंटित है और पिछले सवा साल से वहां एक रुपये के भी नये कार्यों की स्वीकृति नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इसकी जांच करवाकर इसमें जो भी दोषी हैं उस पर कोई कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही करेंगे तो कब तक करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है कि विकास अधिकारी के बारे में मैंने आपसे पूछा यह विकास अधिकारी जो पंचायत समिति परबतसर में वर्तमान है, अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक पांच बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक सरकार द्वारा पांच बार इसका स्थानांतरण किया गया। दो बार

इसको यहां से एपीओ, मुख्यालय जयपुर किया गया, पांचों बार इसने, जहां भी इसको एपीओ किया गया या इसका स्थानांतरण किया गया..।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछें।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): वहां पर इसने पदभार ग्रहण नहीं किया, बावजूद इसके 28.10.2024 को इसको पाटन नीमकाथाना से पंचायत समिति परबतसर लगा दिया गया जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का सर्कूलर जारी है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): जो भी कर्मचारी-अधिकारी, जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेज या डिपार्टमेंटल जांच लंबित है या जांच में दोषी पाया गया है तो उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जायेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह प्रश्न है कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गयी कि पांच बार आपके आदेश की अवहेलना करते हुए आज पंचायत समिति परबतसर में वो विकास अधिकारी पिछले सवा साल से नये कार्यों को स्वीकृत नहीं कर रही है, माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः मैं उत्तर दिला रहा हूं।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): आज अगर विधायिका इतनी कमजोर हो गयी, कार्यपालिका हम सब लोगों पर हावी हो रही है।

श्री अध्यक्षः उत्तर तो लो इसका। पूछ लिये, आपने दो प्रश्न पूछ लिये।

माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): मैं प्रश्न पूछता हूं कि आप इस पर कार्यवाही करके इसको एपीओ या सस्पेंड करने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्षः बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कौन अधिकारी दोषी है और कौन कर्मचारी दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 2024 के बाद से मांगा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कार्य प्रगति पर है, समायोजन नहीं हुआ है और इसमें से 15वें वित्त आयोग का 43 लाख 32 हजार रुपये खर्च हो गया है। राज्य वित्त आयोग षष्ठ का 39 लाख 52 हजार रुपये खर्च हो गया है और अभी कार्य प्रगति पर है इसलिये अभी कोई दोषी नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बीडीओ कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है तो इन्हीं के बारे में बता देता हूं पुराने कि कितनी जल्दी-जल्दी ट्रांसफर करके क्या करते थे, पता नहीं बार-बार ट्रांसफर करके लेनदेन करते थे क्या नहीं करते थे, ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एपीओ कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः उत्तर में व्यवधान नहीं। ...(व्यवधान)... उत्तर में व्यवधान नहीं। आपको अनुमति नहीं है। इनका अंकित नहीं हो। ...(व्यवधान)... इनका भी अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं। बिना अनुमति के कोई बोलेगा, अंकित नहीं। बैठिये, कोई अंकित नहीं है। बैठिये। आप अपना उत्तर दीजिये। जवाब देते रहिये। ...(व्यवधान)... बिना अनुमति के अंकित किसी का भी नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 000

श्री अध्यक्षः आपको क्या हो गया? माननीय सदस्य, क्या हो गया आपको? इट इज माई ड्यूटी। किसको बैठाना है, किसको अनुमति देना है, ...(व्यवधान)... आप बैठिये। नो। क्वेश्चन ऑवर में नो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तीन साल में नौ बार विकास अधिकारी को बदला था, आखिर में ऐसी क्या बात हुई थी?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 000

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): नौ बार।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, उनका उत्तर आने दो। ...(व्यवधान)... उनको भी कह रहा हूं। यह काम मेरा है, आपका नहीं है। ...(व्यवधान)... एक-एक करके खड़े हो गये, यह क्या है? पहले ही दिन सबको खड़े होने की, ...(व्यवधान)...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां पर कोई भी माननीय सदस्य कोई सवाल लगता है तो यह उम्मीद करता है कि उसका निस्तारण हो, यहां पर माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि पिछले सालों में यह हुआ, वो हुआ तो आप अपना बता दीजिये, एक साल में पांच बार बीडीओ को एपीओ किया है, 16 सीसीए की चार्जशीट में उसको दोषी माना गया है, तो फिर उसको क्यों लगाना चाहते हैं, अगर ये लेनदेन की बात कर रहे हैं तो मेरा भी आरोप है कि ये क्या लेनदेन करके करके वापस लगा रहे हैं? और ये बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने 43 लाख 32 हजार के काम कर दिये, 49 लाख 52 हजार के काम कर दिये, कितने में से काम कर दिये? आपने 286.26 लाख में से किया है 43 लाख, आपने 247 लाख में से किया है 49 लाख, 15 परसेंट काम किये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः उत्तर दिलवा रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसको जवाब दीजिये, इसका जवाब दो, और यह बताइये कि आप उस विकास अधिकारी पर कार्यवाही करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हो? आप कह रहे हो कि यह सरकार नियमों से चलेगी तो क्या यह नियम है कि 16 सीसीए की चार्जशीट और उसमें दोषी पाये जाने के बाद में विकास अधिकारी को हटाया गया है तो वापस क्यों लगाया गया उसको? इसका जवाब दीजिये।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मंत्रीजी का उत्तर आने दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये पांचों बार आदेश आपकी सरकार ने किये हैं, हमने नहीं किये हैं, आपकी सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है, आपकी सरकार के आदेश है जिनको विकास अधिकारी नहीं मान रहा है। आप उसको बचाने की बात कर रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 000 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी खड़े हैं। आप सुनिये। अगला एक प्रश्न और आने दो। हरिमोहनजी इंतजार कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जानकर भी अनजाने हो रहे हैं कि पिछला बजट जो पेश हुआ था, वो जुलाई में पेश हुआ था और जुलाई में पेश होने के बाद जब बजट पास हुआ और पास होने के बाद जब प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकलती है तो उसके बाद वर्क ऑर्डर मिलता है, ये सब जानते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी कार्य प्रगति पर है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर तो सुन लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नया बजट पास करने के लिए हम बैठे हैं, पुराना बजट तो पूरा कीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुन लो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट स्टे के कारण कार्यरत रही हैं वो, कोर्ट स्टे था। कोर्ट स्टे के कारण बीडीओ वहां कार्यरत रहे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सदन है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोर्ट स्टे नहीं मिला। सरकार ने क्या प्रयास किये? आप बताइये, आप यहां पर मिथ्या तथ्य पेश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कोर्ट स्टे का आप कुछ नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: बिना अनुमति के कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाओ। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी से जवाब तो दिलवाइये। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब दिलवाइये। ...(व्यवधान)... मंत्री जवाब तो दे। मंत्री से जवाब दिलवाओ। ...(व्यवधान)... ।

MLS/RTM/03.02.2025/12:00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

अनुपस्थिति अनुमति

किरोड़ी लाल, श्री, मंत्री को सत्रान्त तक

अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है, श्री किरोड़ी लाल, सदस्य विधान सभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र में सत्रान्त तक अस्वस्थता के कारण सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही गयी है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बीमार नहीं, किरोड़ी जी मजबूर हैं। ...(व्यवधान)...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संदिग्ध मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत कटौती से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सिद्धमुख में रेलवे अंडर ब्रिज का कार्य प्रारम्भ करने हेतु किसानों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर फीडर, अमर सिंह ब्रांच एवं सिद्धमुख नहर में पानी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफली फसल खरीद में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), श्री अमित चाचाण एवं श्री पूसाराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत

खानपुर को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से बारां जिले में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की नगर पालिका डेगाना के प्रस्तावित मास्टर प्लान पर पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

4. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में जल जीवन मिशन योजना के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने एवं उक्त योजनान्तर्गत डाली गयी पाइप लाइन से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री बालमुकुन्दाचार्य, सदस्य की ओर से जयपुर शहर सहित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी एवं रोहिंग्याओं को वापस भेजे जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से पाली एवं ब्यावर डिपो द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के रोडवेज बसों का आवागमन बन्द किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

8. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में वीर बाला काली बाई भील स्कूटी योजना वर्ष 2022-23 की वंचित छात्राओं को स्कूटी वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम सिन्ती, पंचायत उलेड़ा निवासी अध्यापक श्री मनीष मीणा के परिजनों को आर्थिक सहायता एवं अन्य परिलाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नौनेरा बैराज हेतु ग्राम ऐबरा की भूमि का अधिग्रहण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर स्थित श्री मथुराधीश मन्दिर कॉरिडोर एवं परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री रामबिलास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लालसोट के डिडवाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

14. श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर विकास प्राधिकरण के पैराफेरी क्षेत्र में पट्टों से वंचित राजस्व ग्रामों में कैम्प लगाकर पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में।

15. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की ग्राम पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र की तर्ज पर पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 03.02.2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं	पर्ची सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	8	श्री भागचन्द टांकड़ा	बांदीकुई को जिले का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
2.	16	श्री कालीचरण सराफ	जयपुर शहर स्थित राजकीय जयपुरिया अस्पताल में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	15	श्री ललित मीना	किशनगंज-शाहबाद विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों को पेयजल एवं सिंचाई हेतु ईआरसीपी योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।
4.	4	श्री रविन्द्र सिंह भाटी	पश्चिमी राजस्थान में निजी कम्पनियों के द्वारा किसानों की जमीन डीएलसी से कम रेट में खरीद-फरोख्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सादुलपुर के सिद्धमुख में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिद्धमुख तहसील के पूर्वी दक्षिण की तरफ सादुलपुर से हनुमानगढ़ जाने वाली ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनने के बाद लगभग 300 किसानों की 4 हजार बीघा जमीन पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो माह से किसान अपनी इस बात को लेकर रेलवे कतोनी रास्ते सिद्धमुख से चुबगयागढ़ के रास्ते पर आन्दोलनरत हैं।

सरकार ने रेलवे अंडरपास पोल नं. 145/01 पीडब्ल्यूडी के द्वारा 2023-24 में इसकी निविदा जारी कर दी थी। उसके बाद एक वर्ष का समय हो गया। इस सरकार ने अपने आने के बाद उस निविदा को रोक दिया और इससे किसानों के आवागमन में भारी बाधा पैदा हो गयी। किसानों के लिए खेतों में सिंचाई करने के लिए, अपनी बुवाई करने के लिए आवागमन पूर्ण रूप से बन्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से गौर करे। पिछली सरकार ने 2023-24 के बजट में उस अंडर ब्रिज को स्वीकृत कर दिया था, उसकी निविदा हो गयी थी।

उसके उपरान्त आपकी सरकार ने इस निविदा को परिपत्र 3 और 2 के नाम से रोक दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों की इस गम्भीर समस्या को मद्देनजर रखते हुए कहना चाहता हूं कि 4 हजार बीघा के किसान बिना रास्ते अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो निविदा पीडब्ल्यूडी राजगढ़ द्वारा की गयी है, उसे तुरन्त प्रभाव से खोला जाये और अंडर ब्रिज का निर्माण कर किसानों को लाभ दिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय एक भी सीनियर अधिकारी यहां मौजूद नहीं है। संसदीय मंत्री जी को आप निर्देश दीजिये कि ये आगे से इस चीज का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय मंत्री जी, परसों बात हुई थी कि यहां पर ध्यानाकर्षण से लेकर स्थगन प्रस्ताव, 295 से जुड़े हुए सारे अधिकारी सदन में बैठें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी चिन्ता सही है। हमें प्रश्न काल तक का ध्यान था, लेकिन इसे बढ़ा देंगे। आगे से कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: कह दिया इन्होंने कि कर देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सदन की अगली बैठक से यह व्यवस्था हो जायेगी। अधिकारी तब तक रुकेंगे, जब तक जीरो आवर की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रिंसिपल सैक्रेटरी के देखने की चीज है कि अधिकारी क्यों गायब हैं, यह प्रिंसिपल सैक्रेटरी देखे।

mkd/rtm/03.02.2025/12:10/1h

व्यवस्था

प्रश्नकाल व शून्यकाल में सम्बन्धित विषयों के अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था दे रहा हूं ना। आप बीच में क्यों खड़े होते हों? माननीय ससंदीय कार्य मंत्री जी आपने वैसे तो हां भर दी है। मेरा सदन को निर्देश है कि जब तक प्रश्न काल हो, तब तक प्रश्नों से सम्बन्धित सारे अधिकारी रहें, लेकिन जब जीरो ऑवर हो, तो जीरो ऑवर में जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं, उनसे सम्बन्धित अधिकारी भी अपने यहां बैठें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सर, हम इसकी पालना करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय अमित चाचाण, अमित चाचाण।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो-चार चपरासियों को लाकर बैठवा लो, कौन मना कर रहा है।

श्री अध्यक्षः अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। अधिकारियों को उनके साथ कम्प्येर मत करो। विराजो, विराजो। अमित चाचाण, नहीं हैं। (अनुपस्थित)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, चाचाण साहब की ट्रेन लेट हो गई है।

श्री अध्यक्षः श्री पूसाराम गोदारा। माननीय सदस्य, अपनी-अपनी सीट पर बैठें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में अनियमितताएं

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एमएसपी योजना के अन्तर्गत चूरू और बीकानेर पूरे राजस्थान में किसानों की मूंगफली प्रति आधार कार्ड 40 क्विंटल खरीद की जाती है, किसान 10-10 दिन तक कृषि मंडी के सामने लाइनें लगाये रहते हैं और 10 दिन बाद उनका नम्बर आता है और फिर इतना भ्रष्टाचार होता है, ठेकेदार इतने बलशाली हैं कि दस और बीस हजार रुपये प्रति किसान से पैसे लेकर उनकी तुलाई की जाती है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है।

किसानों को मदद करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एमएसपी में खरीद की जाती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस लूट खसोट को बन्द किया जाये और इसके साथ-साथ किसान की जो चालीस क्विंटल मूंगफली खरीदी जाती है, उसे अस्सी क्विंटल किया जाये, ताकि उसकी फसल का उसको वाजिब दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में 5 हजार रुपये क्विंटल है और जबकि यहां पर पौने 8 हजार रुपये क्विंटल ली जाती है, लेकिन दलाल और बिचौलियों, ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, जिसमें सारे सहकारिता विभाग के लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ अब तक कई बार शिकायतें हुई हैं। बीकानेर और चुरू में बहुत बारे किसानों ने प्रदर्शन किये हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है।

मेरा यह निवेदन है कि तमाम खरीद केन्द्रों पर जांच कराई जाये और राज्य स्तर पर विशेष कमेटी का गठन कर उसकी जांच करवाकर आम किसान को राहत प्रदान की जाये, यह मेरा आपसे निवेदन है और समय पर भुगतान हो, कम से कम दो-दो, तीन-तीन महीने तक उन किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है, भुगतान सुनिश्चित किया जाये और उसके साथ-साथ वहां पानी और छाया की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ाई हुई खरीद का भी वही पैसा उनको मिलना चाहिए और इन बिचौलियों और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार को बन्द किया जाये और किसानों की लूट को बन्द किया जाये। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्षः 295 के अन्तर्गत सूचनाएं। श्री सुरेश गुर्जर। आपने कह दिया, धन्यवाद दे दिया। श्री सुरेश गुर्जर, आप पढ़ना शुरू कीजिये। अगली कार्यवाही शुरू हो गई है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 30 परसेंट मंत्री नहीं हैं।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव

खानपुर ग्राम पंचायत का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 पर मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र खानपुर की जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र खानपुर में ग्राम पंचायत खानपुर एक बड़ा क़स्बा है और पूरी विधानसभा में एक भी नगर पालिका नहीं है, खानपुर की आबादी लगभग 30 हज़ार है। यदि ग्राम पंचायत खानपुर की परिधि में आने वाली चार ग्राम पंचायतों बैसार, गाडरवाडा इंडी, कॅवलदा और गोल्याखेडी को सम्मिलित कर लिया जाये तो इनकी 25 हज़ार आबादी और जुड़ने से खानपुर नगर पालिका की आबादी 55 हज़ार हो जाती है।

खानपुर एक बड़ा कृषि आधारित व्यावसायिक ग्राम है, जहां पर व्यापार एवं नगरीय विकास की अपार संभावनाएं हैं, साथ ही यहां विख्यात जैन तीर्थ स्थल श्री चॉदखेड़ी में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं, जिसके चलते यहां तीर्थ पर्यटन की विपुल सम्भावनाएं हैं। खानपुर के कई राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठन पिछले कई सालों से धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत खानपुर को नगर पालिका बनाये जाने की मांग कर रहे हैं, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ग्राम पंचायत खानपुर को अविलम्ब नगर पालिका बनाया जावे, धन्यवाद, जय हिन्द, राम-राम साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

बारां में अवैध खनन पर रोक

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि बारां जिले में अवैध खनन की बढ़ती गतिविधियों ने स्थानीय पर्यावरण और जन जीवन को गंभीर खतरे में डाल दिया है। तहसील अन्ता के ग्राम देवपुरा बंजारा, बावडीखेड़ा, मऊ, चहेडिया, रामपुरया, खान की झोपड़िया, पलायथा, पाटोन्दा, बालदड़ा व तहसील मांगरोल के ग्राम कनाड़ा, छत्रपुरा, सीसवाली, मूण्डिया, बलून्दा, सूरथाक व बारां के ग्राम जालेडा, सम्बलपुर तथा तहसील किशनगंज के ग्राम कागला बमोरी, महताबपुरा, बिसलाई, माधोपुर, अर्जुनपुरा, केलपुरीजी, महरावता, किशनगंज तथा तहसील अटरू के ग्राम मोट्रका, कुन्जेड, मायथा, रिछंदा, किरपुरिया एवं तहसील शाहबाद के ग्राम देलवाड़ा, दांता, समरानिया, शाहबाद इत्यादि स्थानों पर अवैध खनन की गतिविधियां चल रही हैं। इस अवैध खनन के कारण न केवल प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों, वन्यजीवों और कृषि योग्य भूमि को भी बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है। बारां जिले में अवैध खनन के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट, भूमि का कटाव, और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ ही स्थानीय जनता के लिए यह खनन कार्य सुरक्षा

और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नुकसानदायक है। अवैध खनन के कारण कई माफिया और संगठित गिरोह सक्रिय हो रहे हैं, जो समाज में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना अवैध खनन नहीं हो सकता। यह एक गंभीर मामला है। इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाए जाने हेतु सरकार को कोई प्रभावी योजना बनानी चाहिए।

आपसे निवेदन है कि बारां जिले में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

नगरपालिका डेगाना के मास्टर प्लान पर पुनर्विचार

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, नगरपालिका डेगाना में प्रस्तावित मास्टर प्लान दिनांक 27 नवम्बर 2024 को आपत्तियां प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 तक आपत्तियों प्राप्त कीं मास्टर प्लान पर आमजन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त व एकल 299 आपत्तियां प्राप्त हुईं. इतनी आपत्तियां प्राप्त होने का अर्थ है कि मास्टर प्लान गलत सर्वे व बिना खसरा एम्पोज मैप के बिना आनन-फानन में जारी किया गया। मास्टर प्लान में कई किसानों की पैतृक व कब्जाशुदा कृषि भूमि को PSPU दायरे में लिया गया है। डेगाना कस्बे के चारों ओर कटानी मार्ग रिंग रोड होते हुए भी किसानों के खेतों से रिंग रोड निकाली गई। गौरेडी करणा में 13 वर्षों से निजी सम्पति पर बने विद्यालय को PSPU दायरे में राजनैतिक द्वैषतावश लिया गया, भामाशाहों द्वारा भूदान की गई भूमि एवं पानी की टंकी, मंदिर को आवासीय दायरे में लिया गया। नगरपालिका सीमा क्षेत्र में किसानों की भूमि हाई-वे विकास नियंत्रण व ग्रीन बैल्ट में ली गई, जो आबादी क्षेत्र में आवश्यक नहीं है। मास्टर प्लान में नगरपालिका क्षेत्र एवं पैराफेरी क्षेत्र के राजस्व गांवों को मास्टर प्लान में शामिल नहीं किया गया है। भविष्य में इन गांवों में विकास का कोई आधार निर्धारण नहीं होगा।

अतः माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गलत सर्वे व बिना खसरा/एम्पोज मैप के जारी किये मास्टर प्लान को लागू नहीं किया जाए तथा अब पुनः नये सर्वे व खसरा/एम्पोज मैप के साथ आपतियों का निस्तारण मास्टर प्लान राजस्व व नगरपालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों व पूर्व एवं वर्तमान पार्षदों की संयुक्त टीम से तैयार करवाकर लागू करवाने की कार्यवाही करवाकर नगरपालिका क्षेत्र डेगाना के आमजन को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

Bhs/Rtm/03.02.25/12.20/1j

श्री अध्यक्ष: डा. ऋतु बनावत।

बयाना के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र

बयाना (076) में क्षतिग्रस्त, नवीन सड़कों का निर्माण कराए जाने की घोषणा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ।

विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश इलाका दूर-दराज तक फैला हुआ ग्रामीण इलाका है। काँग्रेस शासन में क्षेत्र की सड़कों को नजरअदांज किये जाने के कारण अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में आवागमन को सुलभ बनाने हेतु सड़कों का निर्माण कराया जाना जरूरी है। 100 से भी अधिक सड़कों का निर्माण किया जाना है समय के अभाव में सभी का नाम लिया जाना संभव नहीं इसलिए प्रमुख सड़कों का नाम इस प्रकार है।

1. रूपवास जटमासी रोड़ 5.50 मीटर चौड़ाई
2. घाटौली से मैरथा-मिल्सवा यू०पी० बार्डर तक
3. बयाना से बारैठा वाया महमदपुरा
4. स्टेट हाईवे सामरी मोड़ से सिंघनियाँ तक
5. मुख्य सड़क मार्ग धुररी से मुआवली

(1) ग्रामीण सड़क - 1. सम्पर्क सड़क सिरौद, 2. सम्पर्क सड़क जौतरौली, 3. सम्पर्क सड़क सज्जनवास, 4. रूपवास से सिंघावली, 5. जटमासी सड़क से राजपुरा, 6. जटमासी सड़क से रानपुर, 7. बयाना रूदावल सड़क से ककलपुरा, 8. खेड़ली से सज्जनवास, 9. रूपवास जटमासी सड़क से बिनऊआ, 10. नयागांव सड़क से जसवन्त नगर, 11. मोरोली डांग से सिरोद खुर्द, 12. बयाना रुदावल सड़क से खटका, 13. सीदपुर से नगला अन्डुआ, 14. रूपवास से खेरिया लोधा, 15. रूपवास से जगनेर सड़क वाया चकसामरी, 16. सम्पर्क सड़क परूआ, 17. सम्पर्क सड़क लखनपुर, 18. सम्पर्क सड़क समाहद, 19. सम्पर्क सड़क धाना खेड़ली, 20. सम्पर्क सड़क नगला खटका, 21. थानाडांग से खेरीडांग, 22. लिंक सड़क से नगला समाहद, 23. पाण्ड्री से यू.पी. बोर्डर सड़क, 24. पुरामालौनी सड़क से टौटपुरा सड़क, 25. चैकौरा सड़क जसवन्त नगर, 26. मौराली डहर से यू.पी. बोर्डर।

श्री अध्यक्षः इसमें जो लिखा है वह ही पढ़ना है।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रमुख ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य करवाना जरूरी है।

श्री अध्यक्षः श्री बहादुर सिंह।

वैर में जल-जीवन मिशन योजना के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने एवं पाइप लाइन से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना एक ऐसी योजना है जो राज्य के प्रत्येक गांव और कस्बे में शुद्ध जल की आपूर्ति करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति हेतु पानी की टंकी लगवाएगी जिससे जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में पानी की समस्या से लोगों को छुटकारा मिले किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई समितियों द्वारा प्रभावी रूप से संचालन न किये जाने के कारण ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेजेएम के तहत डाली जाने वाली पेयजल लाइनों हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है जिससे आये दिन हादसे होते रहते है तथा आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस योजना के तहत बनाई गई अधिकांश टंकियों का निर्माण

कार्य भी अभी तक पूरा नहीं होने के कारण आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो लाइनें डाली गईं हैं वे निर्धारित मापदण्ड भी पूरा नहीं करती है और उनकी गुणवत्ता की जांच भी नहीं की गई है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस योजना से वंचित लोगों को लाभ दिलाने हेतु अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा करवाकर इस योजना का संचालन समितियों के स्थान पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिया जाये, जिससे कि विभाग में कार्यरत अनुभवी अभियंताओं का लाभ मिल सके तथा पेयजल लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की अविलम्ब मरम्मत करवाई जाये। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्षः श्री बालमुकुन्दाचार्य।

जयपुर शहर सहित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी एवं रोहिंग्याओं की वापसी

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव जयपुर शहर तथा प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशी/रोहिंग्याओं को वापस भेजने के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर तथा सम्पूर्ण प्रदेश में बांग्लादेशी/रोहिंग्या घुसपैठिये अवैध रूप से जमे हुए हैं और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

उक्त रोहिंग्या/बांग्लादेशियों के यहां पर दलाल सक्रिय हैं जो इनको वहां से लाकर यहां बसाते हैं तथा इनके वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब बनवाते हैं। सारे प्रमाण पत्र बनवाने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ इनके द्वारा लिया जा रहा है जिससे जो देशवासी पात्र हैं उनका हक मारा जा रहा है। इन रोहिंग्याओं/बांग्लादेशियों ने सरकारी आवास योजनाओं और जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवास तक आवंटित करवा लिये हैं। प्रदेश के समुदाय विशेष की आबादी में अवैध फर्जी ई-मित्र संचालित हैं जिनके माध्यम से ये आधार कार्ड/राशन कार्ड आदि बना लेते हैं और उन दलालों के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पंजीयन करा लेते हैं। विगत सरकार के समय सरकारी कार्मिकों एवं इन दलालों की मिलीभगत से अवैध कारोबार बढ़ा है। इसके अतिरिक्त उक्त अवैध घुसपैठियों द्वारा चोरी/नकबजनी/हत्या/लूटपाट के अपराध किये जा रहे हैं। शहर की कॉलोनियों में कुछ लोगों द्वारा प्लाटों में छोटे-छोटे कोठरीनुमा कमरे बनाकर किराये पर इनको दिया जा रहा है जिससे कॉलोनियों की सुरक्षा खतरे में है तथा इनके द्वारा गन्दगी तक फैलाई जा रही है। जनता द्वारा लगातार मांग की जाती रही है कि इन अवैध घुसपैठियों को यहां से वापस भेजा जाए।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयपुर शहर तथा प्रदेश से इन बांग्लादेशियों/रोहिंग्या घुसपैठियों को खदेड़ा जाए तथा इनके दलालों/फर्जी ई-मित्र सेंटरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि हमारा प्रदेश सुरक्षित रह सके। आदर सहित।

श्री अध्यक्षः इसमें जो लिखा है वह ही पढ़ना है इसके अलावा एक अक्षर भी नहीं। श्री

रामस्वरूप लाम्बा।

पाली एवं ब्यावर डिपो द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के रोडवेज बसों का आवागमन बंद किये जाने से आमजन को ही रही परेशानी

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली एवं ब्यावर डिपो द्वारा बिना किसी सूचना के मनमर्जी से पाली से पीसांगन एवं ब्यावर से नसीराबाद बस सेवा को आये दिन बन्द कर देने से उत्पन्न ग्रामीणों के आकोश के संबंध में राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 1986 के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन में लगातार कमी की जा रही है। पंचायत समिति एवं उपखंड मुख्यालय पीसांगन हेतु पाली डिपों से पाली-रास-ब्यावर-पीसांगन बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। उक्त बस सेवा का संचालन पाली डिपो द्वारा जब चाहे तब बन्द कर दिया जाता है, जिससे पीसांगन के आस-पास के ग्रामीण छात्र-छात्रा जो ब्यावर कालेज में अध्ययन हेतु प्रतिदिन आवागमन करते है उन्हें समस्याओं का सामना करना पडता है। रास ब्यावर स्थित सीमेन्ट प्लान्ट में सैकड़ों की संख्या में रोजाना मजदूरी करने जाने वाले मजदूरों का आवागमन पीसांगन एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से होता है। इस बस सेवा के बंद होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में निवेदन है कि ब्यावर से नसीराबाद मार्ग पर संचालित होने वाली रोडवेज बस सेवा का संचालन भी ब्यावर डिपो द्वारा मनमर्जी से किया जा रहा है। अजमेर-रामसर-गोठियाना मार्ग वाली बस पर यात्रीभार अत्यधिक हो गया है एवं बस यात्रियों में आपस में लड़ाई तक हो जाती है। श्रीनगर के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार हेतु रोजाना अजमेर से आवागमन करते हैं। इन बसों का संचालन नहीं होने से लोगो को आवागमन में परेशानी होती है। मेरे द्वारा बार-बार रोडवेज प्रशासन द्वारा फोन पर वार्ता करने के उपरांत भी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

मेरा सरकार से व्यक्तिगत आग्रह है कि इस मानवीय समस्या का शीघ्र समाधान कर पाली से पीसांगन, पीसांगन से अजमेर, ब्यावर से नसीराबाद एवं अजमेर श्रीनगर रामसर बोराडा मार्ग पर बसों का संचालन सुचारु रूप से शुरू कराया जावे जिससे बड़ी आबादी, महिलाओं एवं स्कूल कॉलेज छात्र छात्राओं एवं मजदूरों को सुविधा मिल सके एवं जनता के आक्रोश को शांत किया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोगरा।

डूंगरपुर में वीर बाला काली बाई भील स्कूटी योजना वर्ष 2022-23 की वंचित छात्राओं को स्कूटी वितरण

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में वीर बाला काली बाई भील स्कूटी वितरण योजना में वर्ष 2022-23 में वंचित छात्राओं को उक्त योजना के अन्तर्गत स्कूटी का वितरण नहीं किया गया। महोदय, उक्त क्षेत्र आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहां गरीबी व पिछड़ापन आम बात है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में डूंगरपुर जिले की 1168 छात्राएं उक्त योजना के अन्तर्गत स्कूटी वितरण किये जाने हेतु चयनित हुई थी। इनमें से 168 छात्राओं को ही स्कूटी का वितरण किया गया, जबकि शेष 1,000 छात्राओं को आज दिनांक तक उक्त योजना के अन्तर्गत स्कूटी वितरण नहीं किया गया। जबकि सरकार की ओर से वर्ष 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा चुका है।

वर्ष 2022-23 की छात्राओं को पात्र होने के बावजूद स्कूटी वितरण नहीं हो पा रहा है। यहां की छात्राएं स्कूटी वितरण के लिए विगत वार कलेक्टर, विधायक, सांसद, शिक्षा अधिकारी, कॉलेज प्राचार्य, समाज कल्याण विभाग इत्यादि को ज्ञापन दे चुकी हैं, किन्तु इन गरीब आदिवासी छात्राओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में वीर बाला काली बाई भील स्कूटी वितरण योजना में वर्ष 2022-23 में वंचित छात्राओं को शीघ्रातिशीघ्र स्कूटी का वितरण किया जावे, जिससे उक्त गरीब आदिवासी छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। सादर।

Kas/rtm/03.02.2025/12.30/1k

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

बून्दी के ग्राम सिन्ती पंचायत उलेड़ा के अध्यापक श्री मनीष मीणा के परिजनों को आर्थिक सहायता

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिन्ती पंचायत उलेडा तह. व जिला बून्दी के निवासी श्री मनीष मीणा (अध्यापक) की दिनांक 04.11.2024 को बदमाशों ने चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी। यह अपने परिवार का एकमात्र सहारा है और अविवाहित है एवं सन्तान विहीन है।

इसकी मृत्यु के पश्चात मीणा समाज सहित अन्य समाजों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आर्थिक सहायतार्थ एवं न्याय दिलाने के संबंध में बड़ा धरना दिया था। हालात की गम्भीरता और जन आंदोलन के व्यापक रूप व जन आक्रोश के बाद जिला कलेक्टर, बून्दी ने सहायतार्थ 1 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक परिवारजनों को कोई मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोई राशि उपलब्ध नही हुई और धरना चल रहा है।

शिक्षा विभाग के द्वारा अविवाहित होने तथा माता पिता की अधिक उम्र होने से

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों का हवाला देते हुए नहीं दी जा रही है। साथ ही 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण समय पर राज्य बीमा की राशि जमा नहीं होने के फलस्वरूप बीमा की कोई राशि भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

अतः मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता धनराशि के साथ-साथ सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए बीमा की राशि और अन्य सहायता राशि उपलब्ध कराना चाहिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल।

पीपल्दा में नौनेरा बैराज हेतु ग्राम ऐबरा की भूमि का अधिग्रहण

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूँ कि पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र की सुल्तानपुर तहसील के ग्राम ऐबरा में नौनेरा बैराज के तहत इन्टेकवेल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु ग्राम ऐबरा में किसानों की जमीन को अधिग्रहीत करने हेतु समाचार पत्रों में दिनांक 24.12 2024 को विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञप्ति से स्पष्ट है कि ऐबरा गाँव के करीब 60 से 75 प्रतिशत लोगों की जमीन का अधिग्रहण कर लिया जावेगा। यदि ऐसा हुआ तो वर्षो से निवास कर रहे ऐबरा ग्राम के बाशिंदों को यहाँ से अन्यत्र जाना पडेगा। यहाँ के निवासियों ने नौनेरा डेम के निर्माण में पूरा पूरा सहयोग किया है। यह भी सही है कि इनके पुनर्स्थापन पर सरकार इनको पूरा मुआवजा देगी मगर स्वाभाविक है कि व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहाँ की भूमि से उसका लगाव हो जाता है। ऐबरा के निवासियों की जमीन ही एक मात्र रोजी रोटी का साधन है। यदि इनकी जमीन अधिग्रहण कर लो जाती है तो इनके यहाँ रहने का कोई औचित्य ही नहीं है, निश्चित ही इनके साथ अन्याय होगा।

इससे पूर्व भी नौनेरा डेम की नहर के लिए भी ऐबरा ग्राम की कुछ जमीन अधिग्रहण करने हेतु सर्वे किया जा चुका है।

पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के नौनेरा डेम के आसपास बहुत अधिक वन विभाग की व सरकारी जमीन स्थित है। यदि सरकार ऐबरा गाँव के निवासियों की जमीन को अधिग्रहण नहीं कर वन विभाग की जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो यहाँ के निवासियों को घर से बेघर नहीं होना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि यह एक गंभीर विषय है। इस विषय पर आपका संरक्षण चाहिए। आपका संरक्षण मिलने पर ही पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ऐवरा के निवासियों के साथ न्याय होगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा

कोटा स्थित श्री मथुराधीश मन्दिर कॉरिडोर एवं परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य का शीघ्र प्रारम्भ

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा कार्य संचालन

एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 295 के तहत मथुराधीश जी मंदिर का विकास करवाने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि वल्लभ सम्प्रदाय की सात उप पीठों में कोटा मथुराधीश जी प्रथम पीठ हैं, सम्पूर्ण देश से दर्शनार्थी यहां आते हैं। लोगों की जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिसमें मथुराधीश जी मंदिर भी सम्मिलित है। कार्यकारी संस्था कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा मंदिर के विकास, परिक्रमा मार्ग, कॉरिडोर एवं हेरिटेज सिटी विकास हेतु लगभग 65 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस मंदिर का परिक्षेत्र नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर क्षेत्र की प्रतिकृति ही है, इसलिए मंदिर समिति, संत समाज, स्थानीय व्यापारियों, निवासियों सहित यहां आने वाले श्रद्धालुओं की हार्दिक अभिलाषा है कि नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर की भांति ही मथुराधीश जी मंदिर कॉरीडोर एवं परिक्रमा मार्ग व हेरिटेज सिटी का विकास करवाया जाये। इससे बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे और कोटा की अर्थव्यवस्था को धार्मिक पर्यटन का सम्बल मिलेगा।

गत बजट में विकास राशि स्वीकृत होने के बाद भी आज तक इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। अतः आप से आग्रह है कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए श्री मथुराधीश मंदिर का परिक्रमा मार्ग, कॉरिडोर एवं हेरिटेज सिटी विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रामबिलास मीणा।

लालसोट के डिडवाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय

श्री रामबिलास (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे नियम 295 के तहत सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान विधानसभा प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत ग्राम डिडवाना में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र लालसोट के डिडवाना में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु राजकीय कन्या महाविद्यालय की अत्यधिक आवश्यकता है। यहां राजकीय कन्या महाविद्यालय न होने से गरीब व ग्रामीण तबके की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। डिडवाना में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। पूर्व में भी कई बार इस हेतु सरकार से मांग होती रही है परन्तु, आदिनांक तक भी यहां राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं खोला जा सका, जिस कारण यहां की बालिकाओं को लगभग 10 किलोमीटर दूर अथवा निजी महाविद्यालय में जाना पड़ता है। इनकी आर्थिक हालत दयनीय होने के कारण इन्हें पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि विधानसभा क्षेत्र लालसोट के ग्राम डिडवाना में कन्या महाविद्यालय खोला जाए ताकि क्षेत्र की ग्रामीण व गरीब तबके की

बालिकाएं उच्च शिक्षा से लाभान्वित हो सकें।

बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पुनः आपको धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का स्थाई समाधान

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना की भौगोलिक स्थिति उबड़ खाबड़ एवं पठारी क्षेत्र में बसी हुई है, जिसके कारण किसानों को पेयजल एवं सिंचाई संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जब गरीब किसानों को पीने का स्वच्छ पानी एवं सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी नहीं मिलेगा तो स्वतः ही आर्थिक स्थिति में पिछड़ना स्वभाविक है। मेरे विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना में पलायन का मुख्य कारण भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होना एवं अन्य स्रोतों द्वारा आय नहीं होना ही है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना में करीबन 300 गांव व ढांणियां पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई हैं जिनके लिए मैने पूर्व में भी सदन को काफी बार अवगत करवाया है। विधानसभा क्षेत्र में माइक्रो एवं मिनी डेम बनाये जाये जिनका सर्वे भी कराया गया था, लेकिन पिछली राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज नहीं देने के कारण कार्य रुका हुआ पड़ा है। क्षेत्र की स्थिति हाल ही में जस की तस बनी हुई है। अगर राज्य सरकार क्षेत्र में निवास करने वाली जातियां भील, मीणा, तंवर, गुर्जर, बंजारा, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष पैकेज या दर्जा दिया जाकर उनकी मांग को ध्यान में रखकर नये माइक्रो डेम, मिनी डेम एवं पेयजल व कृषि विभाग के द्वारा कृषि संबंधी उपकरण जैसे फव्वारा सिंचाई, तारबंदी, पाइप लाइन पर विशेष ध्यान देकर क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सकता है, धन्यवाद।

mdp/rtm/03.02.25/12:40/1l

श्री अध्यक्षः श्री फूल सिंह मीणा

पेरिफेरी क्षेत्र में पट्टों से वंचित राजस्व ग्रामों में कैम्प

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत् विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उदयपुर जिले में यूडीए के पेरिफेरी क्षेत्र में बसे हुए आमजन को पट्टा दिलवाने के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने आश्वासन दिया कि आप हमको वर्ष नवम्बर, 2011 तक का कोई सबूत लाकर देंगे तो आपको पट्टा दे देंगे। मगर पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में आम जनता को एक भी पट्टा नहीं दिया इसके कारण आमजन को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं, जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना व ऋण लेकर मकान का

निर्माण करवाना हो आदि के लिए यूडीए व अन्य विभागों में चक्कर काटते रहते हैं, इससे जनता में बड़ा आक्रोश है तथा जिन पंचायतों का सर्वे करके पंचायत को पट्टा देने के लिये स्वीकृत कर दिया है, उन पंचायतों को नगर निगम में ले लिया है। उनको तुरंत प्रभाव से नगर निगम द्वारा नियमों के आधार पर पट्टा दिलवाया जावे।

अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यूडीए के पेरा-फेरी क्षेत्र में बसे लगभग 130 राजस्व गांवों एवं जिन पंचायतों का सर्वे करके पंचायतों को पट्टा देने के लिये स्वीकृत कर दिया है, उन पंचायतों को नगर निगम में ले लिया है। उनको तुरंत प्रभाव से नगर निगम द्वारा नियमों के आधार पर आमजन को शिविर के माध्यम से कैंप लगवाकर पट्टे दिलवाये जाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्षः श्री हरि सिंह रावत।

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की ग्राम पंचायतों का जनजातीय क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठन

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन जनजातीय क्षेत्र (टीएसपी) के तर्ज पर करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम व ढाणियां बिखरी हुई आबादी में बसे हुए हैं। उक्त क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र की तरह ही बसा हुआ है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के वर्ष 2003 से 2008 तक कार्यकाल के दौरान बजट घोषणा वर्ष 2005-06 में उक्त क्षेत्र के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास के लिए मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन किया गया था।

माननीय, जिस प्रकार जनजातीय क्षेत्र के विकास हेतु पंचायतों का गठन 2000 तक की आबादी अनुसार किया जाता है। उसी की तर्ज पर मगरा क्षेत्र के विकास के लिए मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन किया जाता है तो छोटी पंचायतें बनने से सरकार की मंशा अनुसार क्षेत्र का सर्वागीण विकास होगा।

अतः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार का इस ओर ध्यानाकर्षण करवाते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि मगरा क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन जनजातीय क्षेत्र की तर्ज पर किये जाने का श्रम करे, जिसके लिए मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोग आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः पर्ची। श्री भागचंद टांकड़ा। श्री भागचंद टांकड़ा। (अनुपस्थित)

श्री कालीचरण सराफ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजकीय जयपुरिया अस्पताल (जयपुर) में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की भारी कमी से उत्पन्न अव्यवस्था

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जयपुर शहर के दक्षिण में स्थितराजकीय जयपुरिया अस्पताल में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ की भारी कमी के कारण चिकित्सा व्यवस्था चरमराने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 में जब 100 बेड हॉस्पिटल में थे, उस समय 48 चिकित्सकों के पद स्वीकृत थे। उसके बाद 2015 में जब 150 बेड हुए, उस समय भी 48 चिकित्सक थे और 2017 में 470 बेड हुए, उस समय भी वहां 48 चिकित्सक थे। जबकि 2013 में ओपीडी 300 से 350 थी, वर्तमान में ओपीडी 3000 से 3500 के लगभग है। आईपीडी में 95 परसेंट ऑक्यूपेंसी है। हर महीने 400-500 सर्जरी होती हैं। 250 से ज्यादा डिलिवरियां महिलाओं की होती हैं। स्वीकृत पदों में बढ़ोत्तरी नहीं होने के कारण व्यवस्था सुचारु रूप से चले इसलिए 22 चिकित्सक अधिशेष और 11 चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर वहां लगे हुए थे। पूर्ववर्ती सरकार ने 3 सितम्बर, 2022 को एक तुगलकी आदेश निकालकर 22 अधिशेष डाक्टर्स को अन्यत्र लगा दिया और 11 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी। इसके कारण वहां चिकित्सा व्यवस्था बिलकुल चरमरा गयी।

वर्ष 2013 के बाद निरंतर वहां सुविधाओं का विस्तार हुआ। ट्रोमा वार्ड, एमआरआई, सीटी स्केन, इमरजेंसी, नये वार्ड बनाये गये और 2021 में टाटा ट्रस्ट के द्वारा पीआईसीयू और नये वार्डों का वहां पर निर्माण हुआ, परंतु वे शुरू नहीं हो पाए। 6 करोड़ की लागत से न्यू ट्रोमा सेंटर की स्थापना हुई, परंतु वहां केवल मरहम-पट्टी का काम होता है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आरयूएचएस का पहले कोई सम्बद्ध हॉस्पिटल नहीं था। अब वहां आरयूएचएस का हॉस्पिटल बन गया, इसलिए जयपुरिया हॉस्पिटल की सम्बद्धता वहां से हटाकर एसएमएस हॉस्पिटल पर की जाए। जो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी है, वहां पर जितने बेड हैं, उसके अनुरूप बढ़ाई जाए, जिससे वहां की चिकित्सा व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

किशनगंज-शाहबाद की पंचायतों का ई.आर.सी.पी. से जुड़ाव

श्री ललित मीना (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं आपके माध्यम से, हमारे इस सदन के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और देश के प्रधान मंत्री जी को पहले धन्यवाद दूंगा कि 17 दिसम्बर को इस राजस्थान का ऐतिहासिक दिन रहा। उस दिन ईआरसीपी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गयी और जो दोनों डेम हमारा महलपुर और रामगढ़ बैराज, जिनकी

आधारशिला रखी गयी, वे मेरे विधान सभा क्षेत्र से ही है। वहीं से ईआरसीपी की शुरूआत होती है।

मैं सदन के माध्यम से हमारे मंत्री महोदय का, हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ईआरसीपी का अभी वर्तमान में वहां काम चालू हो गया है। डिपार्टमेंट द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुआवजा भुगतान किए जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ होगा। आज वर्तमान में वहां पर काम चालू हो गया है। किसानों की फसल खड़ी है। इसको देखते हुए वहां पर उनके लिए तुरंत, जिनके पट्टे हैं, उनको खातेदारी की जमीन पर मुआवजा दिया जाए और जो रामगढ़ बैराज है, इससे लगभग मेरे 35 गांव डूब में आ रहे हैं। किसानों को तुरंत राहत प्रदान की जाए।

इसके साथ ही सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस विधान सभा क्षेत्र में डेम बन रहे हैं, उस विधान सभा क्षेत्र को ईआरसीपी से जोड़ने का काम कीजिए। मेरा विधान सभा क्षेत्र वर्तमान में आदिवासी जनजाति विधान सभा क्षेत्र है और बांरा जिले में पहले बृहद सिंचाई परियोजना परवन, इसका पानी लाभ के लिए हमारे अटरू, बांरा, झालावाड़ और अंता को मिला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र उपेक्षित किया गया है। सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरी विधान सभा में मध्यम सिंचाई परियोजना उम्मेद सागर, मध्यम सिंचाई परियोजना गोपालपुरा, मध्यम सिंचाई परियोजना बिलासगढ़, हथवारी खीरिया, रातई ढिकवानी, खटका, समेली फाटक, नारायणगढ़, ऐसी बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनको ईआरसीपी से जोड़कर मेरे नाहरगढ़ क्षेत्र को केलवाड़ा, समरानिया, शाहबाद को जोड़कर ईआरसीपी से पेयजल और सिंचाई हेतु उनको जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में मेरी विधान सभा को ईआरसीपी के रूप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मुख्य मंत्री जी भगीरथ के रूप में लेकर आए हैं, उसका लाभ मिले, किसानों को भी लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मंत्री जी विराजे हैं, मैं आश्वासन चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने हेतु बजट में या यहां पर आश्वासन देने का श्रम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

पश्चिमी राजस्थान में निजी कम्पनियों द्वारा डी.एल.सी. से कम रेट पर किसानों की जमीन की खरीद-फरोख्त

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया। वर्तमान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। वर्तमान सरकार किसानों को लेकर बहुत संवेदनशील है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में कई हाइटेंशन लाइनें निकल रही हैं, परंतु इसकी एवज में किसानों को न तो पूरा मुआवजा मिल रहा है, बल्कि किसानों को परेशान व हताश किया जा रहा है।

Msk/rtm/03.02.25/1250/1m

यह जो काम चल रहा है, वह न किसी योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे को छोड़कर बाकी जगह अवैध तरीके से यह जो काम हो रहा है, मेरा निवेदन रहेगा कि इस ओर ध्यान रखा जाये। साथ ही साथ, हमारे जो अन्नदाता हैं, उनके हक और अधिकारों की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और प्रदेश की सरकार इसको लेकर एक ठोस कदम उठाये। साथ ही साथ, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसको किसी भी तरीके से फोलो नहीं किया जा रहा है। यह वाकई चिन्ता का विषय है। साथ ही साथ, कंपनियों को जो जमीन चाहिए, वह जमीन उनके लिए एक छोटा-सा टुकड़ा होगा, पर किसी अन्नदाता के लिए वह उसके जीवन जीने का एक आधार है। इसके लिए किसानों को उनका पूरा हक और अधिकार पूरे तरीके से मिले। हमारे उस क्षेत्र में किसानों के पास बहुत कम भूमि है। कई सारे ऐसे किसान ऐसे हैं, जिनके पास 5 से 7 बीघा ही जमीन है। एक पोल की वजह से वह पूरी जमीन कहीं न कहीं कवर हो जाती है, जिसके कारण वे खेती करने में भी असमर्थ हैं। हमारा निवेदन यह है कि आप लाइनें निकालें, पर कम से कम उस किसान को पूरे तरीके से मुआवजा दें। वर्तमान में जो मुआवजे से सहमत नहीं होता, उस पर पुलिस और प्रशासन द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है। धमकाने की आये दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। एक अन्नदाता को इस तरीके से परेशान करना ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारा जो अन्नदाता है, वह बार-बार कहीं-कहीं दर-दर की ठोकरें न खायें, इसके लिए हमें मजबूती से उनकी बात को आगे तक रखना चाहिए।

साथ ही साथ, मेरा निवेदन रहेगा कि मुआवजे को लेकर जो एक नियम बनाया है। मेरा निवेदन है कि इनमें भी संशोधन की जरूरत है और किसानों को पूरे तरीके से उनके हक और अधिकारों के तहत पूरा मुआवजा मिले। उचित मुआवजा दो और आप लाइनें निकालें, हम लाइनों के विरोध में नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से विकास के विरोध में नहीं, पर विकास के नाम पर किसान के साथ में इस तरीके से जो अनैतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, वह चिंता का विषय है। यह सिर्फ बाड़मेर का नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान का है। मुझे लगता है कि संवेदनशील सरकार आने वाले समय में किसानों के हित में फैसला लेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार का प्रतिवेदन (क्रम सं. 8)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2025 को मध्याहन पश्चात 02.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय

लिया कि शनिवार, दिनांक 01 फरवरी से बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2025 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाये :-

शनिवार, दिनांक 01 फरवरी 2025 से रविवार, दिनांक 02 जनवरी 2025 तक	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 03 फरवरी 2025	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
मंगलवार, दिनांक 04 फरवरी 2025	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 05 फरवरी 2025 एवं गुरुवार, दिनांक 06 फरवरी 2025 तक	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।
शुक्रवार, दिनांक 07 फरवरी 2025	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
शनिवार, दिनांक 08 फरवरी, 2025 से मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2025 तक	बैठक नहीं होगी
बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2025	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की 04 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या: प.(6)(75)परि/कर/मु./08/13509, दिनांक 04.09.2024 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) आने जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 6500/- रुपये से अधिक के करों का परिहार करती है;

2. अधिसूचना संख्या: प.6(260)परि/कर/मु./2011/18491, एस.ओ.96 दिनांक

26.12.2024 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उर्स मेले के दौरान अन्य राज्यों से अजमेर शहर आने जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 7000/- रुपये से अधिक के कर की राशि में छूट प्रदान की गई है;

3. अधिसूचना संख्याः प.(7)(552)परि/नियम/मु./2017-04161/17062, दिनांक 22.11.2024 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः प.(7)(552)परि/नियम/मु./2017/15227, दिनांक 17.07.2018 को अधिक्रमित किया गया है; एवं

4. अधिसूचना संख्याः प.(7)(3)परि/नियम/मु./2024-07933/18632, जी.एस.आर.89 दिनांक 30.12.2024 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

गृह विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 12 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 21.11.2024 जिसके द्वारा दिनांक 02.08.2024 को गजट में प्रकाशित अधिसूचना में अंकित 'दिनांक 29 जुलाई, 2021' की जगह '29 जुलाई, 2024' पढ़ा जावे;

2. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 29.07.2021 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं को दिनांक 29.07.2024 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

3. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 29.07.2021 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं को दिनांक 29.07.2024 से आगामी छः माह तक हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है;

4. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 21.11.2024 जिसके द्वारा दिनांक 14.11.2024 को गजट में प्रकाशित अधिसूचना में अंकित 'घोषणा' की जगह 'अधिसूचना' पढ़ा जावे किया गया है;

5. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 25.10.2024 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) की सेवाओं को दिनांक 29.10.2024 से आगामी छहमाह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

6. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 25.10.2024 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) से संबंधित सेवाओं को दिनांक 29.10.2024 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया

है; एवं;

7. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 21.11.2024 जिसके द्वारा M/s Modern MVUs Pvt. Ltd mi M/s Community Action Through Motivation Programme द्वारा संचालित योजनाओं 1962 मोबाईल वैटरनरी यूनिट व BFIL द्वारा संचालित समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध के संबंध में दिनांक 14.11.2024 को गजट में प्रकाशित अधिसूचना में अंकित 'घोषणा' की जगह 'अधिसूचना' पढ़ा जावे;

8. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 08.11.2024 जिसके द्वारा M/s Modern MVUs Pvt. Ltd mi M/s Community Action Through Motivation Programme द्वारा संचालित योजनाओं 1962 मोबाईल वैटरनरी यूनिट व BFIL द्वारा संचालित कॉल सेन्टर से संबंधित सेवाओं को दिनांक 08.11.2024 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

9. अधिसूचना संख्याः प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 08.11.2024 जिसके द्वारा M/s Modern MVUs Pvt. Ltd mi M/s Community Action Through Motivation Programme द्वारा संचालित योजनाओं 1962 मोबाईल वैटरनरी यूनिट व BFIL द्वारा संचालित समस्त सेवाओं को दिनांक 08.11.2024 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है;

10. अधिसूचना संख्याः प.(37)(1)गृह-9/2021, जी.एस.आर.76 दिनांक 19.11.2024 जिसके द्वारा राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्याः प.8(1)गृह-12/कारा/2013 दिनांक 24.06.2024 जिसके द्वारा हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र, गांव हिंगोनिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.) को 10 बंदी क्षमता का अस्थाई ''खुले हवा शिविर''घोषित किया गया है; एवं

12. अधिसूचना संख्याः प.4(1)गृह-12/कारा/2024-21426 दिनांक 26.12.2024 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार नियम, 2022 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्षः कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

प्रतिवेदन एवं लेखे

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 12वां प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24;एवं

साल्ट्स लिमिटेड का 59वां प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड

(ई.आर.सी.पी.सी.एल) का प्रथम प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अनुसार, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड (ई.आर.सी.पी.सी.एल) का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम-32 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: गजेन्द्र सिंह जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1. मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23; एवं

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

2. मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 की उप धारा 2 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25;

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025, श्री गजेन्द्र सिंह प्रभारी मंत्री।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

भारतीय जनता पार्टी	9 घंटे 31 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	5 घंटे 16 मिनट
भारत आदिवासी पार्टी	19 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	10 मिनट
राष्ट्रीय लोकदल	5 मिनट
निर्दलीय	39 मिनट

कुल 16 घंटे हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि अपनी-अपनी पार्टी के समय के अनुसार विभाजन करें। सदस्य संख्या भी उतनी ही सचेतकों को दें, जितनी इस समय में पालन किया जा सके। विशेष रूप से छोटी पार्टियां हैं, उनका हर सदस्य मेरे पास आता है कि मुझे बोलने दिया जाये। उनके नेता जो भी हैं, उनके द्वारा नाम लिखित में आ जाये कि हमारी ओर से इस समय-सीमा पर यही बोलेंगे, ताकि उनको बोलने की अनुमति दी जा सके।

सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 तक के लिए स्थगित हुई।)

Ans/rtm 14.00 2c 03.02.2025

(समय:14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

नवीन नेवा एप्लिकेशन के सुचारु संचालन हेतु निर्देश एवं

माननीय सदस्यों से अपेक्षित सहयोग

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन के सदस्यों को एक जानकारी देनी है कि विधान सभा की कार्यवाही को पेपरलैस बनाने हेतु नेवा लागू किया गया है। इसके तहत सभी माननीय सदस्यों की सीटों पर आईपेड भी स्थापित किये गये हैं।

सदन की गरिमा तथा उपकरणों की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्देश है कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी फेस आईडी से उपकरणों को लॉक नहीं करें तथा ना ही एपल आईडी उसमें प्रविष्ठ करें। ऐसा करने से उपकरणों का विधान सभा सचिवालय द्वारा संधारण करना असुविधाजनक हो जायेगा।

सदन की कार्यवाही के दौरान हॉटस्पाट प्रयुक्त कर नेवा की ई-बुक के अतिरिक्त अन्य कोई वैबसाइट सर्फ नहीं करें।

आइपेड का कैमरा ऑन कर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करें। किसी प्रकार का ऑडियो सदन में प्ले नहीं करें।

आईपेड पर नेटवर्क तथा चार्जिंग केबल के द्वारा हो रही है। अतः चार्जिंग केबल को अनप्लग्ड नहीं करें। आईपेड की सेटिंग्स में भी परिवर्तन नहीं करें।

नेवा पर प्रयुक्त लॉग-इन का पासवर्ड यदि बदले तो स्वयं याद रखें। यदि आप पासवर्ड भूल गये हैं तो कक्ष संख्या 315 में जाकर रिसेट करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा आईपेड में लॉग-इन करने पर उपस्थिति भी दर्ज होती है।

सदन में आपकी सहायता के लिये तकनीकी कार्मिक उपलब्ध हैं आवश्यक होने पर आप उनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आईपेड के माध्यम से पेपरलैस विधान सभा हेतु अपन जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग वांछनीय है।

श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू):माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक सेकण्ड।

व्यवस्था का प्रश्न

वाद-विवाद के दौरान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा असंसदीय अभिव्यक्ति का प्रयोग

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन चल रहा था, उस वक्त नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर संसदीय कार्य मंत्री ने एतराज उठाया और एतराज ही नहीं बल्कि गाली दी कि +++ बहुत हो गया, इससे

बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपको भी अनुमति मिलेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष को गाली दे और यह सदन यूं ही चलता रहे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): असंसदीय भाषा आप ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैंने अनुमति दी है। आपको भी अनुमति देंगे आप चाहोंगे तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको तो अनुमति मिल गई। इनका कोटा तो आप खा गये, अब इनको कुछ नहीं मिलना। सीरियस बात है कि अगर संसदीय कार्य मंत्री ही अगर गाली दे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब गाली दे तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हम जनता के मुद्दों के लिए यहां आते हैं, गाली खाने के लिए नहीं आते हैं। अध्यक्ष महोदय को प्रतिपक्ष का संरक्षण करना पड़ेगा और इसके ऊपर व्यवस्था दे, जोगाराम जी माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई और मैं माफी मांगता हूं, उसके बाद सदन चलेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय संसदीय मंत्री, कुछ कहेंगे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा लंबे समय का इस विधान सभा का अनुभव रहा है। मैं स्वयं, मेरे दल के सभी साथी, चाहे विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, हम हमेशा अपने साथियों का मान-सम्मान और आदर करते हैं। अपनी बात पूरे प्रभावी ढंग से रखते हैं, इसमें कोई कमी भी नहीं रखते। ना हमारा कभी आशय रहा है किसी की मान-मर्यादा को ठेस पहुंचाना या असंसदीय शब्द बोलने का। चूंकि कभी ऐसा मन भी नहीं रहा है और ना कभी ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं, ना कभी किया है, ना कभी भविष्य में करेंगे। जब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मान-सम्मान हो तो मैं भी चाहता हूं कि दूसरे का मेरे से भी अधिक मान-सम्मान हो। अगर कहीं भी फ्लो में बोलते वक्त, उत्तेजना में कोई हो जाता है उस पर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ना कभी बोलने की इंटेंशन थी, इसलिए इसको डिलीट फरमाया जाए, मेरा ऐसा निवेदन है।

भविष्य में कभी भी ऐसी किसी माननीय सदस्य के प्रति, चाहे हमारा कोई विधान सभा का साथी हो, किसी के प्रति कोई असम्मान की नहीं होगी और इसके लिए अगर कोई हो तो हम सॉरी फील करते हैं। कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ना कभी कहा है और ना कभी भविष्य में कहेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने कहा ही नहीं तो फिर डिलीट क्या करवा रहे हैं। जब डिलीट करवा रहे हैं तो माफी मांगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऐसा है तो डिलीट कर ले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब डिलीट करवा रहे हैं तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है। ...(व्यवधान)... अगर रिकार्ड के अन्दर आया है तो माफी मांगनी चाहिए। हमारे शान्ती धारीवाल जी ने मांगी थी, हमने इनकी तरफ से मांगी थी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन यह है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर है तो जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसा हो तो हम सॉरी फील करत हैं। ...(व्यवधान)... हम कोई आपकी तरह अड़े हुए नहीं रहते हैं, ना कभी फील करते हैं, ना उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ है। हम सभी का मान और सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। चलिए, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस शुरू करते हैं। श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे भी करना है। पिछले एक साल से मुख्य सचेतक के रूप में काम देख रहा हूं और हाउस ठीक चले मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ी छोटी-मोटी है। मेरा अनुभव यह है, इस हाउस को सबसे ज्यादा यदि डिस्टर्ब करते हैं तो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक करते हैं, उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, आग्रह है, निर्देश है कि सदन की मर्यादाओं, परम्पराओं और नियमों का सभी पालन करें। यदि कहीं बात हो जाती है तो तुरंत हम उसके लिए, मैं समझता हूं कि खेद प्रकट में कोई नहीं है। इधर से भी हुआ है, इधर से भी। भविष्य में पक्ष-विपक्ष दोनों की ओर से किसी प्रकार का नहीं हो। साधारणतया बीच-बीच में बोलने की जो आदत है, मैं समझता हूं कि इसको समाप्त करें। समय का भी अपव्यय होता है। हम लोग अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें तो अधिक समय तक सदन भी चले और आपके सार्थक विषयों पर बात हो। ...(व्यवधान)...

फिर बीच में बोले, अभी तो मैं खड़ा ही हूं, फिर मुझे पिनपाइंट करना पड़ेगा। सदन में विपक्ष के नेता भी हैं, संसदीय मंत्री भी हैं, दोनों सचेतक भी हैं, इनके पास भी जो अपने-अपने अधिकार है वह भी इनका पालन करें। सूची देनी है तो मुझे दोनों सचेतक दें। सदस्य अपने-अपने सचेतक को नाम लिखवाए। बीएसी की मीटिंग होती है उसका सम्मान रखते हुए उसको अपना काम करने दे, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है।

अब श्री कैलाश चन्द वर्मा। ...(व्यवधान)... अब सदन चलने दो भई। दोनों पक्ष विषय रखें। चर्चा आने दो।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए, इस सत्र में एकत्रित हम सब राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन

में दिए गए अभिभाषण के प्रति आभारी है।

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्तुत शुरूआत में बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण ने इस पवित्र सदन को अपने शब्दों से इतना पवित्र किया कि आने वाले समय के अन्दर उनके द्वारा बोली गई एक-एक बात गांव, गरीब, किसान तक जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका मार्गदर्शन भी, इस सदन में नवाचार हेतु बहुत अच्छे काम किए, इसलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। बार-बार विपक्ष वाले उठ-उठकर, इनकी हमेशा समस्या थी, पिछली बार भी जब मैं बोल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष और माननीय इनके अध्यक्ष जी बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे थे, टोक रहे थे, मुझे आपका सानिध्य चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मेरे स्वास्थ्य की चिंता ईश्वर करता है बाकी आप सबकी, दोनों पक्षों की शुभकामनाएं मेरे साथ है।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): इस लोकतंत्र के पवित्र मन्दिर में, इसका एक-एक मिनट कीमती है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण में 168 बिन्दु और मैंने पहली बार देखा कि 01 घंटे, 27 मिनट का भाषण। बीच में विपक्ष टोकता रहा क्योंकि इनकी पुरानी आदत है। मैं जब से देख रहा हूं, बीच में उठना, टोकना। इन्होंने राज्यपाल महोदय को भी नहीं बख्शा। जब यह टोक रहे थे तो राज्यपाल ने इनको जवाब भी दिया। एक कहावत है, मैं उन शब्दों को बोल नहीं सकता। इसलिए मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत शुरूआत में मुझे बोलने का अवसर दिया।

VPS-RTM-03.02.2025-14.10-2d

मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल का विधायक हूं जो विश्व का सबसे बड़ा दल है जिसके प्रधान सेवक केन्द्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अन्दर आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000-2005 के अन्दर भरतपुर की अटारी ग्राम पंचायत से निकला हुआ एक ग्राम पंचायत का मुखिया, किसी ने नहीं सोचा था कि ग्राम पंचायत के अन्दर अपनी कुशल नेतृत्व की योजनाएं बनाते हुए वह प्रदेश का मुखिया बन जायेगा और गांव, गरीब, किसान की आवाज बनकर राजस्थान के लिए नए नवाचार के काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन मुझे शांति से सुने और सुनने का मन बना सके तो मैं इसका भी आभारी रहूंगा। केन्द्र की कुशल नेतृत्व वाली सरकार के विजन को साकार करते हुए यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने मात्र एक साल में समग्र विकास के लिए दूरगामी निर्णय लिये हैं जो आने वाले समय के अन्दर राजस्थान के लिए उपयोगी साबित

होंगे। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा-

''मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था,
मगर सफर में मुझे हर शख्स अपना लग रहा था।
यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज इस मुकाम पर,
जब जग सो रहा था तब मैं जग रहा था।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पिछले पांच साल तक आपसी खींचतान, कुर्सी की लड़ाई के कारण अस्थिर रही और इसका कारण वे प्रदेश के अन्दर अच्छा शासन नहीं दे पाये। जूली साहब मुस्करा रहे हैं। मेरे को पता है कि इनकी मुस्कराहट के अन्दर विश्वास मैं करूंगा नहीं। आप कितना ही मुस्कराओ मैं आपके चक्कर के अन्दर आने वाला नहीं परंतु भाजपा सरकार ने राम राज्य के संकल्प को मजबूती देते हुए, मजबूत कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन करवाकर आमजन को राहत प्रदान की है और मैं विपक्ष को उदाहरण देना चाहूंगा कि कल आर.ए.एस. की परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश के अन्दर हुआ, लीक तो क्या एक पत्ता भी नहीं हिला, तो इससे भी आपको एक सीख लेनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके इस राजस्थान को छोड़ा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय वर्ष 2018 में प्रदेश के ऊपर ऋण भार 2 लाख 81 हजार 182 करोड़ था, विगत कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण वर्ष 2023 में राज्य ऋण भार दुगना यानी, 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये हो गया। 2018 में प्रति व्यक्ति ऋण 36,880 रुपये था जो विगत सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 70,800 रुपये हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय प्रदेश के अन्दर जंगल राज था। आप यदि किसी भी विभाग की बात करते थे तो केवल और केवल वहां लूटने के लिए किसी प्रकार की कमी न कोई मंत्री छोड़ता था और जो आपने पूरे राजस्थान के अन्दर 200 मिनी मुख्य मंत्री बनाये थे, उन्होंने भी राजस्थान का बंटाढार करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी।

विगत पांच साल राजस्थान महिला अत्याचार, दुष्कर्म एवं अपराधों के अन्दर शीर्ष पर रहा। 2019 के अन्दर 42,740 प्रकरण दर्ज हुए। 2020 के अन्दर 35,963, 2021 के अन्दर 42,757, 2022 के अन्दर 47,105 और 2023 के अन्दर 46,380 प्रकरण दर्ज हुए हैं। प्रदेश की छवि खराब होती रही, राजा नींद के अन्दर सोता रहा और इनके मंत्री इसी सदन के अन्दर गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे कि दुष्कर्म तो होते हैं, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के लिए। राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। विगत एक वर्ष में आपराधिक मामलों के अन्दर कमी हुई है। दुष्कर्म के साथ हत्या के मामलों में 26.67 परसेंट की कमी, हत्या के मामलों में

15.25 परसेंट की कमी, डकैती के मामलों में 13.33 परसेंट की कमी, लूट के मामलों में 30.36 परसेंट की कमी, चोरी के मामलों में 34.00 परसेंट की कमी और दुष्कर्म के मामलों में 34.00 परसेंट की कमी, तो यह आकड़े यह बताते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार में अपराधियों में खौफ है और इसीलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश के अन्दर आयेगा नहीं और आयेगा तो बचकर जायेगा नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के प्रथम अभिभाषण में सभी जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के अन्दर रखा। मात्र एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में अंकित 50 से 60 परसेंट वादों को पूरा करने का काम किया जिससे मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का, आम जन का सरकार के प्रति मजबूत विश्वास हुआ इसीलिए प्रदेश की जनता यह कहती है कि भाजपा जो कहती है वह करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, शायद मेरी नसीहत आपके समझ में नहीं आयी और मैं ठोक-ठोककर बोला था, एक-एक शब्द का जवाब दिया था आपको इसी सदन के अन्दर, विपक्ष शुरू से यह तंज़ कसता था कि साहब, यह तो पर्ची की सरकार है, यह कहां से आ गयी? मगर मैंने प्रथम बजट भाषण के दौरान भी यह कहा था कि यह पर्ची नहीं, यह विजन, विकास, जुनून, गांव, गरीब, किसान और प्रदेश को नये आयाम तक ले जाने वाली सरकार है मगर विपक्ष के दिमाग के अन्दर आपके यह बैठे ही नहीं तो मेरे पास तो उसकी कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि आपको दवाई दे दूं और आपके ऊपर जादू हो जाये, यह काम तो आपके जादूगर ही कर सकते हैं मगर जो कहा वह किया हमारी सरकार ने।

माननीय भजन लालजी के नेतृत्व के अन्दर पी.एम. किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर छह हजार रुपये से आठ हजार रुपये की और जिसे बारह हजार रुपये भी करेंगे। महिलाओं के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अन्दर पचास परसेंट का आरक्षण, पेपर लीक मामलों के त्वरित कार्यवाही के लिए एस.आई.टी. का गठन किया। हमने पांच वर्ष में चार लाख नौकरियां देने का वादा किया है। एक वर्ष के अन्दर 59 हजार से अधिक नियुक्तियां दी हैं। करीब 73 हजार पदों के ऊपर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मात्र एक वर्ष के अन्दर पांच नये मेडिकल कॉलेज खोलकर राजस्थान के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशालाओं के अनुदान के लिए दस परसेंट की वृद्धि एवं 2024-25 में 700 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। बिना किसी भेद-भाव के सभी विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर एक हजार करोड़ रुपये की सड़कें, यह आपको भी मिली थीं न? पिछली बार आप भी तालियां बजा रहे थे। प्रथम वर्ष में 206 करोड़ की लागत से अटल प्रगति पथ बनाये हैं। उज्जवला योजना एवं बी.पी.एल. के करीब 38 लाख 86 हजार परिवारों को 450 रुपये के अन्दर गैस सिलेंडर, यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनको

धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताते हुए यह खुशी है कि पूर्वी राजस्थान के अन्दर एक ऐसी योजना को साकार करने का काम माननीय प्रधान मंत्रीजी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर किया है और ई.आर.सी.पी., मैं ई.आर.सी.पी. के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं यह कहता हूं और आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इस ई.आर.सी.पी. के बारे में आपका क्या लेना-देना, आप मानते क्या हो इसके बारे में? आपने ऐसा क्या प्रमाण-पत्र दे दिया और ऐसा क्या गढ़ जीत लिया जो आप ई.आर.सी.पी. के बारे में गीत गाते हो? एम.ओ.यू. हुआ, क्या हुआ, कितना क्या हुआ, यह कर देंगे, वह कर देंगे, पानी कितना आयेगा, कितने खेत पानी पीएंगे तो आप होते कौन हो पूछने वाले? आपने क्या किया है? इसलिए आप मेरी बात को सुन लो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति में काम के प्रति समर्पण हो, वह उसे मन से करना चाहता हो, उसे कोई भी बाधा विचलित नहीं कर सकती। एक बार संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए निरंतर लगन की आवश्यकता होती है और लगातार प्रयास से ही वह पत्थर को भी पानी बना देता है। यह सिद्ध किया प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जब ही तो राष्ट्र कवि दिनकरजी ने यह ठीक ही कहा है-

"खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़!
मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है!"

(समय: 14.19 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जनता के लिए ई.आर.सी.पी. योजना का विजन प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी लेकर आयी थीं। आपकी भी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? जिसे विगत सरकार ने जानबूझकर अटकाया, लटकाया, भटकाया और राजस्थान के लोगों के साथ में अन्याय किया परंतु भजन लाल सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्रीजी की उपस्थिति में इस योजना के एम.ओ.यू. का आदान-प्रदान किया। माननीय प्रधान मंत्रीजी की सभा के अन्दर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा लोग यहां एकत्रित हुए तथा इसे भजन लाल सरकार, भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए राम सेतु लिंक परियोजना के रूप में इसे धरातल के ऊपर उतारने का काम किया।

ssy/rtm/03.02.2025/14.20/2e

अब सुनो, हमने एमओयू के अन्दर क्या किया? अभी भी सुन लेना, इसके लिए 12 हजार करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू कर दिया। इस योजना से 17 जिलों के अन्दर 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और करीब 3 करोड़ की आबादी को पेयजल मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि इतना सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद में भी आप यह गीत गाते हो कि ईआरसीपी का क्या हुआ, तो मेरी बात सुन लो, आपको आने वाले समय के अन्दर पानी भजन लाल सरकार ही पिलायेगी, इस बात को नोट कर लेना।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की भजन लाल सरकार आगामी 4 साल में और भी ऐतिहासिक काम राजस्थान की जनता के लिए करेगी। इसीलिए मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं गया, समय रहते हुए इस भजन लाल सरकार की आदत डाल लो। क्योंकि पहले बजट के अन्दर प्रशंसा आप लोगों ने ही की थी कि यह बजट तो लास्ट के अन्दर आता था। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि शुरुआत के अन्दर ऐसा बजट आया।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए कुछ लाइनें पेश करना चाहूंगा,

'जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा,
जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा,
बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता
और जो जलेगा उसी दीये में उजाला होगा'

माननीय सभापति महोदय, 'एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष' के सपने को साकार करते हुए राइजिंग राजस्थान, प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देकर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान की सरकार हमेशा संकल्पबद्ध है। इसके लिए पहले ही वर्ष के अन्दर राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया, जिसमें 32 देशों ने हिस्सा लिया। 16 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया। 32 हजार से अधिक डेलीगेट्स, विजिटर्स इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मुझे अवगत कराते हुए खुशी है कि प्रदेश के अन्दर 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बुनियाद रखी गई। प्रदेश सरकार ने 11 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1282 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जायेगा। प्रदेश सरकार 2026 के अन्दर पुनः राइजिंग राजस्थान का आयोजन करेगी। इससे राजस्थान के उद्योगों का विकास होगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जो खोखली अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, उसमें गति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के नेता हमेशा बयान देते थे इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर, हमेशा मीडिया की सूर्खियों में बने रहना, इनकी पार्टी को जिंदा करना इनका धर्म भी है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर इनके नेता हमेशा बयान देते थे कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने तो केवल योजनाओं का नाम बदला। अब मेरी सुनो, आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना किसने किया? सुनते जाओ, अन्नपूर्णा रसोई योजना को इंदिरा रसोई योजना किसने किया? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना किसने किया? विजया राजे सिंधिया एवं सहायता समूह योजना को प्रियदर्शिनी एवं सहायता समूह योजना किसने किया? दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ योजना को

मुख्यमंत्री तीर्थ योजना किसने किया? भामाशाह कार्ड योजना को जन आधार कार्ड योजना किसने किया? इसलिए बयान देने से पहले विपक्ष को अपनी गिरे बान के अन्दर भी झांक लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा।

माननीय सभापति जी, मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अन्दर काफी लोगों ने अपने खून-पसीने से, उस जमाने से लेकर आज तक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की, यूं ही नहीं बनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। जिसके अनुशासन से निकली हुई एक-एक लाइन, चाहे प्रदेश हो चाहे हिन्दुस्तान हो, उसके लिए गाइड लाइन का काम करती है। जो गाइड लाइन जारी होती है उसी के ऊपर काम होता है। उसी पार्टी लाइन से निकले हुए माननीय भजन लाल जी आज प्रदेश, गांव, गरीब, किसान की आवाज बनकर संकल्प, वादों को पूरा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के पास थोथी बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। हाल ही के अन्दर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार को सर्कस कहा। अब सुनो, मैं इन्हें पूछना चाहता हूं कि भजन लाल सरकार, मैंने पहले भी कहा था आपको, यह सरकार सर्कस सरकार नहीं है, यह सरकार सर्व गुण संपन्न सरकार है। मैं आपके बारे में बताऊं, कैसे आप लोगों ने सर्कस किया था। आपने कहां-कहां सर्कस के शो किये, यह भी आप मेरे से सुन लो।

विगत सरकार के समय शपथ से लेकर अंत तक सर्कस चली। जिसके अन्दर जादूगर डमरु बजा रहा था और माननीय सदस्य सर्कस कर रहे थे। इनकी सरकार के समय जहां-जहां शो हुए, पहला शो मुख्य मंत्री बनने से लेकर सर्कस हुआ अलबर्ट हॉल के सामने। दूसरा शो, एक लाइन का प्रस्ताव आया, जब सर्कस के अन्दर कोई कमी नहीं रही। तीसरा शो, पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि यहां मुख्य मंत्री तो मैं ही रहूंगा। मैं यहां कोई सब्जी और बैंगन बेचने थोड़े ही आया हूं। वह सर्कस से कम नहीं था। चौथा शो, कोरोना काल के अन्दर सरकार होटलों के अन्दर रही। पांचवां शो, प्रदेश को बेहाल छोड़कर आपने विधायकों की मानेसर और जैसलमेर में बाड़ेबंदी की। छठा शो, आपने कुर्सी बचाव अभियान के तहत सिविल लाइन्स के अन्दर एक माननीय मंत्री के घर के ऊपर ड्रामा किया। सातवां शो, फोन टेपिंग का और आठवां शो, जब लाल डायरी आई तब तो आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी। माननीय सभापति महोदय, यह सोचें कि हमने 5 साल के अन्दर कितने कारनामें किये, राजस्थान की जनता को कहां-कहां ठगा। राजस्थान की जनता के साथ में कहा-कहां अत्याचार किया? युवाओं के सपनों को कैसे चकनाचूर किया। महिलाओं के अस्तित्व को हम बचा नहीं पाये इसीलिए बोलने से पहले सोचो।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय अधिकारी भ्रमित रहे कि किसकी सुनें और किसकी नहीं सुनें। पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहा हूं। यह हमेशा कहते हैं कि एक साल के अन्दर तो यहां पता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब आप सुनो, हमारे पास आपके सारे प्रमाण हैं और आपके पास भजन लाल सरकार का प्रमाण ढूंढने में दिन-रात लग जायेंगे मगर आपको मिलेगा कुछ नहीं। इन्हीं की पार्टी की तत्कालीन ओसियां की विधायक थीं, इसी

सदन के अन्दर पीएचईडी मिनिस्टर को कहा था कि, PHED Minister is a rubber stamp. पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना जी ने अधिकारियों की मनमर्जी के आगे घुटने टेक दिये थे और सार्वजनिक रूप से अशोक गहलोत जी को कहा था कि मेरा इस्तीफा लेकर आईएएस कुलदीप रांका को दे दो।

आपको भजन लाल सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए थोड़ी-बहुत शर्म नहीं आती। बैठे-बैठे बोलते हो, थोड़ी मर्यादा तो सीख लो। मेरे को पता था कि आप बीच के अन्दर फड़फड़ाहट करोगे। आपके मिर्ची लगेगी। मैं प्रमाण पूरे लेकर के आया हूं। आप कहोगे तो आप मेरे पास में आ जाना, आपको एक-एक चीज से अवगत करा दूंगा।

कुर्सी की लड़ाई के अन्दर जिलों की बंदरबांट कर दी। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा कि जब 1998 से 2003 तक आपकी सरकार रही, बताइये आपने कितने जिले बनाये? कांग्रेस की 2008 से 2013 के अन्दर सरकार रही, आपने कितने जिले बनाये? लेकिन 2018 से 2023 के दौरान गुटबाजी और चहेतों को खुश करने के लिए, कुर्सी की लड़ाई के अन्दर बिना किसी वितीय प्रबंधन के गांव नगरपालिका बन रहा है, नगरपालिका नगर परिषद बन रही है। रातों-रात जिले बन गये। लोग ढाणियों में सो रहे थे, उनको पता नहीं कि मैं नगरपालिका में आ गया। नगरपालिका वालों को यह पता नहीं कि मैं जिले के अन्दर आ गया। यह आपकी कौनसी व्यवस्था है, यह मुझे समझ में नहीं आती। सारे ही काम जादू से करते हो क्या?

माननीय सभापति महोदय, इसीलिए इनको लगा होगा कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन हमारे पास है। माननीय भजन लाल जी कल करौली के अन्दर बोल रहे थे कि ईआरसीपी का पानी जब 21 जिलों के अन्दर आयेगा तो गांव, ढाणी, गरीब, किसान की प्यास बुझेगी, खेत से सोना उगल सकता है। मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि इधर से आलू डाल दो और उधर से सोना निकल जाये। कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हो। कभी हरियाणा के चुनावों में आप जलेबी की फैक्टरी लगाते हो। अब आपका कहां-कहां ध्यान रखें। आपके नेताओं के ऊपर किसी प्रकार की कोई कमांड नहीं है। लोक सभा के अन्दर विदेशी शक्तियों, ताकतों के लटका करके जाते हो।

माननीय सभापति महोदय, भजन लाल सरकार जो कहती है वह करती है। मैं आपके माध्यम से भजन लाल सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो जिले यथावत रखे, उनके कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन, वित्तीय प्रबंधन, जिला परिषदों का गठन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलें, वरिष्ठ सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): उनके ऊपर नीतिगत निर्णय लेते हुए आम जन को राहत प्रदान की। तभी तो राजस्थान की जनता कहती है कि एक साल के अन्दर, अभी 4 साल का तो हिसाब बाकी है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): राजस्थान की जनता एक साल के अन्दर बोल रही है, मजबूत मुख्य मंत्री मजबूत फैसले, आपणो राजस्थान अग्रणी राजस्थान। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए काकाजी को काकाजी कहने में कोई बुराई नहीं है।

Spp/rtm/03.02.2025/14.30/2f

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के कुप्रबन्ध ने प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखा। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी सुबह आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से जवाब दे रहे थे। मगर विपक्ष की आदत पड़ी हुई है कि बीच के अन्दर टोकना, छेड़ना और कैसे न कैसे हम सुखियों में रहें और हमारी फोटो आ जाये। बजट सेशन जब स्टार्ट नहीं हुआ तो पेपरों के अन्दर बड़ी-बड़ी न्यूज छपी और उन न्यूज के अन्दर आया कि विपक्ष तो बहुत हमलावर है, बहुत ताकतवर है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम बैठे हैं न आपका जवाब देने के लिये। आइए, ऐसे बीच के अन्दर टोका-टोकी क्यों करते हो? सामने आइए, टाइम लीजिए, आपको समय मिलेगा। एक-एक शब्द का उच्चारण कर देना। भजन लाल सरकार ने क्या किया और आपकी सरकार ने राजस्थान के साथ में कितना अत्याचार किया? आपकी सरकार ने राजस्थान के गरीब, किसान और गांव के साथ में कितना अत्याचार किया? आप भी उसी वोट की ताकत से जीतकर आते हो, हम भी उसी वोट की ताकत से जीतकर आते हैं। उस जनता के वोट की ताकत है माननीय सभापति महोदय, कि आप और हम सबके गले के अन्दर माला डलती है और सिर के ऊपर साफा बंधता है। मगर आप यहां आने के बाद में सारी हदें लांघ देते हो, सारी हदें पार कर जाते हो। कांग्रेस के कुप्रबन्धन ने ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर जनता को अंधेरे में रखने के लिये विवश किया। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार के समय हमेशा केन्द्र के ऊपर आरोप लगाते रहे। कोयला खत्म होने का रोना रोते रहे। जब भी गांवों के अन्दर बिजली जाती तो कहते कोयला तो है ही नहीं, हम बिजली कहां से लायें, हम बिजली कहां से पैदा करें। अब भी बिजली आ रही है न, अब कहां से बिजली आ रही है? अब कहां से सोलर के प्लांट लग रहे हैं? इसीलिये भजन लाल जी की सरकार ने प्रदेश को अंधेरे से निकालते हुए, मैं ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रदेश के मुखिया को, जिन्होंने गांव, गरीब और किसान की चिन्ता करते हुए, प्रदेश की जनता की चिन्ता करते हुए, साढ़े आठ करोड़ लोगों की चिन्ता करते हुए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से समन्वय स्थापित करके कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की। भाजपा सरकार ने 35 हजार 138 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिये करीब 01 लाख 58 हजार 800 करोड़ रुपये के MOU किये। मुझे खुशी है कि भजन लाल जी की सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे आने वाले समय के अन्दर किसान भाइयों को दिन के अन्दर बिजली मिलेगी। कांग्रेस सरकार के समय क्या होता था? किसान

इधर से ट्यूबवैल चालू करके खेत में पहुंचता था और पीछे बिजली गुल। फिर वह वापस जाता था, फिर बटन दबाता था कि अब तो बिजली आयेगी, फिर बिजली गुल। इसीलिये सुनने का माद्दा रखो।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पहली बार अच्छा लगा। माननीय सभापति महोदय, हम अभिभाषण सुनते आये हैं। इस सदन का भी सुनते आये हैं जब विधान सभा पुरानी बिल्डिंग के अन्दर जब हम पढ़ते थे, तब भी सुनते थे। मगर सदन के अन्दर युवाओं का प्रतिनिधित्व देखकर बड़ा अच्छा लगा। इसलिए मैं युवा होने के नाते राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवाओं का ध्यान रखते हुए युवाओं के लिये अच्छा काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, भाजपा प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपने वादे के अनुसार नकल माफियाओं को खत्म करने के लिये SIT का गठन किया। SIT का गठन ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, 260 लोगों को गिरफ्तार भी किया। प्रदेश में एक वर्ष में 100 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ में सम्पन्न भी करवायी। 81 हजार पदों के लिये भर्तियों का कैलेण्डर भी जारी किया और आपके समय के अन्दर क्या हुआ? पेपर देने जाता था, जब गांव से कोई व्यक्ति आता था, उसको यह पता था कि पेपर तो लगेगा नहीं, मुझे वापस जाना है। कांग्रेस सरकार में युवा रोते रहे और संरक्षण के अन्दर नकल माफिया पनपते रहे। शिक्षा मंत्रीजी की मौजूदगी के अन्दर शिक्षा संकुल के अन्दर पेपर का काला धंधा चलता रहा। विगत सरकार ने एक बार नहीं, 17-17 बार पेपर लीक कराकर युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। इसीलिए युवा हितों की बात करना विपक्ष के मुंह से कहां तक शोभा देती है? आप बताइए, मैं युवा होने के नाते हर डिबेट के अन्दर जाता था। जब भी बोलता था और इनको नसीहत भी दी थी कि यह राजस्थान का युवा है, जब अपनी पर उतर आएगा तो अच्छे-अच्छे तख्त उखाड़ फेंकेगा।

''मत छेड़ युवाओं को,
लड़ना मुश्किल होगा।
वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास
कि पढ़ना मुश्किल होगा।''

कितना प्रतिशत आपको वोट मिला, आप बताइए तो सही, आंकड़ों के अन्दर आइए तो सही। अब यहां बीच के अन्दर बैठकर आपने यह कह दिया, वह कर दिया। वो माफी मांग ले, ये माफी मांग ले। उसके ऊपर सुर्खियों में रहने के कारण एक दिन फोटो छप जाएगी। पहले शुरुआत के अन्दर आये थे, तब हम भी देखते थे सदन के सितारे कैसे बनते हैं, फोटो अख़बार में कैसे छपती है। मगर आपके जैसे बीच में अन्दर टोका-टोकी हम नहीं करते। विपक्ष ने शिक्षा के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा, शिक्षा के मन्दिर को नहीं बख्शा। आपको अंग्रेजी विद्यालय खोलने थे तो बहुत सारी बिल्डिंगें खाली थीं, आप उनके अन्दर खोलते। हम तो खुश थे। प्रदेश को इस बात की खुशी है। मगर विगत सरकार ने 2019-20 में महात्मा गांधी

अंग्रेजी विद्यालय शुरू किये। माननीय सभापति महोदय, इनकी संख्या थी 3,737 अब सुनिए, आपकी सरकार के समय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिये आप बताइए, आपने कितने भवन बनाये? एक भी भवन नहीं बनाया न? आपने कितने अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की? जीरो की है। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का अलग से कैलेण्डर बनाएंगे। माननीय सभापति महोदय, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। केवल कलर से नाम लिखने से अंग्रेजी विद्यालय नहीं खुलते। रामलाल का श्यामलाल तो मैं भी कर दूंगा। उससे वाह-वाह नहीं मिलती। इसीलिए, इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का नाम बदलकर महात्मा गांधी किया जिससे विद्यार्थी ना तो अंग्रेजी पढ़ पाया, ना हिन्दी पढ़ पाया और प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए हमारी सरकार इसकी समीक्षा कर रही है तो अब कांग्रेस के पेट के अन्दर दर्द हो रहा है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, योजनाओं के बारे में यह बोल नहीं सकते, क्योंकि एक-एक योजना का मैंने आपको आईना दिखाया है। कागजों और आंकड़ों के साथ मैं बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के बड़बोले अध्यक्ष दावा करते हैं, मीडिया के अन्दर जवाब देते हैं। मीडिया के अन्दर दिया एक विडियो मैं देख रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपने कहा था कि यह भजन लाल सरकार उप चुनाव के अन्दर कैसे जाएगी? फिर क्या हुआ उप चुनाव के अन्दर, कैसे मोरया बोल गया आपके? क्या हुआ बताओ, कैसे मोरया बोले? माननीय गोविन्द सिंहजी, गमछा हिलाने से उप चुनाव नहीं जीते जाते। स्टेज के ऊपर गमछा हिला रहे हो, उससे उप चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिये धरातल के ऊपर उतरना पड़ता है, विजन बनाना पड़ता है, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को गले लगाना पड़ता है और योजनाओं को धरातल पर उतारना पड़ता है, नीति बनानी पड़ती है और उस नीति के सामने 140 वर्ष पुरानी पार्टी भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व के सामने, माननीय सभापति महोदय, ताश के पत्तों की तरह बिखर गयी और जमानत भी नहीं बचा पाये। आपके सात में से कितने आये? आप ही बता दो। इसीलिए, बोलने से पहले सोचा करो। आपकी पार्टी की स्थिति को देखकर मुझे कभी-कभी बंसत याद आता है। इनकी पार्टी को देखकर मुझे बंसत याद आता है कि बसंत के अन्दर पेड़ों के अन्दर नये पत्ते तो आ जाते हैं, मगर मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जिस तरह से आपकी पार्टी बिखरी है, अब यह शायद खड़ी होने वाली नहीं है। (समय सूचक समाप्ति घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे भाषण के शुरुआत में इन्होंने 10 मिनट खराब किये थे। इसके प्रदेश अध्यक्ष जी के ...(व्यवधान).. मैं ज्यादा पोथी खोलूंगा आपकी, आप ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो। ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप भी विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मुझे आप डिस्टर्ब करोगे, माननीय सदस्य।..(व्यवधान).. आप औकात के ऊपर मत आओ। ...(व्यवधान)... यह कौनसा शब्द है?

श्री सभापतिः आपका समय हो गया, आप बैठें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह औकात बताने का काम आपका नहीं है। ..(व्यवधान)... इनकी औकात इन्होंने बतायी है, आपकी औकात जनता ने बता दी है। तीन उप चुनाव में जमानतें जब्त हुई है, उस औकात को पहचानो।

श्री सभापतिः विराजें-विराजें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): आपको तो थोड़ी सी देर में ही गुस्सा आ गया। थोड़े से में ही आ गया। अब सुनो। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी बयान देते हैं कि हम बीजेपी और आर.एस.एस. की ए बी सी डी नहीं जानते। इनको पूछें न कि बीजेपी और आर एस एस क्या है? ए बी सी डी जानते नहीं और माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर कमेंट करते हैं कि यह तो राधे-राधे लिखे दुपट्टे पहनकर आ गये। कभी आर.एस.एस. को बिल में डालने की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से, यह तो गनीमत है कि हिन्दुस्तान और राजस्थान में बीजेपी और आर.एस.एस. है जिसकी वजह से आप बैठे हो, नहीं तो विदेशी ताकतें आपको बिल में डाल देती और आपको पता तक नहीं चलता। याद है न जब छोटी सी घटना होती थी तो पूर्व प्रधान मंत्री अमेरिका जाकर हाथ जोड़ते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी दिमागी हालत का चैकअप कराइए।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, यह कोई नाथी का बाड़ा नहीं है। माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बिराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमारे दल का समय अलॉट हो चुका है। हमें बोलने दें।

श्री सभापतिः तीस मिनट बोले हैं। आपके सचेतकजी ने इसमें लिखकर दिया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे दल का समय निर्धारित है उसके अन्दर ही हम बोलेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, प्रथम वक्ता है, प्रस्ताव रखते हैं। इनको पूरा बोलने दें, जितना यह चाहें, बोलने दें।

श्री सभापतिः क्या कह रहे हैं?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रथम वक्ता हैं, प्रस्ताव रखा हैं, इनको पूरा बोलने दें। हमारा समय काट लेना।

jyg/rtm/03.02.25/14.40/2g

श्री सभापतिः श्री कैलाश चन्द।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह नाथी का बाड़ा नहीं है जो चाहे बोल दोगे। क्योंकि मुझे पता है कि समय कम है,

आपके नेता, प्रतिपक्ष को पूरे राजस्थान के अन्दर सड़कें नहीं दिखीं, भरतपुर के अन्दर ही दिखीं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है, भरतपुर के अन्दर जादूगरी करूंगा तो ज्यादा छप जाऊंगा, फिर क्या हुआ पीडब्ल्यूडी की सड़कों का, शिकायत की थी न आपने? यह आप ही का है। आपने ही की थी न, फिर क्या हुआ? जब आपको यह पता नहीं कि ये सड़के किसके राज के अन्दर बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का भी अपमान किया। संविधान संशोधन करने में जिस तरीके से इन्होंने गरिमा को गिराया, कभी तो इनके नेता प्रतिपक्ष और कभी इनकी नेता बोलती हैं महामहिम राष्ट्रपति के बारे में, कभी इनके नेता यहां पर कमेंट करते हैं राज्यपाल के बारे में, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि संविधान को 80 बार संशोधन आप लोगों ने किया, आपने जिस तरीके से भारत की, आप मोदीजी के ऊपर कमेंट करते थे, भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसने बनाया, डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, पीएम जनधन योजना, किसानों को पीएम सम्मान निधि, 500 वर्ष पुराने विवाद को खत्म करके भव्य श्रीराम मन्दिर बनाने का सपना साकार किया, देश के अन्दर 41 वंदे भारत ट्रेनें संचालित की, 81 लाख से अधिक घरों के अन्दर शौचालय, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35-ए हटाकर, एक देश, एक विधान का सपना साकार किया। आप प्रधान मंत्री मोदी जी के लिए बोलते हो कि उन्होंने क्या किया?

अब सुनो। 2014 से पहले देश के अन्दर 74 एयरपोर्ट थे, जिनकी संख्या अब 150 है, देश में मात्र 5 शहरों के अन्दर मेट्रो थी, अब 20 है, देश के अन्दर 384 मेडिकल कॉलेज थे, वर्तमान के अन्दर 700 है, देश के अन्दर मात्र 7 एम्स थे, आज देश के अन्दर 22 एम्स हैं। देश के अन्दर 400 यूनिवर्सिटी थी, आज देश के अन्दर 1100 यूनिवर्सिटी हैं। इसलिए आप यह गाना तो बंद ही कर दीजिये की मोदी जी ने क्या किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस सदन के अन्दर बार-बार जब बातें आयीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी जिक्र हुआ, जिस तरीके से जिन बातों को लेकर हमारी सरकार काम करना चाहती है, हमारी सरकार की दूरगामी सोच है, उस सोच के लिये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि आने वाले समय के अन्दर जिस तरीके की योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने बनायी है, उन योजनाओं और उन योजनाओं से प्रभावित गांव, गरीब, किसान की प्रतिभाएं आने वाले समय के अन्दर राजस्थान, हिन्दुस्तान की उन कुर्सियों पर जाकर बैठेंगी जहां पर विकास की रूपरेखा तय होती है, जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर हर व्यक्ति बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को गौरवांवित महसूस करता है। इसीलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय भजन लाल जी की कार्य प्रणाली के लिए जो आने वाले समय के लिए इस प्रदेश के लिए पूरी तरीके से मजबूती के साथ में अपनी कैबिनेट को साथ लेकर साढ़े आठ करोड़ लोगों के विश्वास के साथ में खड़े हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा,

'कुछ ख्वाब अभी अधूरे हैं, कुछ अरमान अभी बाकी हैं,
राहों में हैं मुश्किलें मगर, कदमों में जान अभी बाकी है।
हौसलों की उड़ान कभी कम नहीं होगी,
सपनों का आसमान अभी बाकी है,
थककर कैसे बैठ जाऊं मैं,
मेरे राजस्थान के विकास की कहानी अभी लिखना बाकी है।'

माननीय सभापति महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम साहब।

श्री सभापतिः श्री गुरवीर सिंह।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख माननीय, महामहिम राज्यपाल जी ने संविधान के अधिकारों का निर्वहन करते हुए राजस्थान की सरकार का विजन, राजस्थान सरकार का रोडमैप इस पवित्र सदन में रखा, पूरे राजस्थान के आठ करोड़ लोगों ने आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्माजी ने इस एक साल के कार्यकाल को जनता के समक्ष रखा और जो निर्णायक फैसले इस एक साल में हुए उनका पूरा ब्यौरा उस पूरे अभिभाषण में रखा गया। पहली बार राजस्थान के इस लोकतंत्र के मन्दिर में प्रदेश के अन्न का कटोरा कहे जाने वाले श्रीगंगानगर से चुनकर आने का हमें मौका मिला और पहली बार सदन के इन उतार-चढ़ावों को, सदन की इन गरिमाओं को, सदन की इन परम्पराओं को हम देखते रहे और पहली बार हमें अनुभव करने का मौका मिला कि जनता की आवाज को कैसे सरकार तक पहुंचाया जाता है, सरकार के माध्यम से कैसे धरातल तक योजनाओं को लेकर जाया जाता है।

इस अभिभाषण के 44 पृष्ठों के 168 पैरों को जब हम गम्भीरता से पढ़ते हैं और मुझे खुशी है कि पहले ही साल में राजस्थान की सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक राजस्थान की कोई सरकार नहीं कर पायी। यह मुख्य मंत्रीजी की लगन और मेहनत थी, यह जनता का उन पर विश्वास था कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी लेकर चुनावी मैदान में उतरी वह पहले ही साल में 53 प्रतिशत बिन्दुओं पर राजस्थान की सरकार ने उपलब्धि हासिल की है और 45 बिन्दुओं पर राजस्थान सरकार ने अमल किया है। यह जनता के लिए बधाई है, राजस्थान की जनता बधाई की पात्र है कि उसने ऐसी सरकार को चुना जिसने उनकी मांगों को उनकी दिशा देते हुए पहले ही साल में पूरा किया।

मैं सरकार के साथ पहले साल के सफल कार्यकाल का, हमारे बजट में जो संकल्प मुख्य मंत्रीजी ने लिया, जो हमारे परिवर्तित बजट 2024-25 था, राजस्थान की सरकार ने सर्वजन हिताय को अपना संकल्प मानते हुए, जो दस संकल्प हमारे बीच में पढ़े, उनको सरकार ने

पूरा वचनबद्ध रहते हुए पूरा करने का प्रयास किया। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन बनाने का पहला लक्ष्य इस सदन के अन्दर रखा। जो दूसरा लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया वो बुनियादी सुविधाओं, पानी-बिजली और सड़क के विकास का था और जो तीसरा संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, तीसरा संकल्प हमारी सरकार ने लिया है सुनियोजित विकास के साथ-साथ शहरी-ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास का, चौथा हमारा एग्रीकल्चर, जो देश का 70 प्रतिशत आज भी लोग गांवों में रहने वाले हैं, उनके लिए सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण, आज देश और दुनिया के सबसे ज्वलंत हमारी जरूरतें हैं इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के नाम पर हमारा पांचवां संकल्प और छठे संकल्प के रूप में राजस्थान की विरासत भी और विकास की सोच के साथ धरोहर संरक्षण का संकल्प लिया। सातवें संकल्प के रूप में सतत् विकास के साथ हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण का लिया। हमारी सरकार का आठवां संकल्प संसाधन विकास एवं सबके स्वास्थ्य की जो रचना हमारी सरकार ने की और सबसे महत्वपूर्ण हमारी सोशल सिक्योरिटी का हमारा नवां संकल्प है। दसवां संकल्प गुड गवर्नेंस, परफोर्म, रिफोर्म और ट्रांसफोर्म के साथ जो एक साल राजस्थान की सरकार का कार्यकाल है वह अपने आप में एक अनोखा कार्यकाल है। पहले भी राजस्थान में बहुत-सी सरकारें आयीं, देश ने भी बहुत-सी सरकारों को देखा, पर हमने राजस्थान में पहले भी इंवेस्टमेंट समिट देखे हैं पर जो इंवेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट हुआ वो पहले कार्यकाल में सफलतम इंवेस्टमेंट समिट हमारे राजस्थान में साबित हुआ, जिस समिट ने पूरी दुनिया में राजस्थान की साख छोड़ी, देश भर के लोगों ने देखा, पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट आकर उसका गवाह बने और 350 बिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था का सपना साकार होते हुए पूरे देश की जनता ने देखा।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच का जिनके माध्यम से, जिन पर विश्वास व्यक्त करते हुए दुनिया के कोने-कोने से आये, 32 कंट्रीज से हमारे यहां पधारे इंवेस्टर्स, 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू करके राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर ला दिया और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से हमारी सरकार इस राजस्थान के विकास को और गति देगी और हमारी जो पॉलिसीज मुख्य मंत्रीजी लेकर आये, जो आज कोई भी राजस्थान की सरकार हो, देश-दुनिया की सरकार हो, उसकी नीतियां बताती हैं कि उस देश का भविष्य कैसा होगा, उस प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो नीतियां लीं, वो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, चाहे राजस्थान की एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी हो, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट की पॉलिसी हो, राजस्थान एमएसएमई की पॉलिसी हो, राजस्थान एकीकृत कलस्टर विकास की योजना हो, ये सभी वो नीतियां हैं जो राजस्थान के विकास को नये पहिये देगी।

MLS/RTM/03.02.2025/14:50/2h

मुझे खुशी है, जो हमारा यूनियन बजट पेश हुआ, प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के मिशन के साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ द जीडीपी है, जो कि 17 परसेंट है, उसे 25 परसेंट तक लेकर जाने का सरकार ने मिशन लिया है। आज इस चीज का सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को होगा तो वह राजस्थान प्रदेश को होगा, जिसने इसके महत्त्व को समझते हुए सबसे पहले इस काम को शुरू किया है।

पारदर्शी शासन तब दिया जा सकता है जब नीति निर्धारण हो। हमने नीति तय कर ली है, रोडमैप तय कर लिया है। सरकार तैयार है। दुनिया पूरे राजस्थान को आशा भरी निगाहों से देख रही है। आने वाला सुनहरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आयेगी। मैं मुख्य मंत्री जी को, राजस्थान प्रदेश के हर शख्स को, इस आठ करोड़ की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा। इस सदन में बहुत-सी सरकारें आईं, बहुत-सी गईं, बहुत-से राजनीतिक दलों को यहां सत्ता में रहने का मौका मिला, पर जो हमारे पानी के स्रोत हैं, उनकी चिन्ता किसी ने नहीं की। राजस्थान के कोने-कोने में एक ही कमी महसूस होती थी। भौगोलिक स्थिति देखी जाये तो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है।

हमारे पास प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की डबल इंजन की बहुत अच्छी सरकार है। चाहे दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे हो, चाहे अमृतसर-जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हो, चाहे भारत माला प्रोजेक्ट हो, हमारे पास आज न सड़कों की कमी है, न बिजली की कमी है, न जगह की कमी है। हमारे पास कमी थी तो पानी की कमी थी। उस पर चौतरफा अगर किसी ने पहले दिन से काम शुरू किया है तो माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने किया है। आज राम जल सेतु के लिए, चाहे कोई पक्ष में हो या विपक्ष में, आप सब इसके गवाह हैं कि पिछली सरकार ने इसे लटकाया और भटकाया, लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं आने दिया। लगातार उनके बजट भाषणों में, लगातार 5 साल में उनके जो अभिभाषण पेश किये गये, ईआरसीपी के मुद्दे को लटकाते रहे। आज राम जल सेतु के नाम का जो हमें वरदान मिला है, 17 जिलों में उसका सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, 4 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और राजस्थान की 3 करोड़ आबादी को, एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी को आज पीने के लिए पानी मिलेगा। यह बहुत बड़ी योजना है।

आज चाहे यमुना जल समझौता हो, हमारे पड़ोसी क्षेत्र शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता अपने आप में बहुत बड़ी देन है। मैं अगर पानी की बात करूं तो पोंग डैम और भाखड़ा डैम के नाम सुने होंगे, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन्हें आज तक कोई नहीं समझ सका। मुझे खुशी है और मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी सिंचाई तंत्र से नहीं, भरतपुर से आते हैं। हमारे गंगानगर और पंजाब-हरियाणा के सिंचाई तंत्र से आने

वाले किसानों की समस्याएं और हैं और बाकी की ट्यूबवैल से खेती करने वालों की समस्याएं और हैं। पहली बार किसी ने इस बात को समझा है कि पोंग डैम और भाखड़ा डैम का लेवल ऊपर करके राजस्थान का कोटा पूरा किया जा सकता है। मुझे खुशी हुई जब मुख्य मंत्री जी ने इस पर चिन्ता जाहिर की और इस मुद्दे पर यूनियन जल शक्ति मंत्री के साथ जाकर बैठक की। आने वाले दिनों में हमारे परिणाम बताएंगे।

आज यूनियन बजट में, पिछली बार जब जनता जल मिशन के साथ राजस्थान की सरकार में जो पैसा आया, पूरे देश में प्रधान मंत्री जी ने घर-घर जल पहुंचाने का जो मिशन लिया, उसका फायदा जो राजस्थान की सरकार ले सकती थी, उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, क्या इन्हें रुकवटें थीं, ये बता सकते हैं, पर जो फायदा हम ले सकते थे, राजस्थान ने नहीं लिया। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधान मंत्री जी का, जिन्होंने उस योजना को 2028 तक एक्सटैंड किया। हमारी सरकार ने पहले ही साल में 6091 करोड़ खर्च करके 11 लाख 17 हजार परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत लाभ पहुंचाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज प्रधान मंत्री जी ने यूनियन बजट में ज्ञान का एक जो 3-4 अक्षरों का मिशन लिया है, जिसमें गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो या महिला हो, इन चारों की तरफ पूरी राजस्थान की सरकार हो या हमारी केन्द्र की सरकार हो, इनका ध्यान, इनका डायरेक्शन इन चारों कैटेगरीज के लिए किया है, ताकि अन्नदाता हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, उन्हें हम सम्बल प्रदान कर सकें, उन्हें प्लैटफॉर्म दे सकें, इस देश की तरक्की में सहभागी बना सकें। मुझे खुशी है कि इस सदन में हमें मौका मिला, मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं, जहां मेरे दादा सरदार गुरजंट सिंह जी हों, कई बार उन्हें इस सदन में आने का मौका मिला, किसानों की बात रखने का मौका मिला। हम किसानों के मुद्दों को लेकर इस सदन में आये हैं।

प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा। जो किसान कर्ज के तले दब रहा था, जो सूदखोरों के नीचे दब रहा था, आज 3 लाख का क्रेडिट कार्ड, जो किसी समय में स्व. प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, आज केन्द्र की सरकार ने उसकी सीमा 5 लाख तक बढ़ाकर देश के किसानों का दिल जीता है। देश का किसान इस बात के लिए खुश है। आज जहां मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधि की बात करूं, प्रधान मंत्री जी कई वर्षों से लगातार देश के किसानों को 6 हजार रुपये बिना किसी तड़क-भड़क के, बिना किसी ताल-तड़क के जो उनके खातों में बिना मांगे, बिना किसी के आगे झोली फैलाये आते थे, उसमें हमारी सरकार ने, पहले ही साल से हमारे मुख्य मंत्री जी ने उसे चरणबद्ध तरीके से दुगना करने का काम किया है। पहले ही साल में हमने 2 हजार रुपये की वृद्धि करके 70 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बहुत बार विपक्षी पार्टियां सवालिया निशान उठाती हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या मिला। मैंने पांच साल के कांग्रेस की सरकार के एक-एक शब्द को पढ़ा है। हर अभिभाषण में आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की

उपलब्धियों को गिनाया है। मुझे खुशी है, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 करोड़ 56 लाख पॉलिसीज का लाभ देकर 2700 करोड़ रुपया किसानों में वितरित किया है। आज किसान को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जहां हमारा किसान अन्नदाता है, मुझे खुशी है, अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता का जो नाम मुख्य मंत्री जी ने दिया है, किसान अपने घर में बैठा, अपने खेत में बैठा, किसानी-खेती के अलावा एक और आमदनी का जरिया बना सकेगा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।

हमारे महामहिम जी के अभिभाषण में पैरा 60 में जहां 30 लाख किसानों को 16 हजार 781 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी घोषणा, जो हमारे मैनिफेस्टो में थी और जो पहले ही साल में लागू करके मुख्य मंत्री जी ने किसानों का दिल जीता है, वह है गेहूं की एमएसपी पर जो बोनस दिया गया है, वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश की सबसे महंगी अगर कोई खरीद कर रहा है, सबसे ज्यादा गेहूं पर पैसे किसी को मिल रहे हैं तो वह राजस्थान का किसान है, जिसके लिए बोनस के साथ खरीद की जा रही है। हमारी सरकार ने मात्र एक साल में 1 लाख 10 हजार कृषि कनेक्शंस देकर किसानों को लाभान्वित किया है। आज जो कृषि कल्याण सेस है, यह जादूगरी का कल्याण वर्ड है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से पिछली सरकार के पिछले मुख्य मंत्री जी ने जो किसानों की जेब पर डाका डाला, उसका नाम रखा गया कल्याण सेस।

माननीय, जो भी खरीद बाजार में बोली पर होगी, जो भी खरीद बोली पर बिकेगी, उसका जो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वह किसान की जेब से जायेगा। जो पिछले मुख्य मंत्री जी ने 2 परसेंट की घोषणा की, मुझे याद है, कांग्रेस के विधायकों ने उसका विरोध किया और फिर वह 1 परसेंट की गयी। आज हमारी सरकार ने 50 परसेंट तक उस पर कटौती की है। जहां फल-सब्जी पर 2 परसेंट की इन्होंने लागू की, आज हमारी सरकार 50 परसेंट की कटौती करके उसे 1 परसेंट पर लेकर आयी है। जहां कृषि जिंसों पर 1 परसेंट का इन्होंने टैक्स लगाया, उसे हम 0.5 पर लेकर आये हैं और गुड़ और चीनी को 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

माननीय, ये कृषि उपज मण्डी समितियां, जिनके ऊपर अभी पिछले दिनों 31 तारीख को तीन कृषि बिलों को इन्होंने रिपील करने का इसी सदन में प्रस्ताव पास किया था, जो केन्द्र सरकार और गवर्नर से वापस होकर आया, उसकी सच्चाई भी मैं सदन को बताना चाहूंगा। जब किसानों के लिए आपको बहुमत था, इसी सदन में आपकी संख्या ज्यादा थी और आपने ऐसा बिल पास किया, अगर आपने उस टाइम मॉडल एपीएमसी एक्ट को पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से किसान को गुमराह कर रहे हैं। मॉडल एपीएमसी एक्ट के लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। उसे भी मण्डी शुल्क की तय सीमा से बाहर रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें कमी क्या थी, उसमें

कमी थी कि कम्पनियां आती थीं और भोला-भाला किसान उनके ट्रैप में आ जाता था। देश में सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कहीं हुई तो लुधियाना में हुई।

mkd/rtm/03.02.2025/15:00/2j

तत्कालीन देश के प्रधान मंत्री स्व. मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री ने 300 एकड़ में जाकर कांट्रेक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया। ये ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को और गुमराह कर रहे हैं किसानों को कि हम आपका कृषि कल्याण ऐसे-ऐसे करेंगे। जो कमियां थीं, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट नम्बर तीस के तीसरे पैरे में, towards 'Indian single market' में, जो प्रावधान किये थे। एक नोडल ऑफिसर अधिकारी लगाया गया था, जो तालमेल बिठाना का काम करता पर आज मुझे खुशी है कि इनकी वह मंशा पूरी नहीं हुई। आज वे जिस तरीके से चाहते थे, वह ये नहीं कर पाये और किसानों ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। किसान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड अगर कुछ है तो हमारा पशुपालन है। किसान पशु को अपने परिवार के बच्चों की तरह पालता है। मुख्य मंत्री जी, आपने समझते हुए मुख्य मंत्री मंगला पशु योजना के तहत 400 करोड़ का प्रावधान करके उन पशुपालकों को भी राहत प्रदान की है। राजस्थान की सरकार ने पैरा 62 में राजस्थान सहकारी गोपालक क्रेडिट कार्ड में 24 हजार किसानों को पहले ही साल में एक लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया है, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। पैरा 76 में प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं का, गऊ का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है, लगन है, लोगों की सेवा है, आज गोशालाओं को जीवनदान देने का काम आपने किया है, पहले ही साल में 700 करोड़ का अनुदान 10 प्रतिशत की वृद्धि से देकर के आपने गोपालकों का भी दिल जीता है, मैं इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय, अगर किसानों की डिग्गियों की बात करें तो मैंने इनके सारे पिछले चिट्ठे खोलकर देखे हैं। पहले ही साल में, आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3,266 डिग्गियां दी हैं, 18,813 फार्म पोंड दिये हैं, 12,400 किलोमीटर सिंचाई पाइपपाइन और 17,000 किलोमीटर तारबन्दी दी है, 33 लाख 88 हजार महिला कृषकों को निःशुल्क बीज वितरित करके 70 करोड़ रुपये खर्च किया है, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारी आईजीएनपी नहर के लिए 2816 करोड़ रुपये का प्रावधान, यमुना के पानी के लिए एमओयू, चम्बल की लाइनिंग के लिए ढाई सौ करोड़ का काम और गंगानगर, हनुमानगढ़ में पहले ही साल में किसानों के पक्के खाले के लिए 108 करोड़ रुपया दिया गया है और मैं 2021 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा नम्बर 130, कांग्रेस की सरकार में इन्होंने तीसरे अभिभाषण में माना है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में तीन सालों में इन्होंने मात्र 40 करोड़ के खाले दिये हैं। हमारी सरकार ने 108 करोड़ के दिये है। यह आपकी मंशा और आपका प्रूफ है, जो आपके अभिभाषण में पेश किया है।

मैं गत सरकार के एक और असत्य को सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2021 के

आपके अभिभाषण के पैरा 128 में स्काडा सिस्टम लगाने का आपने काम किया, एक पैसा आज तक नहीं लग पाया, चाहे फिरोजपुर फीडर हो, गाजर मंडी हो और सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल, डीजल हो, गंगानगर, हनुमानगढ़ में देश का सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल था, आज उसकी राहत भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने दी है। नौकरियों के मामले में आंकड़े मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने दिये, मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभिभाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बाहर जाकर प्रेस कांफ्रेस की। प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने मांग की है कि मुख्य मंत्री जी ने एसआईटी का गठन करके, जो आज तक उन्होंने 100 एफआईआर दर्ज की हैं, 260 अरेस्ट हुए, इनके पूर्व मुख्य मंत्री सन्तुष्ट नहीं हैं, वे मछलियां पकड़वाना चाहते हैं, मछलियां और मैं सोचता हूं, जो ढाई साल तक उप मुख्य मंत्री रहे, जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनकी राय लेनी चाहिए, एसओजी को उनके साथ बिठाना चाहिए, हो सकता है मछलियों की जगह मगरमच्छ मिल जाये, कई सीटें खाली हो जायें, इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: टाइम हो गया, आपका। अगली बार।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): मेरे बहुत से बिन्दु माननीय अभी पड़े हैं। अगर मेरा टाइम हो गया है तो लास्ट बात रखना चाहता हूं। हम सदन में नये हैं। हमने इसी सदन में इन दर्शक दीर्घाओं में बैठकर भैंरोसिंह जी शेखावत, माननीय वसुन्धरा राजे जी सिंधिया, हमारे गुलाब चन्द जी कटारिया, राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, प्रद्युम्न सिंह जी और बड़े-बड़े नाम रामसिंह जी विश्नोई जैसे को सुना है, पर यहां मर्यादाओं की बात होती थी, यहां परम्पराओं की बात होती थी। जिस तरीके से राज्यपाल जी के अभिभाषण को टोका गया, वह असंवैधानिक, आपने मर्यादाओं को तार-तार किया है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): कांस्टीट्यूशन का पैरा नम्बर 159 में जो ओथ दी हुई, आप माननीय उसको पढिये, इसकी ओथ में लिखा गया है - "the office of the Governor (or discharge the functions of the Governor) will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution.", उसमें अधिकार है उनको, आप उनकी पावर्स को आर्टिकल 163 और 159 को दोनों को जब जोड़कर पढ़ोगे तो माननीय आपको पता चलेगा। राज्यपाल जी गंगानगर गये, राज्यपाल जी बाड़मेर गये, राज्यपाल जी बीकानेर गये तो कोई आपत्ति नहीं आई और सीकर जाते ही कौन-सी वीणा के तार छेड़ दिये जो आपको बयान देने पड़े। यह हमारी समझ से बाहर है। इतना ही कहते हुए मैं सदन का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वाह साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही तसल्ली से हमारे दो विद्वान एमएलए साथियों को सुना, अच्छा लगा। बड़ी तैयारी के साथ

आये और ज्यादा मुद्दा से नहीं भटके, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सदन ने भी शान्ति से उनको सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप तसल्ली से सुनेंगे। मैं महामहिम जी ने जो अभिभाषण, भाई जीनगर साहब, आप बैठ जाओ। मुख्य मंत्री जी यहीं खूब मिलते हैं। आज ही तो मुश्किल से आये हैं, आज ही तो सुनने का मौका मिला है और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। इनसे तय करवा लो, मुख्य मंत्री जी को बुलवाना है कि नहीं 7 तारीख को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम से सरकार ने कैबिनेट में अभिभाषण तैयार करवाकर, उनकी मुहर लगवाकर और अपनी पीठ थपथपवाने का काम किया है। मैं जो उसी टाइम लिख रहा था, वही पन्ने हैं, कोई दूसरे नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी विराजमान थे। आपने ईआरसीपी से शुरू किया और केपीसी पर आये, रामसेतु जल पर आये, यमुना जल की बातें कराईं, आपने जेजेएम घोटाले की बात भी कराई, दिन में बिजली की बात भी कराई, पेपर लीक की भी बात कराई, भर्तियों की बात भी आपने कराई। मुख्य मंत्री आयुष्मान की बात भी आपने कराई, आपने यूरिया, डीएपी और किसान की बात भी छोटी-छोटी की एकाध लाइन में, गोशालाओं की बात भी की। भरतपुर और बीकानेर में एक महान काम आपने किया है, विकास प्राधिकरण बनाने की बात, वह भी आपने की और अन्नपूर्णा रसोई और शिक्षा की नैतिक शिक्षा और बालिका शिक्षा और ये करते-करते 34 महाविद्यालय खोलने की बातें भी कराईं, लू-तापमान की बातें भी कीं, 730 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात भी की, मरम्मत के लिए भी बात की, कानून व्यवस्था की बात की, रिफाइनरी की भी बात की, ये सारी बातें आपने की हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाया, जिन मुद्दों की बात की, मैं उन्हीं मुद्दों पर ही रहूंगा, उनसे इतर एक भी मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोग ग्रहण करें नहीं करें, गम्भीरता से लें नहीं लें, लेकिन इन चीजों का जवाब प्रदेश की जनता मांगती है कि भाई यह हो क्या रहा है। 12 महीने से जिस प्रकार से केवल बातें ही बातें हो रही हैं, होर्डिंग लगे पड़े हैं, मुख्य मंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, धन्यवाद यात्राएं करा रहे हैं, आभार करा रहे हैं, तो यह है क्या चीज, हुआ क्या है?

मैं ईआरसीपी पर पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी विराजमान हैं, अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शुरूआत हुई थी तो 3921 एमसीएम पेयजल की बात हुई थी, जो वसुन्धरा राजे जी ने पूर्व मुख्य मंत्री जी ने यहां से जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी बात हुई थी। हमारी सरकार यहां कांग्रेस की थी, इसलिए उनकी सरकार चली गई थी, वह बात आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन 2022 में रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति की 20वीं बैठक में आपने 1775 एमसीएम पानी की जो इनकी नोटशीट चली और जो बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हुआ, उससे हमें पता लगता है। उसके बावजूद भी एक रुपये का काम नहीं हुआ। केन्द्र ने उल्टे हमने जब हमारी सरकार ने काम चालू किये....

Bhs/Rtm/03.02.25/15.10/2k

और 10 हजार करोड़ रुपये, 12 हजार करोड़ रुपये की सैंक्शन जारी की अपने स्टेट फंड से तो चिट्ठी दी यहां के जल संसाधन मंत्री जी ने कि आप यह काम नहीं करोगे, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्थिति है। चलिये, कोई बात नहीं, मुख्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से दोस्ताना ताल्लुक़ात बढ़ाये, केन्द्र से भी डबल इंजन की सरकार थी, आप गये, आपने कोई एम.ओ.यू. किया बताते हैं, कोई लिखा-पढ़ी की, जबानी जमा-खर्च किया। आप बार-बार कहते हैं, हम गये। प्रधान मंत्री जी का आभार और हमने वहां पर एक समझौता किया।

मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वह समझौता क्या है? जब वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री थी तब जो पानी हमको 3,921 एमसीएम मिलना था उसके ऊपर वहां मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को एतराज था, वहां की सरकार को एतराज था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे आगे की कार्यवाही के लिए स्टे ले रखा था तो आपके एक एम.ओ.यू. साइन होते ही आपके साथ फोटो क्लिक करते ही मुख्य मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें एतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं तो वह समझौता क्या है मुख्य मंत्री जी? आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

फिर आपने पी.के.सी. बनाई साहब, बना लो आपकी डबल इंजन की सरकार है। आपने उसके बाद में नाम चैंज कर दिया। आप बताओ तो सही कि आपने और केन्द्र सरकार ने एक धेला दिया क्या? एक रुपया दिया क्या? आपने एक पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया दिसम्बर से पहले तो तैयार ही हो गया, अक्टूबर, 2024 में तो तैयार ही हो गया। दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकोप्टर से घूम कर आये थे। अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस के सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ई.आर.सी.पी. का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही।

आज देश के प्रधान मंत्री के बयान सुनिये। प्रदेश की जनता पूछना चाहती है मुख्य मंत्री जी, आप विराजमान हैं इसलिये आपसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, जो वसुन्धरा जी ने ई.आर.सी.पी. का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वह राष्ट्रीय परियोजना कहां है? दूसरा बजट केन्द्र का आ गया और आपका दूसरा आने वाला है। आप बताओ तो सही। हमने ...(व्यवधान)... भाई, सुनो तो सुन लो बैठ जाऊं नहीं तो। अपनी दोस्ती जगजाहिर है काहे को बीच में बोल रहे हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट फंड से पैसा देकर के जो 26 बांध थे उनमें 53 बांध जोड़ने का काम किया हमने और 12 हजार करोड़ रुपये देकर के काम चालू करा दिया और आपकी डबल इंजन की सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। मैं देख रहा था, मुख्य मंत्री जी इन्नोसेंट हैं। भोले व्यक्ति हैं। इनके सलाहकार जरूर थोड़े बहुत गड़बड़ हैं वो दूसरों से मिले हुए हैं कहीं न कहीं। आप बताइये कल बजट आ रहा था तो इनको बैठा दिया एक पन्ना और

पैन लेकर के और डेढ़-दो घंटे तक बैठे रहे, 'क' ही नहीं लिख पाये क्योंकि उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं थी। अब इनको वह फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी। मीडिया में इतना ज़ाब्ता है, इनका मीडिया तो मेरे पीछे लगा रहता है, डोटासरा क्या बोला, इस मंत्री से क्या कहलवाना है, इस एम.एल.ए. से क्या कहलवाना है। मैं तो आप कहो तो कम बोल लूंगा। मैं कोई अपशब्द बोलूं तो बोलना न आप।

आप कम से कम ऐसे लोगों को तो तैयार रखो। मैंने कहा कि आई.ए.एस. की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, आपने एक ही दिन में ठोक दी, जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण छपना था उस दिन तो आई.ए.एस. की और आर.पी.एस. की लिस्ट छपी है और केन्द्र का अभिभाषण और आपका अभिभाषण एक दिन आ गया लेकिन अभिभाषण केन्द्र का छपा आपका छपा ही नहीं तो यह जो मीडिया वाले हैं न जो सलाहकार हैं मेरे पीछे नहीं लगा करके आप अपनी व्यवस्थाओं के सुधार के लिए लगाओ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह अभिभाषण की बहस नहीं है। मीडिया किसके पीछे लगा हुआ है यह अभिभाषण की बहस नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई बात नहीं। चैंज कर देते हैं यमुना जल पर आ जाते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप यमुना जल के लिए बहुत वाहवाही लूट रहे हैं और पता नहीं कितने होर्डिंग आपके लगे, लगे तो सरकारी खर्चे पर हैं, व्यक्तियों ने एक ने ही नहीं लगवाया आप गिनवा लेना। मेरी बात मान लेना। आपने कहा कि यमुना जल के अन्दर, आप बताइये 1994 में समझौता हुआ और 1190 एमसीएम पानी हमको मिलना था, 3100 क्युसेक्स की डी.पी.आर. हमने बना करके 2021 में भेजी। आपकी केन्द्र की सरकार ने कुछ किया नहीं और 17 फरवरी, 2024 को आप आनन-फानन में एक समझौता करते हैं। चार महीने के अन्दर डी.पी.आर. की बात करते हैं और जो समझौता आपने आज तक आउट नहीं किया लेकिन मेरे पास कॉपी है उसमें लिखा हुआ है कि 577 एमसीएम पानी मिलेगा, 2400 क्युसेक्स पानी पहले हरियाणा लेगा। पहले हरियाणा 2400 क्युसेक्स पानी लेगा उसके बाद में 4 महीने केवल जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर में चार महीने में अगर फ्लड छलकता है ऊपर से यह पूरा लेने के बाद में हरियाणा में तो उसके बाद चार महीने में पाइपलाइन से आप पानी ले जा सकते हो और आप होर्डिंग लगा रहे हो, बड़े-बड़े अलग-अलग जॉकेट पहन करके कि साहब, भागीरथ बन करके आये, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको।

आज 12 महीने से ज्यादा हो गये मुख्य मंत्री जी, आपकी संयुक्त टास्क फोर्स भी नहीं बनी, आपकी डी.पी.आर. नहीं बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य मंत्री सदन में यह कह दे, दो सौ सदस्यों के सदन में यह कह दे कि चार महीने में डी.पी.आर. बनेगी और 14 महीनों में नहीं बने तो शर्म आनी चाहिये उस सरकार को। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

फिर आपने कहा कि जल जीवन मिशन में बहुत घोटाले हुए। हमने भी सोचा पता नहीं, घोटाले हुए कि नहीं हुए, ये कह रहे हैं राज्यपाल महोदय से प्रथम अभिभाषण में पढ़वा रहे हैं

तो पकड़ेंगे। मगरमच्छों को जेलों में डालेंगे लेकिन क्या हुआ साहब, एक भी मंत्री पकड़ा, एक भी एम.एल.ए. पकड़ा, एक भी आई.ए.एस. अधिकारी पकड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने, जिन छोटे-छोटे कारिन्दों को पकड़ा न, उन सबको जमानत दे दी और आप कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में हम यह वाहवाही कर देंगे।

मैं आपको नमूना बता रहा हूं आपने बजट में 15 हजार करोड़ से 25 लाख ग्रामीण घरों में नल पहुंचाने की बात की थी और आपने ट्विट किया 17.12.2024 को मुख्य मंत्री जी, आपने कहा कि 5,257 करोड़ में 10.22 लाख घरों में पेयजल पहुंचेगा। ठीक है, फिर आपने राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से क्या कहलवाया? 11 लाख 17 हजार परिवारों को 6,091 करोड़, यह 17 तारीख को तो आपका टाइम पूरा हुआ 12 महीने का और आपने तीन आंकड़े बदल दिये, एक 12 महीने की प्रगति में अलग, राज्यपाल के अलग और आपके अलग तो कम से कम एक बार पढ़वा लिया करो। आपके पास इतने अधिकारी हैं क्या करते हैं ठाले बैठे? बताओ आप। आप पढ़वा कर देख लो कि इसको मैच कर लेना कहीं डोटासरा पकड़ नहीं ले इस बात को तो यह बात आपको देख लेनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा ये सब चीजें तो कम से कम दुरुस्त होनी चाहिये और लॉ एंड ऑर्डर कानून-व्यवस्था, अपराध कम हो, यह सारी की सारी चीजें होंगी तभी तो गुड गवर्नेंस की बात कहोगे वरना तो ट्विट करने से गुड गवर्नेंस आता है क्या? तब तो ये ट्विट करने वाले ही ला देते तो आपने देखा शिक्षा विभाग में एक लाख से ज्यादा के पद खाली हैं नहीं भर पाये। आपने वो ही पुरानी परिपाटी जो वसुन्धरा जी के समय बीस हजार स्कूलें बन्द की थी, 450 फिर करा दी। मैं एक-दो नमूने बता रहा हूं आपके संज्ञान के लिए कराओ या नहीं कराओ इनका प्रमोशन करके डिप्टी सी.एम. बना दो मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन एक नमूना बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की 3737 स्कूल, सात लाख से ज्यादा बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं गरीब का बच्चा है, मंत्री जी के तकलीफ हो रही है।

आप बताओ 12 महीने हो गये आपने उस इंग्लिश मीडियम की स्कूल में एक भी टीचर दिया क्या, एक भी कमरा दिया क्या? ...(व्यवधान)... बैठ जाओ। नमूना बता रहा हूं। मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं। हो सके तो या तो इनका प्रमोशन कर देंगे। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार मुख्य मंत्री जी आपके शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पद स्वीकृत नहीं किये और बोर्ड टांग दिये तो सड़क पर बोर्ड टंगते हैं, स्कूलों में ही तो टंगेंगे, भवन बने हुए हैं तभी तो टंगेंगे। चाहे आपकी सरकारें रही हो, हमारी सरकारें रही हों, बने हैं। अपने बीस हजार बन्द किये तो उनको वापस खोल कर इंग्लिश मीडियम बना दिया तो हमने कोई अन्याय कर दिया क्या? सवा सात लाख बच्चे ऐसे ही आ गये क्या? आपका विधान सभा क्षेत्र है सांगानेर उसमें जाकर के देखिये, विद्याधर नगर डिप्टी सी.एम. का विधान सभा क्षेत्र है उसमें जाकर के देख लीजिये, कितने भामाशाहों ने पैसे दिये, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने, आपके शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया?

...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह बलजीत आ रहा है, उसका ध्यान रखो। मैं कहना चाहता हूं कि 45,300 हजार पद स्वीकृत किये हमने, 28,018 कार्यरत हैं, अलग से कैडर बनाया।

Kas/rtm/03.02.2025/15.20/2l

10 हजार इंग्लिश मीडियम के संविदा पर हमने भर्ती की, परीक्षा लेकर थर्ड ग्रेड के लगाये थे, आप देखिए बीजेपी सरकार ने 8 माह बाद 28.8.2024 को तो परीक्षा ली, आप दिसम्बर में आये और अगस्त में तो इंग्लिश मीडियम में टीचर लगाने के लिये परीक्षा ले रहे हैं, 23.12.2.24 को उनका परिणाम जारी किया, जबकि वह 24-48 में जारी हो जाना चाहिये था। मुख्य मंत्री जी, आज की तारीख तक एक टीचर नहीं लगा और समीक्षा की समिति और बना दी और उस डिप्टी सीएम साहब को बना दिया, जिनको पहले आपने हटाया था। जिलों की समिति बनाई, उसमें हटा दिया और मैं लिख कर दे रहा हूं इस डिप्टी सीएम को आपको पुन: हटाना पड़ेगा। उनकी दूदू विधान सभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल हैं, उनको गांव वाले बंद नहीं करने देंगे, वे साइन करने से मना कर देंगे, जैसे किरोड़ी जी की छुट्टी के लिये सब अधिकारियों ने साइन करने से मना कर दिया और आपके शिखर साहब को साइन करने पड़े कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। लोगों को अचंभा हुआ, मुझे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि सारे काम ही पर्ची से हो रहे हैं, उनके पास पर्ची आई होगी तो उन्होंने कह दिया मुझे लिखित में निर्देश प्राप्त हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि आखिर यह हो क्या हो रहा है, एक मंत्रिमंडल का सदस्य अगर कोई सरकार के खिलाफ की बात करता है तो वह संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, वह उस सरकार का फैसला होता है। आपका मंत्री नहीं आ रहा, कह कर जा रहा है कि सात करोड़ की बजरी प्रतिदिन निकाली जा रही है, लोग मिले हुए हैं। वह मिले हुए लोग कौन हैं? वह कह रहे हैं कि इंटेलीजेंसी फैल है। मुख्य मंत्री जी का गृह विभाग मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। यह हो क्या रहा है साहब? यह गुड गवर्नेंस की निशानी मुझे तो नहीं लगती है।

विद्या संबल योजना कालेजों में, आप बताइए आपने 2500 शिक्षक हटा दिये। लगाओ तो लगाओ, लेकिन आप हटाने वाला काम क्यों कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुख्य मंत्री जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आप भर्तियां निकालो। यह जो छोटी-छोटी भर्तियां, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या सफाई कर्मचारी की निकाल रहे हो, यह भले ही निकालो, लेकिन टीचर्स की भर्ती भी निकालो, स्कूल खाली पड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सवा लाख के करीब टीचर्स के पद खाली हैं। अभी आप रीट की बात कर रहे हो, दूसरी नहीं कर रहे हो। कंप्यूटर शिक्षक भी संविदा पर ले रहे हो। 14 परसेंट मुख्य मंत्री जी आपके विधान सभा क्षेत्र में, दिया कुमारी के 18 परसेंट, वसुंधरा जी के 30 परसेंट, दिलावर साहब के

21 परसेंट पद खाली पड़े हैं, भर्ती करो ना। ....(व्यवधान).... कोई बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे आग्रह करूंगा कि या तो शिक्षा मंत्री जी को अधिकार दो कि यह खुल्ला बोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी बोले चाहे। यह शिक्षा की बात होती है तब तो कहते हैं कि मुख्य मंत्री जाने या समय आने पर जवाब दूंगा और बाकी अर्ध नग्न शिक्षिकाएं, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, इस विषय में जाना ही नहीं चाहता कि ये क्या-क्या बोल जाते हैं। इनको तो मेरा नाम ले लो और फिर उसके बाद इनका तो पूरा काम शुरू हो जाता है। नैतिक शिक्षा की बात आपने महामहिम से कराई और दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की बात करेंगे। आप बताओ, कोटा में कोचिंग के बच्चों ने आत्म हत्या की, उसमें कहा कि प्रेम प्रसंग था। आप गये थे क्या उनका वार्तालाप सुनने के लिये? यह समझ के बाहर की बात है। हमने विदेश में गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिये राजीव गांधी जी के नाम से योजना चलाई, आपने स्वामी विवेकानंद कर दिया, काई बात नहीं। हमने 500 का टार्गेट रखा, आपने टार्गेट घटा दिया। आप 130 बच्चों का सलेक्शन नहीं कर पाये। जो फरवरी में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिये, इस योजना का जो कार्य पूरा होना चाहिये, मुख्य मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी उसको जुलाई तक ले आये। उच्च शिक्षा मंत्री जी के तो दिल्ली के दौर भी बढ़ गये थे, आजकल तो कम हो गये। आपका तो समझ में आता है, उनके दिल्ली के दौरे बड़े-बड़े होटलों में क्यों हो रहे हैं, यह हमारे समझ में नहीं आता। ....(व्यवधान).... आप बुलवाना चाहते हो क्या? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दिल्ली के दौरे ही तो बता रहा हूं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः माननीय श्रीचन्द जी, संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, आप विराजो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ....(व्यवधान).... ये इधर-उधर की बातें करेंगे, दिल्ली के दौरे करेंगे, यह करेंगे। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः आपके मंत्री महोदय खड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इनका मंत्री बनने का था और वह आपने छीन लिया, यह आपको बख्शेंगे नहीं, मैं आपको आज बता रहा हूं।

श्री अध्यक्षः यह विषय नहीं है। इसको राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित करो इसको।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आसन के प्रति अविश्वास प्रकट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहो। ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह सब बातें हटाने जैसी हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भर्तियों पर बहुत वाह-वाही कर रहे हैं कि हमने यह भर्ती कर दी, यह कर दी। मुख्य मंत्री जी, पेपर लीक पर भी आऊंगा आप थोड़ा धैर्य बनाये रखें, विराजमान रहें तो अच्छा लगेगा। राज्यपाल महोदय

से आपने कहलवाया 59,236 नियुक्तियां दे दीं। 17 तारीख को जो आपके एक साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ, उसमें आपने अपनी पुस्तक में कहा कि एक वर्ष में 32 हजार नौकरियां हमने दे दीं। 17 दिसम्बर से लेकर 3 फरवरी तक आपने ऐसा क्या जादू घुमाया कि जब 31 तारीख को महामहिम से 59,236 का कहलवा दिया। मतलब 32 हजार से 59 हजार और फिर 1 लाख का आपने वादा कर दिया, एक बार नहीं, एक हजार बार वादा कर दिया और एक साल के विज्ञापन में आपने लिख दिया 47 हजार और 2025 में 81 हजार देंगे, यह माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। आप जोड़ तो मिला लो। एक चीज तो कहलवाओ, विज्ञापन में अलग, आपका ट्विट अलग, आपकी 12 महीनों की उपलब्धियों में अलग, आपके महामहिम के अभिभाषण में अलग और अब आप कह रहे हैं कि 1,72,900 की भर्ती प्रक्रियाधीन है और फिर कह रहे हैं 4 लाख दे देंगे और 81 हजार का एक विज्ञापन मैंने देखा। मुझे सुबह-सुबह लगा कि आज तो मारे गये, 81 हजार का विज्ञापन दे दिया तो मुख्य मंत्री जी ने युवाओं के लिये कुछ न कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। मुख्य मंत्री जी, जब मैं उसे पढ़ने लगा तो आप थोड़ी हंसी रोक कर रखना, उसमें से 52,453 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। उसमें 52 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 8,256 एनएचएम में संविदा कर्मी, 2,200 खंबे पर चढ़ने वाले टीए बिजली बोर्ड के, 2041 पशुधन सहायक, कुल मिलाकर यह 64,950 बनते हैं और कुल 16,050 बची हैं, जिसमें से 2202, 24 विषयों के सैकिण्ड ग्रेड के अध्यापक। आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं साहब, दो-दो अध्यापक पाती आयेंगे। 29 विषयों में 2200 का सैकण्ड ग्रेड का आप विज्ञापन निकाल रहे हैं और उस पर आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सफाई कर्मचारी, क्यों रोक दी सफाई कर्मचारी की भर्ती? हमने 30 हजार, आपने 23 हजार का कहा, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। फर्जी प्रमाण पत्र खूब बने। 10-10, 20-20, 50-50 हजार में खूब बने ....(व्यवधान).... कोई बात नहीं, उसकी जांच करानी चाहिये। आपने उसको रोक दिया कि कल निर्णय आना है। यहां मंत्री जी बैठे हैं, वह हमारे सीकर से ही हैं, हम दोनों साथ में प्रधान रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों को संविदा पर रखेंगे, 4-6 महीने उनका परीक्षण लेंगे और उसके बाद नियमित करेंगे। साहब, इस राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह कर दिया मुख्य मंत्री और मंत्री परीक्षण कर के क्यों नहीं लगाये? इनको सीधा ही स्थाई ठोक दिया ....(व्यवधान).... क्या बात है, मेरी समझ में आयेगा वह बोलूंगा। ....(व्यवधान).... किया था क्या परीक्षण?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको परीक्षण करके लगाया था तो फिर आपको शिक्षा मंत्री से क्यों हटाया, वह बता दो?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने परीक्षण करके लगाया होता तो उप मुख्य मंत्री को नाकारा नहीं कहना पड़ता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नाकारा, निकम्मा, यह किसने कहलवाया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब आपका मौका आयेगा, आप बोल लेना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की गरिमा बनाये रखूंगा, अगर इनको किसी बात पर एतराज होता है तो इनके बोलते ही मैं दूसरा विषय चेंज कर लूंगा।

पेपर लीक, कानून व्यवस्था, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपने एस.आई.टी गठित की, हमने स्वागत किया। आपने कहा हम सी.बी.आई. से भी जांच करा सकते हैं, खुली छूट दे दी, हमने स्वागत किया।

Msk/rtm/03.02.25/1530/2m

आपने हम लोगों के ईडी भेजी, हमने स्वागत किया। दोबारा भेजो, स्वागत है। ..(व्यवधान).. रुक जा, सब चीज में बोलना जरूरी थोड़े ही है।

मैं यह कह रहा हूं कि आप भर्ती और युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं तो आरपीएससी का चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे हैं? आप आरपीएससी में खाली पदों पर मेम्बर क्यों नहीं बना रहे हैं? मगरमच्छों को पकड़िये, आपको किसने मना किया? साहब, कहीं ऐसा नहीं हो जाये कि हमारी सरकार चार साल बाद आये तो आपमें से किसी के लिए जेल के गेट चौड़े कराने पड़े। खा-खाकर इतने बड़े मगरमच्छ हो जायें कि गेटों को चौड़ा करने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आपको मना किसने किया, आप कीजिये। हो सकता है किआपके मन में कोई मैल नहीं होगा, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि आप अपने संगठन से आये हुए हैं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुख्य मंत्री जी आपने 12 महीने निकाल दिये। 12 महीने निकाल दिये, पकड़ूंगा, पकड़ूंगा, पकड़ूंगा। साहब ये रूटीन के काम हैं। आपने कहा कि हमारे कोई भर्ती लीक नहीं हुई। अभी माननीय कैलाश वर्मा जी, आपने बहुत लिखकर दिया होगा, आपके कार्यालय ने बहुत अच्छा लिखकर दिया है, मैं स्वागत करता हूं। वे कह रहे थे कि आरएएस का पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। नवलगढ़ में बन्द लिफाफे खुले मिले हैं, परीक्षा हॉल में आने से पहले। मैं आपको और बताऊं। नेशनल सीड कॉर्पोरशन का राजस्थान में पेपर लीक हो गया। बीएससी (नर्सिंग) आयूएचएस का पेपर लीक हो गया। डीएलईडी सैकेण्ड ईयर का पेपर लीक हो गया। एनसीसी (सी ग्रेड) का पेपर लीक हो गया। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एमएससी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया। कल आरएएस का नवलगढ़ के अन्दर लीक हो गया। आप छोटे छोटे एग्जाम का बता रहे हैं, आप बड़े तो करा ही नहीं रहे हैं। करायेंगे तब पता चलेगा। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। हम आपकी सरकार के साथ इस बात में साथ ही हैं कि अगर कोई पेपर सरगना है तो उनको पकड़ो, जेल में डालो, आगे से किसी का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इस बात की भी व्यवस्था करो। हमें इन बातों में कोई दिक्कत नहीं है।

आपने कहा, कानून व्यवस्था। बड़ी-बड़ी बातें कीं। आपकी कानून व्यवस्था के बारे में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक साल में करीब सात हजार

महिलाओं से रेप, 1610 नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी, 2023 की तुलना में नाबालिग बच्चियों से 3.34 प्रतिशत अधिक दरिंदगी हुई, 2022 की तुलना में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी 10.12 प्रतिशत, एक साल में आदिवासी समाज एसटी की नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी 46.62 प्रतिशत। मुख्य मंत्री जी, 46.62 प्रतिशत। 2024 में पॉक्सो एक्ट के रिकॉर्ड 2082, आज तक इतिहास में दर्ज नहीं हुए हैं, उतने हुए हैं। तीन साल में सबसे ज्यादा हैं। बालोतरा में दिन-दहाड़े बेटी का अपहरण, डीग में दिन-दहाड़े दसवीं की छात्रा का अपहरण, भरतपुर में माफियाओं का महिला पर अत्याचार, रूपनगढ़ में खुलेआम गोलीबारी, उदयपुर में 15 साल के छात्र देवराज की हत्या। जोधपुर में अनिता चौधरी का हत्याकाण्ड। समरावता में किस प्रकार से क्या किया, किरोड़ी जी न्यायिक जांच करा रहे थे, वे तो छुट्टी लेकर चले गये। लेकिन आपकी सरकार ने कहा था, बेढ़म साहब, गृह राज्य मंत्री बैठे हैं। आपने गृह राज्य मंत्री अच्छा बना रखा है। आप इनको पॉवर दें, इनको आपने सिपाहियों की पॉवर नहीं दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने संभागीय आयुक्त से जो जांच करायी, उसका क्या हुआ? आप बतायें। मैं एक नहीं, आपको एक हजार बता दूं। आप देखिये, दौसा में माफियाओं के सामने पुलिस का सरेण्डर, टोंक में खनन माफियाओं द्वारा कांस्टेबल की हत्या, सवाई माधोपुर में एसडीएम ज़ाब्ता मांगता रहा, अवैध बजरी निकलती रही। मालपुरा में माफियाओं का पुलिस पर हमला। बारां में पुलिस पर फायरिंग, बांरा-अटरू में किसनाराम मेघवाल हत्याकाण्ड, शिक्षक शंकरलाल मेघवाल, बूंदी में शिक्षक, बाड़मेर में व्यापार मण्डल अध्यक्ष सूजेलाल जैन की हत्या। हनुमानगढ़ में, जोधपुर में 5 बच्चियों से 15 दिन में हैवानियत। अलवर में आईसीयू में महिलाओं का रेप, जयपुर में पुलिस थाने के क्वार्टर में छात्रा का रेप, बीकानेर व डूंगरगढ़ में स्कूली छात्रा, जालौर में प्रिंसीपल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हैवानियत। एक कल परसों की शर्म की बात है कि एक शिक्षक जिसको आपने बर्खास्त कर दिया। मंत्री जी चले गये। मुख्य मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि उसको अश्लील हरकत के कारण से बर्खास्त कर दिया, लेकिन आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको कॉर्डिनेटर लगाने के लिए सिफारिश की है। जनता जानना चाहती है कि शिक्षा मंत्री जी का उस व्यक्ति से, मैं उसका इस सदन के अन्दर नाम नहीं लेना चाहता, इतना घृणित काम करता है, उसकी आप सिफारिश कर रहे हैं। यह आप कहां किस तरीके से क्या बातें कर रहे हैं, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जिले संभाग खतम कर दिये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः आपका समय हो गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पांच मिनट, मुख्य मंत्री जी आराम से सुन रहे हैं। चिंता मत करिये, मैं नहीं आ रहा हूं। मैं एक बार लास्ट में आऊंगा।

मुख्य मंत्री जी, आपने जिले संभाग क्या सोचकर किये? एक रिपोर्ट जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने दी है, बाड़मेर वाले रिटायर्ड आइएएस ने। वे लोकसभा के दौरान बीजेपी जॉइन कर चुके हैं। मंच के सामने मोदी जी के साथ उसकी फोटो है, उससे आपने हमारे जिले ही

खतम करा दिये, संभाग ही खतम करा दिये। थोड़ा बहुत दायां-बायां कर देते, साहब आप मुख्य मंत्री हैं। फिर आपने जिले और संभाग खतम करके इतना अच्छा काम कर दिया तो महामहिम राज्यपाल से आप एक बात तो लिखवा देते कि हमने बहुत अच्छा काम किया। जब और ही लिखवाया तो यह भी लिखवा देते कि आप किसानों की बिजली को निजी हाथों में दे रहे हैं, वही लिखवा दे देते कि हम निजी को दे देंगे।

मैं लंबी बात पर नहीं जाऊंगा। आप 'वन नेशन वन इलेक्शन' क्या शगूफा लाये हैं, इसको आप पांच साल बनाये रखना। आपकी वाहवाही हो जायेगी कि एक इतिहास पुरुष आया था, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा मुख्य मंत्री बने तो कैसे जनता को राहत प्रदान की कि इन्हीं सरपंचों के कार्यकाल बढ़ा दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने झुनझुना पकड़ा दिया, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली एसएफसी राज्य वित्त आयोग की 2024-25 की बकाया राशि 3800 करोड़, 2023-24 की सैकेण्ड किस्त 1400 करोड़, उसमें से थोड़ी-सी राशि दी है। पांच हजार करोड़ रुपये, आपने ग्राम पंचायतों की पंचायतों समितियों, जिला परिषदों के पैसे रोक रखे हैं। आपके पास देने के लिए धैला नहीं है। आप क्यों बढ़ा रहे हैं और कैसे करायेंगे, वन-नेशन, वन इलेक्शन। एक नयी इकाई जिस दिन गठित होगी, उस दिन पुरानी इकाई का विघटन होगा और पुरानी इकाई विघटित होगी तो यह लास्ट में होगा, एक साथ करायेंगे उस दिन। तब तक यह परिसीमन का खेल खेलते रहो, जनता को फुटबॉल बनाते रहो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सर, आखिर में बिजली की बात करुंगा। बिजली मंत्री जी बैठे हैं। इनकी थोड़ी बढ़ाई कर दूं। अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों को साल के 12 हजार रुपये की सब्सिडी दी। घरेलू में भी, आप बताइये कि नये जितने जुड़े गये, आपने एक का किया हो तो बता दें। आपके कैबिनेट मंत्री तो यहां आकर कहते हैं कि इस झमेले को खतम करें। क्यों सब्सिडियां देते हैं? एक बात जो आप बार-बार कहते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आप मनन करना, अधिकारियों से पूछ लेना। आप कह रहे हैं कि बिजली में मैंने ऐसा कर दिया, हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया। भाई साहब, किसान को चार घंटे बिजली नहीं मिली। वसुंधरा जी के समय में भी और अशोक गहलोत जी के समय में भी, दस साल तक किसान को फसल के लिए छह घंटे बिजली मिली, आपके आने के बाद चार घंटे बिजली नहीं मिली। आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली आ रही है, यह कोई ऊपर से चमक-चमक कर थोड़े ही आ रही है। केन्द्र की सरकार द्वारा 1000-1100 मेगावाट जो राज्यों को देनी होती है, उनका कमिटमेंट होता है, वह बिजली हमारी सरकार को नहीं दी थी, वह बिजली आपको मिलने लग गयी। कोयले में छत्तीसगढ़ की प्रोब्लम हमारे समय में थी, आपकी वह प्रोब्लम दूर हो गयी। ये दो कारण हैं, जिनके कारण बिजली ठीकठाक है, लेकिन किसान को नहीं मिल रही है और बिजली का पैसा आपने कितना बढ़ाया, यह आप देखें। 500-1000 नहीं, एक-एक बिल के ऊपर दो-दो हजार रुपये। हर व्यक्ति के ऊपर बढ़ाने का काम कर दिया। अब तो आप निजी

को दे देंगे। किसानों और गरीबों के लट्‌ठ मारेंगे। ये प्राइवेट वाले दलितों और पिछड़ों के लट्‌ठ मारेंगे। यह मॉडल कहां से लाये हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साहब आपने बहुत ट्रांसफर बहुत किये हैं। बहुत अच्छा है। क्या बात है? गजेन्द्र खींवसर साहब तो हैं नहीं, वरना मैं इनको धन्यवाद देता।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, खतम करें। चार मिनट ज्यादा हो गये, कनक्लूड करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं इनको धन्यवाद देता कि इन्होंने जो किया है, वह कहना चाहता हूं। एएनएम बाड़मेर जायेगी, , वहां जायेगी, क्या तांडव मचाया? क्या तमाशा लगा रखा है? हर व्यक्ति यह कहता है कि मंत्री के यहां नाम नहीं था, सीएमओ में जुड़ गया है। कोई कहता है, मंत्री के था, सीएमओ में कट गया है। साहब, सामंजस्य स्थापित कर लें और इन ट्रांसफरों से हमें बहुत नुकसान हुआ था, आपको भी नुकसान होगा, यह सचेत रहने की आवश्यकता है। ये जो ट्रांसफर कराने वाले हैं, वे तेल लगा-लगाकर, मस्का लगा-लगाकर करा ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या परिणाम होता है, वह हम सब देखते हैं।

mdp/rtm/03.02.25/15:40/2n

इसलिए कम से कम ट्रांसफर कैसे हों, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। मैं एक बात और कहते हुए कि ये किरोड़ी जी वाला तो सॉल्व करना पड़ेगा साहब, मेरे साढ़ू हैं, मैंने साढ़ू बनाया है और आपको उन्होंने दौसा में भाई बनाया था, लेकिन वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि मुख्य मंत्री जी ने भाई बनकर मेरी पीठ में छुरा घोप दिया, ...(व्यवधान)....ये किरोड़ी जी का दर्द है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह अभिभाषण का पार्ट नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये ही जवाब दे देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): समय आने दीजिए तब ये भी जवाब दे देंगे। जवाब नहीं मुंहतोड़ जवाब देंगे। सुनते रहना, याद रखना, उस दिन हाजिर रहना।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पांच मिनट ज्यादा हो गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लास्ट।

श्री अध्यक्षः आखिरी एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट में साहब। एक बात बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, जब आपका कैबिनेट मंत्री यह कह रहा है कि रोजाना की 7 करोड़ की बीसलपुर में चोरी हो रही है बजरी और उसके बाद में आप सब मौन धारण किए हुए हैं, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।

श्री अध्यक्षः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्री जी, जवाब देना पड़ेगा। किरोड़ी जी जो कहकर गये हैं, वह छोटी बात नहीं है। एक मंत्री कह रहा है, मुख्य मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका कैबिनेट मंत्री कह रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप विराजिए। मैंने अगला नाम पुकार दिया। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर इसके बाद भी आप नहीं सुधरेंगे तो आप का राम रखवाला है। धन्यवाद, जय हिन्द। जय भारत।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पर इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूं।

हमारा मंत्र- हमारा विश्वास, सबका साथ-सबका विकास,
सुशासन से फैले समृद्धि की धार, गांव-गांव गूंजे प्रगति की पुकार,
अंत्योदय से हर दीप जले, निर्धनता के तमस को दूर करे,
मोदी संग बढ़ेंगे, रचेंगे नव इतिहास,
नये भारत, नये राजस्थान का नव प्रभास।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य की प्रगति और विकास के लिए उठाये गये ठोस कदमों का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि राज्य की जनता ने असत्य वादों और मिथ्या दोषारोपण, जो अभी माननीय सदस्य हमारे कर रहे थे की राजनीति को सिरे से नकार दिया गया है। राजस्थान ने अपनी जागरूकता और विवेक से यह सिद्ध करदिया है कि असत्य वादों और मिथ्या दोषारोपण की राजनीति का समय अब समाप्त हो गया है। जनता अब प्रमाणित नेतृत्व और ठोस विकास को प्राथमिकता देती है। हमें इस विश्वास को बनाए रखते हुए राज्य को आगे बढ़ाना है और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक, यह आपके लिए ही मैं बोल रही हूं माननीय सदस्य कि सकारात्मक बदलाव लाना है। विपक्ष के साथियों की स्थिति पर तो मैं यही कह सकती हूं कि-

वादों के महल जो बनाते रहे, हकीकत की जमीन से कतराते रहे,
जो लूटे थे सपने, वही रहनुमा अब खुद को मसीहा बतलाते रहे।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि अच्छे इरादों के साथ सुशासन हमारी पहचान है। पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ समर्पण भाव से कार्य करना ही हमारा मूल स्वभाव है। प्रधान मंत्री मोदी जी के विचार सुशासन और समर्पण की भावना को प्रदर्शित करते हैं, जो हमारी सरकार की कार्यशैली का मूल आधार है। महामहिम के अभिभाषण से यह बात स्पष्ट है कि हमारी सरकार संविधान के मूल आदर्शों पर आधारित है। सुशासन तभी सार्थक सिद्ध होता है जब प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, सुरक्षा और न्याय प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू

करते हुए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार किए हैं।

इसके अलावा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और वंचित वर्गों को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का व्यापक उल्लेख किया गया है। सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र पारदर्शिता, प्लीज इस बात को आप नोट कीजिए कि प्रशासनिक तंत्र पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर कार्य करे और यही कारण है कि पिछले एक वर्ष में एक भी पेपर लीक और एक भी परीक्षा रद्द नहीं हुई है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन उद्देश्यों और योजनाओं का उल्लेख किया गया है, वह यह सिद्ध करते हैं कि सरकार राज्य के हर नागरिक को समृद्ध और सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव मिथ्या दोषारोपण की राजनीति को ही अपनाया है। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए लिये गये प्रत्येक निर्णय का निराधार विरोध किया है। आपने विरोधियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस ने बार-बार संवैधानिक संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार एवं तुष्टिकरण की राजनीति को अपनी कार्यशैली बना लिया है। तभी मुझे लगता है कि इनको अच्छे से पता है कि कौन, कहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी सार्थक संवाद, सहमति और समझौते की भावना में कोई विश्वास नहीं रखती। उनका उद्देश्य केवल नकारात्मक राजनीति करना और जन हित की नीतियों में बाधा उत्पन्न करना रहा गया है।

संविधान की गरिमा जो ठुकराये,
भ्रष्टाचार के पथ पर जो चला जाए,
जनता ने ठुकराया उसे दिया ये संदेश,
अब विकास ही होगा राजस्थान का वेश।

वैसे भी कांग्रेस के मन में न तो इस राष्ट्र के जन, न सनातन किसी के लिए भी कोई सम्मान नहीं रहा। इसीलिए उनके नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कभी तो राम मन्दिर, तो कभी काशी कोरीडोर पर सवाल खड़े करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आस्था के उत्सव महाकुम्भ पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुम्भ के पवित्र स्नान को भुखमरी और गरीबी से जोड़ने वाले इन नेताओं से मैं पूछना चाहती हूं कि गरीबी हटाओ जैसे नारे देकर इस देश में सर्वाधिक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी कब तक अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था, सनातन संस्कृति व उनके उत्सव का अपमान करते रहेंगे।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

महाकुम्भ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह भारत की सनातन परम्पराओं की जीवन धारा है। यह आयोजन, जहां न केवल संत और श्रद्धालु एकत्र है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का एक विराट दृश्य प्रस्तुत करता है। दुनियाभर से लोग यहां आते हैं। आस्था की गंगा में डूबकी लगाते हैं और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनते हैं। यह आयोजन न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता है, बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है।

तुष्टिकरण में डूबे लोग भारत के मन को क्या समझेंगे,
आस्था के उत्सव के अद्भुत आगमन को क्या समझेंगे,
राममंदिर और महाकुम्भ पर जिनकी प्रश्न की उठाने की आदत,
ऐसी कुंठा वाले लोग अपने सनातन को क्या समझेंगे।

राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि महाकुम्भ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, आध्यात्मिक ऊर्जा और विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। कांग्रेस की टिप्पणियां उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को उजागर करती है, जबकि भाजपा सरकार आस्था और विकास दोनों को समान रूप से बढ़ावा दे रही है। यह महाकुम्भ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एकता और समता का संगम है, जिसमें संपूर्ण देश की आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का दर्शन होता है।

राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने प्रदेश के सतत विकास के साथ हमारी समृद्ध धरोहर के संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने प्रयागराज में महाकुम्भ आयोजन स्थल पर 'राजस्थान मंडप' की स्थापना की, जो राज्य की सांस्कृतिक भव्यता और लोक परम्पराओं का परिचायक है। महाकुम्भ में राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा काविशेष ध्यान रखा गया है। सरकार द्वारा निशुल्क आवास एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था की गयी है। इससे श्रद्धालु अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें। यह पहल राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी सोच और सेवा भाव का परिचय देती है।

माननीय सभापति महोदय, आज भारत संस्कृति और आधुनिकीकरण का संगम बनता जा रहा है। जिस तरह से सरकार ने अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण किया। काशी विश्वनाथ कोरीडोर और महाकाल लोक जैसी परियोजना शुरू की, उसी तरह महाकुम्भ को भी एक भव्य स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बदले भारत का नया चित्र है जहां परम्परा और प्रगति साथ-साथ चलते हैं। जहां आस्था और आत्मनिर्भरता एक साथ बढ़ती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। विशेष रूप से जनजाति समाज के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए हमने उनकी गौरवशाली परम्पराओं को सम्मान और नयी पहचान देने का कार्य किया है। इसी के चलते

जनजातीय इतिहास और संस्कृति को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उदयपुर में कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर में डूंगर बरंडा जैसे महान जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

Ans/rtm 15.50 20 03.02.2025

यह स्मारक ना केवल जनजाति समाज के गौरवशाली अतीत की गाथा को प्रस्तुत करेंगे बल्कि युवाओं को अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने को भी सहायक सिद्ध होंगे। जनजातीय क्षेत्रों में संरचना विकास एवं आर्थिक सुदृढीकरण को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि जनजाति समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

हमारी सरकार ने बेणेश्वर धाम और मानगढ जैसे पवित्र स्थलों के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। **इन** स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केन्द्र बन सकते हैं। किन्तु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी जनजाति समाज को सनातन धर्म से अलग करने की राजनीति कर रही हे। उनका यह प्रयास समाज को बांटने एवं सांस्कृतिक एकता को कमजोर करने के षड्यंत्र का भाग है। कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति से ना केवल जनजाति समाज की एकता की समृद्ध परम्पराओं को आघात पहुंचता है बल्कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए भी एक बड़ा खतरा है।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। यही कारण है कि आज किसानों को डिजिटल परिवर्तन और एग्रीस्टैक की भूमिका में आगे बढ़कर लिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में एग्रीस्टैक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना को राजस्थान में लागू करने का काम भी प्रारम्भ कर दिया है। यह परियोजना किसानों को इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन टेक्नीक का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बात नहीं करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): किसानों को अधिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए डिजिटल परिवर्तन एग्रीस्टेक की भूमिका से उनकी आय में वृद्धि के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के माध्यम से किसानों से जुड़ी विभिन्न सूचनाओं का एक व्यापक डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जा रहा है। जिस डेटा बेस से

एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों की जन सांख्यिकी जानकारी, जमीन की जानकारी और उनकी बोई गई फ़सलों के बारे में विस्तृत डेटा एकत्रित किया जाता है। यह डेटा कृषि क्षेत्र में नीतिगत निर्णय लेने और किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एग्रीस्टेक से किसानों की रजिस्ट्री, गाँवों के नक़्शे और बोई गई फ़सलों की सूचना शामिल होगी,जिससे यह डिजिटल प्लेटफार्म केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के मंत्रालयों को किसानों से सम्बन्धित सटीक जानकारी समय पर उपलबध कराएगा। इस जानकारी का उपयोग किसान केन्द्रित डिजिटल सेवाएं विकसित करने, कृषि योजनाओं को लागू करने और किसानों को समय पर सही संज्ञान देने के लिए लिया जाता है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफोरमेशन को गति देने में भी यह सहायक सिद्ध होगी।

इसके साथ-साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में वृद्धि, गेहूँ के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, कृषि कनेक्शन में वृद्धि, बिजली बिलों में अनुदान, मंडियों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण एवं मंडियों को डिजिटल प्लेटफार्म और इलेक्ट्रोनिक नेशल एग्रीकल्चर मार्केट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसल का सीधा व्यापार कर सके। राजस्थान सरकार की यह किसान हितैषी नीतियां कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। किसान सम्मान निधि में वृद्धि, गेहूँ के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, नये कृषि कनेक्शन, बिजली बिलों में अनुदान और मंडियों का विस्तार जैसे निर्णय किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मददगार साबित होंगे। राज्य सरकार का यह प्रयास किसानों के लिए एक नई उम्मीद एवं संभावनाओं का द्वार खोलता है1

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गये अभूतपूर्व कार्यों का उल्लेख प्रदेश की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। चिकित्सा क्षेत्र में किए गये यह प्रयास ना केवल जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं बल्कि प्रदेश को एक स्वस्थ व समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इस दिशा में हमारी सरकार ने गत बजट के कुल बजट का रिकार्ड 8.26 प्रतिशत चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किया है। यह आवंटन राज्य के स्वास्थ्य के ढाँचे को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले अंतरिम बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई चिकित्सा सुविधाएं ऐसी विधान सभाओं में मिली है जहां पर जब से हमें आजादी मिली तब से वहां चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई, इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सर्वांगीण विकास की सोच से अपने बजट को पेश किया था। राजस्थान ने संस्थागत प्रसव, मातृ शिशु, मृत्यु दर, टीकाकरण और चिकित्सा संस्थानों की उपलब्धता जैसे कई महत्वपूर्ण मानकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

इसके साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में भी राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति

की है। प्रदेश में करीबन छह करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है जो लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है जो हमारे डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की सफलता को दर्शाता है। स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडीकल स्टाफ के करीब 21 हजार पदों पर नियुक्ति की है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग ने लगभग 50 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है, जिसे जल्दी ही पूरा किया जाएगा। यह कदम राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगा। आम जन को सुलभ व सस्ती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी के माध्यम से पहली मेडिसिन की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा 01 लाख 67 हजार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों की संख्या में लगातार वृद्धि की गई है जिससे लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक दवाइयां उपलबध हो सके।

इसके साथ-साथ टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया। यह अभियान टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने और इस बीमारी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। हमारे प्रयासों का उद्देश्य राज्य को स्वस्थ व समृद्ध प्रदेश बनाना है जहां हर व्यक्ति स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारी राजस्थान सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी के लिए भी अनुरोध किया है। यह मेजबानी प्रदेश के खेल के ढाँचे को सुदृढ़ करने, युवाओं में खेल भावना विकसित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान बनाने में बहुत सहायक होगी।

श्री सभापति: कंक्ल्यूड करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में उपखण्ड, जिला व राज्य स्तर पर खेलों राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अवसर दिया जाएगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें करीबन 3500 खरब रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है। निवेश के साथ-साथ प्रदेश में रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनिस को बेहतर बनाने के लिए अधोसंरचना विकसित करने और निवेशकों का विश्वास बनाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। यह समिट राजस्थान को औद्योगिक और आर्थिक केन्द्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

इसके साथ-साथ अब तक 59 हजार नियुक्तियां दी गई है जबकि 1.73 लाख पदों पर प्रक्रिया जारी है। न्यायालय में लंबित भर्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी हो रही है। साथ ही 81 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा का कलेण्डर भी घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

मारी सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों को चयनित करके महाविद्यालय खोले गये हैं, करीबन 37 नये राजकीय विद्यालय और 06 नये राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यह पहल छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों के.....

VPS-RTM-03.02.2025-16.00-2p

श्री सभापतिः विराजिये। माननीया, समय पूरा हो गया।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं कंक्लूड करने के लिए दो मिनट लूंगी। युवाओं के लिए- शिक्षा के नये द्वार खोलने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सारी नई स्कीम्स चालू की हैं जिसमें प्रधान मंत्री मातृ वंदन योजना, वे कैसे आत्मनिर्भर हो सकें, राज सखी के माध्यम से आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 प्रतिशत राज्य निधि में बढ़ोतरी और मुख्य मंत्री अमृत आहार योजना एवं लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी कई योजनाएं महिलाओं के लिए चालू की गईं। इसके साथ ही साथ हमारे आदरणीय स्वर्गीय अटलजी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का आदर्श राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है।

आज हमारे देश में दो विचारधाराओं के बीच में एक स्पष्ट संघर्ष का सामना हो रहा है। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं रहा है बल्कि यह हमारे राष्ट्र के भविष्य, उसके विकास और उसकी एकता, अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री सभापतिः विराजये, प्लीज।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत उक्त धन्यवाद प्रस्ताव का आपकी अनुमति से अनुमोदन करती हूं।

अंत में, अपनी बात को कन्क्लूड करते हुए मैं आप सबसे यही कहूंगी कि सबका साथ, सबका विकास का इरादा है, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान हमारा वादा है। अंत्योदय से जगमगायेगा हरेक गांव, सुशासन से बढ़ेगा राजस्थान का नाम। मोदी के संग चलें, रचे नये इतिहास, विकसित भारत का अब है यह प्रयास। निर्धनता के अंधेरों को मिटाएंगे, नया भारत, नया राजस्थान बनाएंगे। प्रगति की लहर हर ओर लाएंगे, सबको साथ लेकर देश सजाएंगे। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम का भाषण एक घंटा

27 मिनट और 22 सैकण्ड चला। मैं लम्बे समय से सुन रहा हूं, कई महामहिम तो इसको पढ़ा हुआ ही मान लेते थे। ये आदिवासी थे, इसलिए इन्होंने पूरा पढ़ा।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): आप तो सैकण्ड का भी हिसाब रख रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को।

अब उन्होंने क्या किया? कुल 44 पेज का भाषण पढ़ा और सारी बातें उनको जो लिखकर दी गईं, वे पढ़ दीं। अभिभाषण तो पढ़ने के लिए होता है, वह पढ़ लिया लेकिन कमियां क्या-क्या हैं, वे चाहे इधर हों या चाहे उधर हों, कोई दूर तो करता नहीं है। अब आप यह देखिये कि जब मैं शुरू में आया था तो उन्होंने यह कहा था कि टेंडर हो गये हैं कुम्भाराम लिफ्ट योजना के पानी के और उसके बाद पहले महीने में ही उस टेंडर को खारिज कर दिया। आज स्थिति यह है कि पानी के लिए कोई बोलता नहीं होगा लेकिन चाहे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की बात आप कर लो, चाहे बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य की बात कर लो, सारे पानी के लिए दु:खी हैं पर वे इस कुर्सी के माध्यम से बंधे हुए हैं।

मैं यह खुले रूप में कहता हूं कि अगर यही हालात रहे और यही सारा चलता रहा तो लोग रोड पर आ जाएंगे। मेरे क्षेत्र में तो आ ही रहे हैं। जो पांच कुएं माननीय जल मंत्री ने दिये थे, दस हैंडपम्प दिये थे, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज तक भी उनका टेंडर नहीं हुआ है, आज तक वे कुएं नहीं खुदे हैं। आप यह देखिये कि पांच कुएं तो ऊँट के मुंह में जीरे के सामन थे और वे भी नहीं कर पाये तो फिर क्या फायदा? आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं? आज अख़बार में यह आया था कि एक महीने में 1 लाख 30 हजार कनेक्शन देंगे तब 2028 में जाकर जल जीवन मिशन पूरा होगा। आपका पूरा नहीं होगा। पानी गांवों में है ही नहीं। आपने कुएं तो खोद दिये पर उनमें पानी नहीं है और जल मंत्री इस सरकार को पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। आप यह देखिये कि गांवों में कुआं खोद दिया और उसका कनेक्शन पास में ही है लेकिन सरकार का एग्रीमेंट नहीं है इसलिए वह कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कुआं तो हमने खोद दिया हमारे कोटे से, पंचायत समिति ने खोद दिया अपने कोटे से, सरपंच ने खोद दिया अपने कोटे से लेकिन कहते हैं कि ऊपर से पाबंदी है कि आप इस कनेक्शन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने क्या कर रखा है? आगे खाना देकर पीछे हाथ बांध दिये। जब कुआं हमने खोद दिया, पानी अवेलेबल है तो कनेक्शन आप नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आप यह बताओ? मंत्रीजी, आप बोलो। आप थोड़ी देर पहले बहुत बोल रहे थे। अब आप यह बताओ कि इस पानी का, कुएं का कनेक्शन कौन देगा? सरकार देगी या हम देंगे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अभी हमारा बोलना ठीक नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो अपना बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप कनेक्शन दे सकते हो तो बोलो न? पर बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है।

श्री सभापति: वे आपको बताएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कह रहा हूं कि कोई नहीं बोलता है। मैं बोल रहा हूं, आप बोलने दो। ...(व्यवधान)...

आपके मंत्री भी इसलिए नहीं बोलते कि उनको कभी हटा नहीं दें। नहीं हटाएंगे। इनके पास दूसरे आदमी नहीं हैं तो हटाएंगे कहां से? आदमी ही नहीं है इसलिए मैं यह कहता हूं कि पानी की महती आवश्यकता थी इस राजस्थान को जिसके लिए अशोकजी ने भी पूरा जोर लगा रखा था, आप भी पूरा जोर लगा रहे हैं। एक लोटा पानी का पिलाया नहीं और भाषणों से कान खराब कर दिये। तीन बार तो मैंने कान ठीक करवा लिये डाक्टर से, वह यह कह रहा है कि आपके कान तो इसलिए खराब हो रहे हैं कि आप पानी के बारे में सोचते रहते हो इसलिए कान खराब हो गये। क्या चौथी बार भी करवाना पड़ेगा क्या? मैं तो पानी के लिए ही बोल रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): श्रवणजी सही बोलने वाले हैं। चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो या चाहे कोई सरकार हो, श्रवणजी ने सही-सही बता दिया कि उनकी सरकार में भी गड़बड़ियां हुई हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, रहीम दासजी ने भी कहा था कि- 'रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून।' मोती भी शून्य हो जाते हैं। पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि मार्च के बाद आपका जो सिलसिला अभी चल रहा है, यही चलता रहा तो लोग रोड पर खड़े हो जाएंगे। बिजली के लिए इस बार खड़े नहीं हुए हैं, मैं असत्य बात नहीं कहूंगा, इस बार बिजली के लिए कोई आदमी रोड पर नहीं आया, यह बात सत्य है लेकिन यह थपथपी कब बजाओगे? गांवों में लोग लट्ठ मारेंगे, इसकी थपथपी कौन बजाएगा पानी के लिए?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): श्रवणजी, जैसी बिजली की व्यवस्था की है, वैसे ही पानी की व्यवस्था भी कर देंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कब कर दोगे? बिजली के बिना तो अंधेरे में भी बैठ सकते हैं, दीया भी जला लेंगे। आप जब गांवों में आये थे तो कहा था कि बाबा, आपके घर में दीपक जलाएंगे पर जो केरोसिन तेल था, वह भी बंद कर दिया तो दीपक कहां से जलाएंगे आप? केरोसिन तेल भी बंद कर दिया। मैं यही कह रहा हूं कि पहले जो केरोसिन तेल देते थे, वह भी बंद कर दिया तो अब दीपक कहां से जलाएंगे? बाबा तो रो रहा है झोंपड़ी में बैठा-बैठा। वे नेता कहकर तो गये थे, वोट भी दिया था, पर अब दीपक कैसे जलाएंगे, तेल ही नहीं है। जोगारामजी पटेल ने सुना तो है लेकिन पता नहीं कब क्या होगा? मैं यह कह रहा हूं कि आपकी सरकार में ...(व्यवधान)... आप मेरा टाइम खराब कर रहे हो, यह मुझे मालूम है। माननीय सभापति महोदय घंटी बजा देंगे और फिर मैं बैठ जाऊंगा। आप रुको, मेरी बात को सुनो। आपकी बात मैंने सुनी थी।

श्री सभापति: आप बोलो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जब कैलाश चन्द वर्मा बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आप तो बोलो। आप बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब आप यह बता दो कि जो पांच कुएं आपने दिये थे, वह आप पूरा नहीं कर सके तो अब क्या करोगे? हमें तो पानी की परेशानी है। आप हमें बता दो। मुख्य मंत्रीजी ने भाषण में यह कहा था कि मैं जल पिलाऊंगा, पानी नहीं, वह जल और पानी एक ही होता है। जैसा यह हमारे शिक्षा कह रहे हैं। उन्होंने एक लड़की से पूछा कि आप कौनसी क्लास में पढ़ती हो? वह बोली दसवीं में और दूसरे एक लड़के ने कहा टेंथ में तो इन्होंने कहा कि यह तो टेंथ कह रहा है और आप दसवीं कह रहे हो। जब आप यही अंतर नहीं समझ रहे हो तो मामला चलेगा कैसे?

आप यह देखिये कि यही हालत हमारी फसल की है। आपने फसल की बात कही है। एम.एस.पी. में बाजरा सब जगह किसान का, बगैर खर्चे का बाजरा पैदा होता है तो उसको आपने उसमें से हटा ही दिया। उसको हटा दिया। किसान की यही मूल पैदावार थी।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): यह आपको किसने कहा? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहली बात तो यह है कि आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये। इतना भी नहीं सीखे क्या? बारह महीने हो गये। अपनी सीट पर जाकर बोलिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं जल जीवन मिशन की बात कहना चाहता हूं। एक जे.ईएन. ने जल जीवन मिशन में एम.बी. भर दी परंतु पाइप गया ही नहीं, पाइप गड़ा ही नहीं और उस पाइप की एम.बी. भर दी। ए.ईएन. से उसको सर्टिफाइड कर दिया और एक्स.ईएन. ने उसका पेमेंट कर दिया और जब अजय सिंह राठौड़ ने जांच करवायी तो न तो पानी मिला, न पाइप मिला, कुछ भी नहीं मिला और करोड़ों रुपये लूट गये। भगवान देख रहा है। आप हो या चाहे आप हो, राजस्थान को इस तरह से मत लुटवाओ। पाइप गया ही नहीं, पैसा उठ भी गया तो उसका क्या करेंगे? जल मंत्रीजी हैं क्या? गायब। जब सदन में ये मंत्री गायब रहते हैं तो फिर क्या होगा?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम बैठे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप सबका जवाब नहीं दे पाओगे। कौन है? ये भले आदमी दो-चार बैठे हैं आगे। हमारा उप मुख्य मंत्री बैठा है, वे बैठे ही रहते हैं। आप यह बताइये कि बजट के ऊपर और अभिभाषण पर बोलते हैं तो सभी बिंदुओं पर बोला जाता है तो उस समय सभी मंत्रियों को बैठना जरूरी होता है।

आप यह देखिये कि ये कहते हैं कि हमने तीन सौ सरकारी अस्पताल खोल दिये, चार सौ सरकारी अस्पताल खोल दिये। पहली बात तो यह है, यह मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि ये जो मिलावट की चीजें हैं इन पर आप अंकुश नहीं लगाओगे तब तक आप चाहे जितने भी हॉस्पिटल खोल दो मगर दुनिया जिंदा नहीं रह सकती और जब पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भी राज किया, 76वां गणतंत्र दिवस अपन ने मनाया है तो पटेल साहब, आप यह बताइये कि छह सम्भाग थे, छह सम्भागों में एस.एम.एस. की तर्ज पर

छह हॉस्पिटल खोल देते, एक जैसलमेर का, बाड़मेर का आदमी जब एस.एम.एस. में आता है तो वह तो रास्ते में ही मर जाता है, अजमेर के पास ही मर जाता है। आपने यह क्या किया? एक बिंदु को तो पूरा कर देते। कोई भी सरकार आये तो बातें तो करते हैं पर उसके बाद पूरा करते नहीं है। आप एस.एम.एस. की तर्ज पर छह हॉस्पिटल बना देते तो सारे के सारे रोग दूर हो जाते।

ssy/rtm/03.02.2025/16.10/2q

आप क्या करते हो, इधर से जाते हैं, उधर से आते हैं, वह दौड़ के आ रहा है, कोई झुंझुनूं से आ रहा है। 6 संभाग थे, 6 संभागों में 5 के और बना देते। छठे में, हमारे तो बना हुआ ही है। लेकिन आपके, अजमेर में यहां बना देते तो लोग वहां जाकर के इलाज करा लेते। लेकिन छोटा-छोटा काम करते, पूरा कोई भी नहीं करते। आपने, दोनों सरकारों ने कभी सोचा क्या कि एक बिंदु को तो पूरा करते। एक बिंदु को भी पूरा नहीं किया। ना पानी का बिंदु पूरा किया, ना चिकित्सा का बिंदु पूरा किया, ना शिक्षा का पूरा किया, आज भी 116827 पोस्टें खाली हैं। लेंगे, लेंगे, कब लेंगे? वह सफाई कर्मियों की तो कांग्रेस सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी। आप करते, करते वहां तक पहुंच गये, निरस्त ही कर दी। मतलब, कितना अच्छा किया? उन्होंने विज्ञप्ति निकाल दी, वोट ले लिया। अब आप क्या करोगे बताओ? आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि आपने खत्म ही कर दी।

जो काम आप बता रहे हो, वह नहीं करोगे ना तो गांवों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भी कई मंत्री ऐसे थे, बोलते नहीं थे, करड़े रहते थे, छाप आ जाती थी, सिर पर गर्मी छा जाती थी, अब हुआ क्या कि 53-53 हजार से हारे हैं। पटेल साहब, संसदीय मंत्री साहब, आपके मंत्री तो कुछ ऐसे हैं जो 57522 वोट से हारेंगे। 57 हजार से हारेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं। हां, बता देंगे।

आप देखिये, पहले क्या होता था, अधिकारी लगते थे, भय होता था नेताओं का, अब नेता और अफसर एक ही होने लग गये, सीर की खाने हैं, सीर के टोल टैक्स हैं। शाम को एक संग ही दारू पीते हैं। कैसे डरेंगे? जब तंत्र और मंत्र में अंतर नहीं होगा तो चलेगा कैसे? अब आप देखिये, पहले एसडीएम लगते थे कोर्टो में, 7 केस एक महीने में उसको सलटाने पड़ते थे। अब एसडीएम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। स्टे दे दिया, 50 हजार रुपये ले लिये, स्टे तोड़ दिया 2 लाख ले लिये। अब इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? सरकार ठीक करेगी।

आपके रेवेन्यू बोर्ड में जाकर देखिये 20-20 साल के केस पड़े हैं। एसडीएम कोर्ट में 15-15 साल के पड़े हैं। कोई ध्यान नहीं देता है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। यह गेम चलता रहेगा क्या? आप लोग राजस्थान की जनता के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हो? आते हो, बात सुनते हो, सुनकर चले जाते हो।

मैं कह रहा हूं कि इसको प्रतिबंधित करिये सभी कलेक्टरों को। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि कलेक्टर अपने आपको क्या समझते हैं, आप देखिये मेरे वहां यह विजय सिंह

जी कौनसे हैं? सैनिक कल्याण मंत्री, वहां गये झुंझुनूं में, I don't know about the then situation, वहां सिचुवेशन क्या थी? वहां गये और एक किसान ने कहा, बाबा, ऐ बाबा, बाबा बोला, ऐ बाबा हमें 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। उठाकर के पुलिस वाले ले गये, 4 दिन तक जेल में रखा। ऐसा तो अंग्रेजों के टाइम में नहीं होता था। उसका नाम है रामवतार डांगी, वहां पेंशन के लिए गया था कहने के लिए कि 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, मैं अब भी कह रहा हूं। नहीं मिल रही है तो गलती माननी चाहिए।

आप यह बताइये कि लोकतंत्र में भी लोग बोल नहीं सकेंगे तो कब बोलेंगे। यह ऑथोंटिक बात कह रहा हूं। ऑथोंटिक बात है, कभी यह सोच जाओ कि मैं गलत बोल रहा हूं। यह बात रामवतार डांगी 70 वर्षीय को बोलते ही उठाकर के बंद कर दिया कि डिस्टर्ब मत करो। मंत्री डिस्टर्ब होने लग गये क्या? समय एक ऐसा आयेगा कि डिस्टर्ब नहीं होगे, ईजी हो जाओगे। बिजी नहीं ईजी हो जाओगे। क्योंकि जनता ही तो ईजी करती है। हमारे वाले 22 ईजी हो रहे हैं। घर बैठे हैं।

अब कोई आदमी इस बात को सोचता है कि हमारा स्वायत्त शासन मंत्री बोलता है, कोई जायेगा जब, क्या है? कुछ नहीं है। आप देखिये, एमएसपी से बाजरे को हटा दिया। आज जयपुर की दशा क्या है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अच्छी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अच्छी है? आत्मा से कह रहे हो? आप देखिये, मंत्री जी ने क्या किया? बरसात हुई, 4-4, 5-5, 6-6 घंटों तक गाड़ियां फंसी रही। बेटे वेट कर रहे हैं कि मां कैसे नहीं आई? पापा कैसे नहीं आये? आयेगे कहां, पानी भरा हुआ था। नाले बंद थे। वहां 15 साल पहले के जो बीएसआर है ना, उसी पर काम करा रहे हैं। माननीय संसदीय मंत्री जी, बात बाद में करना, आप बताइये 15 साल पहले लोहे का भाव क्या था? सीमेंट का भाव क्या था? कंकरीट का भाव क्या था? मजदूरी क्या थी? 15 साल पुरानी बीएसआर पर आप काम करा रहे हो। कौन करेगा? ऐसा ही करेंगे। फिर सबको पैसा चाहिए। मंत्री को चाहिए और आपके अफसरों को चाहिए। 30 परसेंट में काम नहीं होता। 70 परसेंट चला गया ऊपर की ऊपर। इसलिए इसकी बीएसआर बदलिये। इसमें ठेकेदारों की गलती नहीं है। ठेकेदार तो भेंट, पूली देकर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना आप पैसा ज्यादा कमाओगे उतने पापी हो जाओगे। कोई भी हो चाहे।

आपको मालूम है प्रधान मंत्री मरता है तो उसका नाम भी डैड बॉडी होता है और धूणा, धानका मरता है तो भी डैड बॉडी होती है। मरने वाले का नाम डैड बॉडी हो जाता है। कितना भी कमा लो चाहे। संपत्ति किसी ने भी कमाई होगी उसका नाम बड़ा नहीं हुआ है। आप यह बता दो, सदन में सभी को कहना चाहता हूं कि आप प्रसिद्ध बनना चाहते हो या लोकप्रिय बनना चाहते हो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जूली साहब से पूछो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जूली साहब तो लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय वह होता है जो

जनता के दिलों में वास करता है और प्रसिद्ध वह होता है जो एक बार टेम्परेरी, किसी भी तरह से होता है। मंत्रियों को यह वहम है कि जनता में जब जाते हैं तो मंत्रियों के चारों तरफ जनता लूम जाती है। जो स्वार्थी तत्व हैं वह आपके भी ऐसे ही घूमते हैं और हमारे वालों के भी ऐसे ही घूमते थे। मेरे पास भी घूमेंगे। लेकिन जब समय आयेगा, आचार संहिता लग जायेगी, उस दिन जब आँख फाड़कर देखोगे तो पीछे कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि वह चले जाते हैं। समय के हिसाब से वह होते हैं। इसलिए आप देख लो, सब बातें आपको बता रहा हूं। नहीं मानो तो मर्जी है। करोगे तो वही जो आप सोच रहे हो। लेकिन बेकार में कोई नहीं रुकेगा। सब काम के लिए रुक रहे हैं। यह जितने भी झंडे दिखाते हैं, जितने भी आपकी वाहवाही लूट रहे हैं, यह सारे के सारे स्वार्थी लोग आ रहे हैं। मजबूत आदमी बहुत कम बचे हैं। अब देखना आप, सब बातें आपको धीरे-धीरे मालूम हो जायेंगी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बोलते रहो श्रवण जी बोलते रहे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह पेंशन वाला ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): जिसको जेल में बंद किया उसको पेंशन कब से हुई, यह तो बताओ।

श्री सभापति: आपस में बातें ना करें सदस्य गण।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं राजस्व विभाग की बात कह रहा हूं। राजस्व विभाग की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्व विभाग में जो सरकार की भूमि है, उस पर लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है और किसी का ध्यान नहीं है। कोई मान लो 200 वर्ग गज में बस जाये, वह तो ठीक है। लेकिन 30-30 बीघा जमीन बो रखी है। तहसीलदार तहसील में नहीं है। एसडीएम तहसीलों में नहीं है। बीडीओ पंचायत समिति में नहीं है। इस सिस्टम को चलाओगे कैसे? सिस्टम तो सिस्टम से चलेगा ना। अब हमारे बुहाना में, सूरजगढ़ में कई महीनों से एसडीएम नहीं है। कई महीनों से तहसीलदार नहीं है। कई महीनों से बीडीओ नहीं है। जब मंत्रियों को कहते हैं तो, हमारी जेब में थोड़े ही है। तो जेब में क्या है? रुपया तो है, कोई 10-20 रुपये तो हैं क्या? वह तो किसी को बांट दो। क्यों नहीं हैं? यह तंत्र आपको चलाना है। हम तो केवल आपको देखेंगे। सारी आंखें बंद करके मत बैठो।

अब आप बताओ, आपने 24 दिसम्बर को अधिसूचना जारी कर दी, जिले हटा दिये और कलेक्टरों को कब हटा रहे हैं, मालूम है, 28 जनवरी को। एक महीने 4 दिन की तनख्वाह कहां से दोगे?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बताओ जोगाराम जी?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बताओ जोगाराम जी? जोगाराम जी, आप इनसे बात बाद में कर लेना। एक ही घर में रहते हो।

श्री सभापति: आप तो बोले जाओ। माननीय सदस्य, आप तो अपना बोलने का जारी

रखें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं कि 24 दिसम्बर को आपने अधिसूचना करके जिले बंद कर दिये। बड़ी खुशी की बात है। आपने कलेक्टरों, एस.पी. को कब हटाया, मालूम है? 28 जनवरी को। एक महीने 4 दिन की तनख्वाह किस हिसाब से आप देंगे? बताओ।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): आप खुश तो हो ना जिले समाप्त करने से?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप इसके अधिकारी नहीं हो, आप अपना काम करो।

श्री सभापति: आप बोलना जारी रखें माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप अपना काम करो। आप जितना आपका दायरा है उतना ही काम करो।

श्री सभापति: आपका समय खत्म होने वाला है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप यह बताओ, किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि बजरी का दोहन हो रहा है। क्या सरकार की आंखें मिंची हुई हैं। पहले वाली सरकार भी कहती थी कि बजरी का दोहन हो रहा है। अब वाले भी कह रहे हैं कि बजरी का दोहन हो रहा है।

श्री सभापति: 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 25 मिनट हैं मेरी, 25 मिनट हैं।

श्री सभापति: आपको 25 मिनट हो गये हैं। आप अपनी बात को समाप्त करें। कन्क्लूड करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी मर्जी आये, हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन 25 मिनट हैं। अब आप बताओ, डेली बजरी की चोरी हो रही है। क्या सरकार की आंखें नहीं हैं? सरकार की आंखें हैं। लेकिन आँख बंद करके बैठ गये। आप बोल लो, खड़े होकर बोलना चाहते हो तो, बताओ। क्या कहना चाहते हो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): काम तो आपके टाइम में क्या हुआ है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं, मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं? मैं इनके गीत गा रहा हूं? मैं यह कह रहा हूं कि क्यों हो रहा है? पेड़ कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं? वन विभाग के मालिक यहां बैठे हैं। आप भी बैठे हो। पेड़ क्यों कट रहे हैं? वह भी हमने ही काटना सिखाया है क्या? बजरी आपके उधर के लोग चोरी कर रहे हैं। आप आंखें बंद करके बैठे हो। बड़े-बड़े अफसरों की मिलीभगत है। आपके नेताओं की मिलीभगत है। चोरी हो जाये क्या? जब शेर के सामने बकरी आ जाये तो पत्ता खायेगी क्या? बकरी के पास शेर बांध दें, पत्ता खायेगी क्या? मींगनी करेगी। लेकिन शेर है ही नहीं कोई। सारे अपना काम करते हैं। मतलब साधा, गन्ना पाड़ा खेत के पार, 5 साल में आप 5 साल में हम।

हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी, हैं नहीं यहां, मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे यहां 12 महीने में 8 ईओ बदल दिये। मेरे ऊपर मुख्य मंत्री जी मेहरबान थे। भले आदमी हैं। 20 करोड़ रुपये 1939 में बनी नगरपालिका के लिए, सीवर लाइन के लिए दिये थे। कोई ईओ ही नहीं बैठा। उसकी ना तो डीपीआर बनी, ना पैसा काम में आया। लेकिन करें क्या? एक ईओ बैठा 15

दिन बाद में उसका ट्रांसफर हो गया। आप नियम तो बनाओ कि एक ईओ कितने दिन रहेगा। एक तहसीलदार कितने दिन रहेगा? जब भी सरकारें आती हैं तो सबको बदल देते हो। छोड़ो, इस सिस्टम को बंद करो। अगर सिस्टम आपने यही रखा तो जो हालत हमारी हुई वही आपकी होगी।

श्री सभापतिः विराजें माननीय सदस्य। श्री केसाराम।

Spp/rtm/03.02.2025/16.20/3a

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और।

श्री सभापतिः बीस मिनट से ज्यादा हो गये। समय हो गया। ...(व्यवधान)... कहां आ रहा है? यह लिख रहे हैं न। आप बिराजें। बिराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसमें समय आ रहा है।

श्री सभापतिः मेरे पास समय लिखा हुआ है। रिकार्डिंग में भी आप चैक कर लें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यहां 25 मिनट लिखा हुआ है।

श्री सभापतिः आप बिराजें। समय हो गया माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सड़कों के ऊपर कोई जाता है...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप बिराजिये। आप रिकार्डिंग देख लेना। आप बैठिये। ..(व्यवधान).. आप भी बैठिये। अंकित नहीं होगा। श्री केसाराम चौधरी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): 000

श्री सभापतिः क्यों व्यर्थ की बातें करते हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, 31 जनवरी, 2025 को इस पवित्र सदन में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से अभिभाषण का वाचन किया गया, उसके लिये हम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। इस अभिभाषण को सुनकर विश्वास हुआ कि देश के प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रीजी की डबल इंजन की सरकारें मिलकर इस राजस्थान को विकसित राजस्थान की तरफ अग्रसर करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आयेगी। राजस्थान में पानी की कमी है, उसके लिये बहुत बड़े-बड़े कार्य होने जा रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में राजस्थान आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की महती योजना साकार रूप लेने जा रही है। ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): श्रवण कुमार जी, प्लीज आप बिराजिए।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से सहकारी संघवाद की अवधारणा सशक्त हुई है और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बन गया है। हमारी सरकार ने युग पुरूष दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा को आत्मसात् किया है। एक वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिये दूरगामी निर्णय किये हैं जिससे माता-बहिनें, युवा, किसान भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 मिलियन डॉलर तक ले जाने की हमारी सरकार का लक्ष्य है जिससे राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो सके। सरकार के इस उद्देश्य में पहले वर्ष राइजिंग राजस्थान, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, सरकार की दूरदर्शी सोच का उदाहरण है। सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में 35 लाख करोड़ निवेश की मजबूत बुनियाद रखी गयी है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के प्रेरणादायी सान्निध्य हमें मिला है। इस सफल वैश्विक समिट में 32 देशों में हिस्सा लिया। 16 देशों ने पार्टनरशिप करके सहभागिता निभायी। 147 देश एवं विदेश के लोग, 32 हजार से अधिक डेलीगेट्स एवं विजिटर्स शामिल हुए हैं। राइजिंग राजस्थान से औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा जिससे युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि बाधाओं को दूर कर नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी जाए। इस उद्देश्य से राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन, 2024, राजस्थान में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, MSME नीति 2024, राजस्थान एकीकृत कलस्टर विकास योजना 2024 लागू की गयी है जिससे चहुंमुखी विकास के लिये राजस्थान प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। राज्य के लिये उद्योगों का योगदान सर्वविदित है। उद्योगों के क्षेत्र में विकास हो इसके लिये भूमि अधिग्रहण के लिये 512 करोड़ से अधिक व्यय किये गये हैं और जमीन अधिग्रहण करके किसानों को मुआवजे के रूप में पैसे दिये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, नये 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गयी है। 1 हजार 282 करोड़ रुपये इसके लिये स्वीकृत किये गये हैं। 11 नये औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन के लिये खोले गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार वादों में नहीं, काम में विश्वास करती है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के लिये पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में पहली बार पूर्वी राजस्थान को सरसब्ज बनाने के लिये महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है। इस योजना को विगत सरकार के समय लटकाया और अटकाया गया था। वसुन्धरा जी की मंशा थी कि यह प्रोजेक्ट उस जमाने में स्वीकृत किया हुआ था तो आज उस स्थिति तक पहुंच सकता था मगर केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने इसको अटकाकर छोड़ दिया था जिससे यह काम ठंडे बस्ते में पडा रहा। जिस योजना के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था उसके अनुसार नदियों को जोड़ने की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा मंशा

रही है कि हम नदियों से नदियों को जोड़ें ताकि राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो सके। राजस्थान का किसान प्रगति कर सके, उसके लिये हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश से समझौता करके राजस्थान का 'राजस्थान' और मध्य प्रदेश का 'म' लेकर 'राम जलसेतु लिंक परियोजना' के नाम से संशोधित पार्वती-कालीसिंध चंबल परियोजना के रूप में मजबूत पहल की है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधान मंत्रीजी के सानिध्य में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स का जयपुर की धरती पर आदान-प्रदान हुआ। इस अवसर पर जीवनदायिनी नदियां के जल को रामजल कलश में प्रवाहित किया गया। परियोजना के साकार होने से किसानों एवं प्रदेश में समृद्धि एवं खुशहाली के नये युग की शुरूआत होगी। पूर्वी राजस्थान में 17 जिलों में 4 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। 3 करोड़ से अधिक आबादी हेतु पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी देवगढ़ और छापली, जो राजसमंद के नजदीक पड़ते हैं, अगर मारवाड़ जंक्शन को भी जोड़ा जाये तो बिना खर्च इस योजना में ग्रेविटी से पानी मारवाड़ जंक्शन पहुंच सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस योजना में मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ा जाएगा ताकि मारवाड़ जंक्शन की पेयजल व्यवस्था सुचारू हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष को किसानों का समृद्धि वर्ष कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस अभिभाषण में किसानों के खेतों में पानी, खाद एवं बिजली तीनों का काम हो रहा है जिससे इस वर्ष को किसान समृद्धि वर्ष कहा जाये तो भी कोई अतिश्योक्ति नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 2 हजार 816 करोड़ खर्च किये गये हैं जिससे 14 हजार 517 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हुई है। भजनलाल जी शर्मा के प्रयास एवं मोदीजी की पहल पर भारत सरकार हरियाणा-राजस्थान के मध्य समझौते के आधार पर यमुना जल लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन लगकर काम करने के लिये हरियाणा सरकार ने भी राजस्थान की सहायता करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। हमारे प्रदेश में खून सस्ता एवं पानी महंगा की कहावत चरितार्थ है। राजस्थान में अगर पानी होता है और पानी अगर आयेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान पूरे भारत को अनाज की पूरी-पूरी सप्लाई दे सकता है। इतनी समतल जमीन है। यही तो सोच थी, इसी को तो आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसीलिए हम चिंता कर रहे हैं और भजनलाल जी की सरकार आते ही यह चिंता की और यमुना जल समझौता किया। मध्य प्रदेश से यह समझौता किया केवल पानी लाने के लिये।

jyg/rtm/03.02.25/16.30/3b

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने तो 65-70 साल राज करके ऐसी चिंता देश की की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। आपने चिंता की ही नहीं। ...(व्यवधान)...

आपके दिमाग में ऐसी सोच थी ही नहीं कि नदियों से भी नदियां जोड़ी जा सकती है। एक तो भगीरथ पुत्र हुआ अटल बिहारी वाजपेयी, उसने सोच पैदा की कि नदियों से नदियां जोड़ी जाये पर आपकी कांग्रेस सरकार ने इसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया, नहीं तो आज राजस्थान सरसब्ज होता। आज के भगीरथ हमारे भजन लाल जी शर्मा हैं, जिन्होंने यह सोच पैदा करके, ये नदियों के समझौते आप नहीं कर सकते थे क्या मगर आपकी सरकारें होते हुए भी ये समझौते नहीं किये।

श्री सभापति: आप विराजिये प्लीज, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)... आप विराजिये। बोलने दीजिये। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। ...(व्यवधान)... आप भी विराजे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसकी वजह से आज हमें यह देखना पड़ रहा है। ...(व्यवधान)... 228 किलोमीटर चम्बल की नहरों की लाइनिंग एवं 5400 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खाळों का निर्माण कार्य किया गया है। आपने तो नहरों के पक्के खाळे बनाने का भी कभी सोचा नहीं।

श्री सभापति: आप भी विराजें। आपका समय पूरा हो गया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अभी कहां साहब?

श्री सभापति: दस मिनट से ऊपर हो गये आपके।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दस मिनट से ऊपर हो गये, अभी तो बोलना शुरू ही किया है।

श्री सभापति: एक मिनट में कन्क्लूड करें अपनी बात।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का महत्व राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। अटल भू योजना, गिरते भूजल की रोकथाम, विभिन्न विभागों द्वारा कंजर्वेशन से 1132 ग्राम पंचायतों में 450 करोड़ रुपये से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कराये जायेंगे। 404 फार्म पोण्ड एवं डिग्गियों के निर्माण से 4339 हैक्टेयर क्षेत्र में पाइप लाइन, ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी किट वितरण एवं मृदा जल संरक्षण के कार्य हुए हैं।

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। श्री प्रताप पुरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो कार्य किये हैं उनकी भी तो सराहना कर दूं।

जल जीवन मिशन का बंटाढार करके रख दिया, अगर आप जांच करवायेंगे तो पाइप कहीं बेच दिये, कहीं पीतल की टूंटियां लगानी थी, एक भी जगह नहीं लगी, आज भी आप जाकर देखिये ...(व्यवधान)... मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं, आप आइये। आकर देखिये। पाइप ही बेच दिये।

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। श्री प्रताप पुरी।

श्री सभापति: बिजली के हालात खराब कर दिये। पांच घण्टे से ज्यादा किसानों को

बिजली नहीं दी, पांच घण्टे से ज्यादा, आज की तारीख में किसानों को छह-साढ़े छह घण्टे बिजली भजन लाल जी दे रहे हैं। प्रदेश में बजरी माफिया पैदा कर दिये। ये आपकी देन है, आज भी बजरी के कारण गुण्डागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है।

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000 ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): जय-जय श्रीराम। ...(व्यवधान)... केसारामजी, राम-रामसा। ...(व्यवधान)... राम-रामसा। राम-राम।

श्री सभापतिः विराजिये माननीय सदस्य, आपका समय हो गया। अच्छा बोले आप। धन्यवाद।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं आसन का, माननीय राज्यपालजी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आभार और धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पूर्व जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में भीषण दुर्घटना हुई एवं प्रयाग संगम तट पर जो विभीषिका हुई, उनमें दिव्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार जनों को भगवान सम्बल दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम तो नये चुनकर यहां आये हैं। निश्चय ही समय सबका अनमोल है। हम लोग कभी-कभी तो बहुत ही गम्भीर विषय उठाते हैं और कभी-कभी उन गम्भीर विषयों को शून्य पर ले जाकर समाप्त कर देते हैं। जब ऐसा लगता है तो केवल राजस्थान की जनता ही नहीं इस मीडिया के माध्यम से पूरा देश और विदेश देखता है कि हमारे राजस्थान का जो गरिमामय इतिहास है उस इतिहास के आज के पृष्ठ में क्योंकि हर व्यक्ति का हर जगह, हर समय इतिहास लिखा जाता है। आज का हमारा भी इतिहास लिखा जायेगा। जिस प्रकार हमारे पुरखों का इतिहास गरिमामय रहा है, मैं आशा रखता हूं कि मेरे से पूर्व कई विद्वान मित्रों ने बहुत सारगर्भित विषय रखकर प्रदेश की उन्नति की चर्चा की और साथ-साथ अच्छे सुझाव भी दिये कि आने वाले समय में क्या किया जाये। मैं इसी आशा के साथ अपनी बात को अभिभाषण के ऊपर ले जाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय को आभार व्यक्त करते हुए इस अभिभाषण के लिये मैं सबसे पहले धन्यवाद यह दूंगा कि नौजवानों के लिये परीक्षा परिणाम आने से पहले ही पेपर लीक हो जाते थे उन पर रोक लगाने का मान्यवर के अभिभाषण में यदि प्रस्तुतीकरण होता है और साथ ही सरकार ने अपनी पारदर्शिता के साथ में इस समय, कल तक जो परीक्षाएं करायीं उनमें पारदर्शिता रखते हुए युवाओं के सपनों को साकार किया उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और समस्त सदन को, बैठे हुए हमारे पक्ष के जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इससे पूर्व इतिहास के पन्नों में, प्रधान मंत्रीजी ने भी अपने

इतिहास के पन्ने स्वर्णमय किये और उन विषम परिस्थितियों के अन्दर देश को एक नई ऊँचाई देकर, विश्व में एक महाशक्ति बनने के लिए भारत को अग्रसर किया है और आज सबके सपने, हमारे क्रांतिकारियों के सपने, हमारे महापुरुषों के सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं कि यह भारत विश्व गुरु बनेगा, सक्षम बनेगा, समृद्ध बनेगा, विकसित बनेगा, उन सपनों को साकार कराने में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि उन्होंने चाहे राम मन्दिर का विषय हो या धारा 370 का विषय हो, चाहे अर्थव्यवस्था से जूझती हुई भारत की इस व्यवस्था को आज विश्व पटल पर लाकर खड़ा किया इसके लिए मैं प्रधान मंत्रीजी को भी इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सक्षम समृद्ध नहीं, देश को भी मजबूत किया है। इसका परिणाम है कि अभी-अभी हरियाणा में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, एक तरफ जनता ने उनको साथ दिया और आशा करता हूं कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के भी पास में है और दिल्ली हमारे सबका हृदय और वो हृदय मोदीजी जीतेंगे, उनके लिए मैं शुभकामना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, निश्चय ही राजस्थान सरकार कदम दर कदम उनके साथ चल रही है और यह सिद्ध कर दिया है कि जब दो ही शक्ति होती है, शक्ति सामर्थ्यवान व्यक्ति और सार्थक व्यक्ति के हाथ में जाती है तो उसका सदुपयोग होता है और शक्ति यदि नकारात्मक भाव के व्यक्ति के हाथ में जाती है तो निश्चय ही दुरुपयोग होता है। उस शक्ति का ही परिणाम है कि आज एक वर्ष के अन्दर राजस्थान की सरकार ने भी अपना इतिहास लिखा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि असम्भव को सम्भव करने की शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया है, आप और आगे बढ़ें।

माननीय सभापति महोदय, शुरू-शुरू में निश्चय ही कुछ विनोद भाव से भजन लाल की भजन मण्डली के नाम से उपहास किया जाता था पर मैं यह कहता हूं कि भजन करके भजन लाल बनना बहुत कठिन है, जिसका भजन तपा, जिसने भजन किया इसलिए उसका नाम भजन लाल भी पड़ा और एक वर्ष के अन्दर उसने भजन का परिणाम भी दिया है।

माननीय सभापति महोदय, पर्ची नहीं यह पर्चा है, यह चमत्कार है कि एक वर्ष के अन्दर उन्होंने राजस्थान की जनता का दिल जीत लिया, इसलिए उप चुनावों के अन्दर उन्होंने परिणाम लाकर दिखा दिया कि एक वर्ष के अन्दर वो कर कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने एक वर्ष के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण को भी बहुत हृदय से लगाकर, क्योंकि सीमांत क्षेत्र का, चाहे राजस्थान का यह कोना हो चाहे वो कोना हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रीजी बनने से पहले पूर्ण रूप भ्रमण किया है जब वो संगठन में थे, एक-एक गांव को, गली को जानते हैं, पूरे प्रदेश का उन्होंने बारीकी से, अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर योजनाएं बनायीं हैं और उनको धरातल पर लाये इसलिए मैं उनका आभार हृदय व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद भी देता हूं कि पहले ही बजट में पोकरण के अन्दर आपने विकास की गंगा बहायी

और वो अभी चरितार्थ हो रही है इसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। चूंकि पोकरण ही नहीं, जब मैं यह कह रहा हूं पूरे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कदम उठाये हैं वो सराहनीय और प्रशंसनीय है और जनता अब विश्वास के साथ तय कर चुकी है कि आपका भविष्य उज्ज्वल होगा और आने वाले समय में राजस्थान में अपरिवर्तित सरकार बनकर पुनः आपके हाथों में नेतृत्व होगा, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं।

MLS/RTM/03.02.2025/16:40/3c

आपकी योजना के अन्तर्गत पोकरण में आपने जो काम किया, उसमें सबसे ज्यादा पुण्य का काम किया आपने गोमाता की सेवा करने का। जो रजिस्टर्ड गोशालाएं हैं, उनमें आपने 10 प्रतिशत वृद्धि की है, परन्तु मैं आशा के साथ कहता हूं, सन्यासी के नाते कहता हूं, अधिकारपूर्वक कहता हूं, राजस्थान गो आधारित नहीं, बल्कि गो हमारी माता है और पूजनीय भी है। गाय का संरक्षण और संवर्द्धन करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को और ज्यादा कुछ करना है और हम सब लोग आशा रखते हैं, पूरे राजस्थान की जनता आशा रखती है कि आने वाले समय में गोशालाओं में निराश्रित और बुड्ढी-बुजुर्ग गायों के लिए और अच्छी योजना बनाकर हमारे सामने लाने की मंशा रखेंगे।

वर्तमान सरकार ने पानी को लेकर भी खूब काम किया। अभी-अभी तर्क-वितर्क, मैं यह तो नहीं समझ पाया कि वाद और विवाद क्यों किया जाता है, इसमें यह नाम भी क्यों रखा गया है वाद-विवाद। काहे का वाद-विवाद, यहां तो विकास की बात हो रही है। जब जल जीवन मिशन के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने एक सपना देखा, ''घर-घर नल'' और पिछले समय में क्या हुआ, मैं अपने शब्दों से कहूंगा तो हो सकता है, किसी की आत्मा को ठेस लगे, जब सचिवालय के अन्दर पैसे मिलें या इतना भ्रष्टाचार हो कि उसको इतना लम्बित किया जाये कि हमारे प्रधान मंत्री के सपने, हमारी जनता के सपने चूर-चूर हो जाएं तो यह अच्छा नहीं लगा, परन्तु मैं आशा रखता हूं कि आने वाले समय में जो समय बढ़ा है, उस समय के अन्दर जल जीवन मिशन से पूरे राजस्थान की जनता के घर-घर नल पहुंचेगा और निश्चय ही यह कार्य सफल होगा, इसके लिए भी मैं शुभकामना करता हूं।

साथ ही साथ, नहरी परियोजना में भी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत हमारी सरकार ने जोधपुर फलोदी जल मिशन में इतना अच्छा काम किया है, 927 करोड़ रुपये व्यय करके 592 गांवों को लाभान्वित किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, परन्तु इसको बढ़ाकर पोकरण विधान सभा में साकड़ा, फलसूंड तक यदि योजना बनायी जाये तो रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि पानी की यदि कमी नहीं है तो जमीन की हमारे पास भी कोई कमी नहीं है, इसलिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यदि सिंचाई केलिए पानी दिया जाये तो उपजाऊ जमीन के साथ हम अन्नदाता पूरे देश को अन्न दे सकते हैं, ऐसी हमारी उपजाऊ जमीन है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने

1 लाख 10 हजार से अधिक कनेक्शंस दिये। 5 सालों में लाइट के लिए घरेलू कनेक्शंस दिये गये, फिर भी कृषि कनेक्शंस की अभी भी बहुत मांग है, जिसकी मैं आशा रखता हूं, क्योंकि सपना है 2027 तक विद्युतीकरण पूरे प्रदेश में होगा। इस सपने को भी साकार करने में हमारी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाओं को लाकर दूरगामी राजस्थान का एक स्वर्णिम नक्शा बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और वर्तमान सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

हमारे देवालय, धार्मिक स्थान, उनको भी पूरे ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने पूरे देश में प्रत्येक धार्मिक स्थान को ऐतिहासिक बनाया है, विश्व पटल पर लाया है, ठीक ऐसे ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मेरे क्षेत्र में रामदेवरा है, तनोट है, तेमड़ा है, इन सबके विकास के लिए भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया है। सबसे गम्भीर विषय कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके सराहनीय कार्य किया है। किसानों की जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, राजस्व रिकॉर्ड प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं।

मैं सरकार का एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में विशेषकर, जमीन, नदी, नाले, तालाब, गोचर, ओरण रिकॉर्ड में नहीं हैं, जबकि पुरखों ने इसके लिए इन्हें छोड़ा था। मैं आशा रखता हूं, यह सरकार बहुत अन्तर्मन से गो के लिए, किसान के लिए सोच रही है, इसलिए जो हमारे पुरखों ने ओरण यानी ओण यानी सौगन्ध है इस देवता की, इस जगह का कोई पेड़ या दातुन भी नहीं तोड़ेंगे, उन ओरणों को, उन गोचरों को, जो गायों के लिए छोड़े हैं, जो तालाब-सरोवर हैं, उनको जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, मैं आशा रखता हूं माननीय मंत्री जी से कि उनको शिघ्रातिशीघ्र रिकॉर्ड में दर्ज कराएं।

इसके साथ एक और विशेष बात कहूंगा, कम्पनियां हमारे क्षेत्र में आएं, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि विकास हमारी एक बहुत बड़ी धुरी है। प्रदेश की ही नहीं, देश की धुरी है। विश्व के सामने हमें दिखाना है कि भारत सक्षम और समृद्ध हुआ है, परन्तु आने वाले समय में कम्पनियों को वह जमीन दें] जो अनुपयोगी टाइप की हैं। सौ साल बाद यदि वहां का किसान जमीन चाहेगा तो कौन-सी जमीन आप उस समय देंगे, क्योंकि यह सम्पत्ति हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की है। गोचर, ओरण, तालाब, नाड़ी एवं उपजाऊ जमीन पर न लगाकर अन्य जितनी जमीनें हैं, उन पर आप विकास के कार्य कराएं और आने वाली पीढी के लिए हमारी उपजाऊ जमीन को आरक्षित करें।

श्री सभापति: विराजें साहब, प्लीज। श्री विकास चौधरी।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): इसलिए मैं इतना ही कहते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आशीर्वाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़):

वाणी में दर्द और गुस्सा लेकर आया हूं,
एक साल बेहाल राजस्थान की आवाज बनकर आया हूं,
एक साल बेहाल राजस्थान की आवाज बनकर आया हूं।।

सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के अवसर पर मुझ नौजवान को बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं नेता प्रतिपक्ष महोदय और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कि पहले ही दिन मुझ नौजवान को बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं शुरुआत करूंगा प्रथम पेज के बिन्दु संख्या 2 से। राज्यपाल महोदय ने बड़ी आत्मीयता से हम समस्त 200 विधायकों से कहा कि प्रत्येक सदस्य के मन-मस्तिष्क के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना आवश्यक होगी। आज मैं उसी भावना के अनुरूप अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, 16वीं विधान सभा का यह तीसरा सत्र है। पक्ष के साथियों का लगातार हमने तीसरी बार उद्बोधन सुना। इनके उद्बोधन और इस सरकार के क्रिया-कलापों से यह प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार केवल और केवल जनता को गुमराह करने और पूर्ववर्ती सरकार को कोसने का काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं खुली बात कहूंगा कि योजनाओं के नाम बदलने से या सदन का रंग बदलने से इस राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। इस राजस्थान का भला तब होगा, जब जवान और किसान की आवाज सुनी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न विजडम है। आज प्रदेश के किसानों के हालात, युवाओं की विवशता और महिलाओं की असुरक्षा को देखकर मन द्रवित होता है। ''महिलाओं पर अत्याचार, नहीं सहेगा राजस्थान'' का नारा देने वाले सत्तापक्ष में बैठे इन लोगों के राज में जनवरी 2014 से अगस्त 2024 तक 3989 प्रकरण बलात्कार के दर्ज हुए हैं। रोजाना 16-17 बहन-बेटियों की अस्मिता के साथ इस प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, क्या सत्तापक्ष में बैठे भाजपा के लोगों का यही महिला सशक्तीकरण है? सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिन्दु 7 पर लिखा है कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 45 लाख करोड़ रुपये के एमओयूज साइन हुए हैं ...(व्यवधान)... 35 लाख करोड़ रुपये, ज्यादा हों तो और बता देना, क्योंकि आंकड़े वैसे ही हवा-हवाई हैं। मैं उस मार्बल नगरी से आता हूं, जिस मार्बल नगरी ने इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी दी है। माननीय सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान के नाम पर कागज का एक नकली नोट जनता को दिया गया है। मुझे याद है, बचपन में वह नकली नोट किराने की दुकान पर चूरण के साथ दिया जाता था। माननीय सभापति महोदय, यदि एमओयूज धरातल पर हैं तो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा की ईओआई कैंसल क्यों हुई? यदि नहीं होती तो 20 हजार नौजवानों को रोजगार मिलता।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास न कोई रोडमैप है, न ही निवेश कब, कहां और कैसे होगा, उसका विजन है। पूरे प्रदेश की जनता में एक माहौल बन गया है कि यह निवेश के नाम पर केवल जमीन हड़पने का और भ्रष्टाचार करने का एक ताण्डव भाजपा की सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरे सर पर जो यह पगड़ी है, वह इस राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की देन है। यह पगड़ी किसानों की आन, बान और शान भी है और किसानों से जिस प्रकार के वादे इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले किये, ये सत्तापक्ष के साथी कैसे भूल सकते हैं कि राज्यपाल महोदय ने पेज संख्या 18-19 में किसान सम्मान निधि की बात कही थी, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपये किया जायेगा, आपने किया क्या? आपे आपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि बाजरे और ज्वार को एमएसपी पर खरीदा जायेगा, आपने खरीदा क्या?

mkd/rtm/03.02.2025/16:50/3d

सभापति महोदय, आज किसान के पास न बिजली है, न बीज है, न पानी है, न उसकी फसल की एमएसपी पर खरीद हो रही है। वादे करते हैं 2047 में विकसित भारत का, वादा भूल गये, देश के प्रधान मंत्री ने कहा था कि 2022 में किसान की पूरे देश और प्रदेश के किसानों की आय दोगुना किया जायेगा, आपके किसानों की आय को दोगुना करने के वादे का क्या हुआ? आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं उस वर्ग आता हूं, जो मेहनत करता है, वह किसान वर्ग जो आज खून के आंसू रो रहा है और मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं कि किसान का एक-एक आंसू, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आखिरी ताबूत पर कील ठोंकने का काम किसान कर रहे हैं और वह जल्द ही आपके सामने आ जायेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं नौजवान हूं, अपनी भावनाओं को यहां प्रकट करने आया हूं। दो करोड़ प्रतिवर्ष नौजवान को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? नौजवानों को अग्निवीर बनाकर इस सरकार ने छोड़ दिया, डबल इंजन की सरकार कहती थी कि हमारी सरकार आयेगी तो आरपीएसी को भंग कर देंगे, आरपीएससी को भंग करने के वादे का क्या हुआ?

आदरणीय सभापति महोदय, नौजवान रोजगार मांग रहा है और नौजवानों को ये ड्रग्स दे रहे हैं। ड्रग्स कहां से आ रहा है? एमडी नाम का जो ड्रग्स आ रहा है, वह गुजरात से आ रहा है, उसका रसायन, गुजरात के लोगों को हमने देश की सत्ता दे दी, इन गुजरातियों को हमने देश की अर्थव्यवस्था दे दी और अब वह एमडी नाम का नशा हमारे नौजवानों की खून की नसों में दौड़ा रहे हैं, इसका हिसाब आने वाले समय में राजस्थान करेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मुझे धूमिल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, एक व्यक्ति होता है, जो रोटी बेलता है। दूसरा व्यक्ति होता है, जो रोटी खाता है और तीसरा व्यक्ति होता है, जो ना रोटी बेलता है, ना रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है और यह भाजपा की

सरकार भी नौजवानों और किसानों की रोटी के साथ खेलने का काम कर रही है। जनता पूछती है कि वह तीसरा आदमी कौन है, डबल इंजन की सरकार आखिर क्यों मौन है? क्यों मौन है?

आदरणीय सभापति महोदय, एक साल से भजन लाल सरकार आठ करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उनके सपनों पर भार बन चुकी है। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह भजन लाल सरकार नहीं है, यह इस प्रदेश पर वज़न लाल सरकार है, यह प्रदेश पर भार है, यह भजन लाल सरकार युवाओं के भविष्य पर वज़न है, यह भजनलाल सरकार किसानों की समृद्धि पर वज़न है, यह भजनलाल सरकार बहन, बेटियों की सुरक्षा पर वज़न है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से अफसरशाही हावी हो रही है, इस प्रदेश में जिस प्रकार से माफियाओं का राज हो रहा है और दर्द तब होता है, आज एक नौजवान की भावनाएं उमड़ रही हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, इस सीट पर जब किरोड़ी लाल जी मीणा बैठे थे और मैं शपथ ले रहा था और माइक चालू था, किरोड़ी लाल जी ने खड़े होकर हाथ मिलाया, मुझे कहा विकास कोई काम हो तो आधी रात को बताना, पर दर्द होता है कि एक मेहनत करने वाले आदिवासी नेता को, दलित नेता को इस प्रकार से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। उसी की सरकार, उसी सरकार से कहना पड़ता है कि यह सरकार मुझे अपमानित कर रही है, वह किरोड़ी लाल जी मीणा, मैं पहले उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और कहना चाहता हूं उन किरोड़ी लाल मीणा जी को 2018 से 2023 में ''नहीं सहेगा राजस्थान'' का झंडा आपने पकड़ाया और सर्दी में ठिठुरे किरोड़ी लाल, जेल जाये किरोड़ी लाल, जेल जाये किरोड़ी लाल और माल खाये भजन लाल, मलाई खाये भजन लाल, कैसे चले इस प्रदेश में, इस प्रदेश की इस प्रकार की हालत करने का जो जिम्मेदार है, वह आदरणीय (..व्यवधान.).

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इसको डिलीट किया जाये। यह बदतमीजी वाली बात है। आप थोड़ी तो मर्यादा रखिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मेहनत किसी की?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर ही अपनी बात कहें और इधर-उधर जो अनावश्यक है, उसको हटाया जाये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ये अचानक किरोड़ी लाल जी पर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है, आपको। जेल भेजने वाले आप थे। किरोड़ी लाल जी को जेल भेजने वाले आप थे।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): यह आपके कमजोर नेतृत्व का परिणाम है कि एक नौजवान की आवाज को दबाने के लिए ये वरिष्ठ भाजपाई खड़े हो गये हैं, लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है। यह पीड़ा है एक नौजवान की, जो नौजवान बड़ी मुश्किल से सड़क पर लड़कर इस सदन में आया है और आपके द्वारा यह आवाज रुकने वाली नहीं है।

आदरणीय सभापति महोदय, इस कमजोर नेतृत्व का प्रमाण है कि राजस्थान राइजिंग

होने नहीं जा रहा है, राजस्थान होलिंग राजस्थान बनने जा रहा है, फिर से बीमारू प्रदेश बनने जा रहा है। जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी से पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने निकाला था, कांग्रेस के राज में बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकला।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एनसीबी की एक रिपोर्ट लेकर आया हूं। एनसीबी की रिपोर्ट है, ड्रग्स के मामले में राजस्थान देश में तीसरे नम्बर पर है, हरियाणा और पंजाब के बाद नौजवानों की नसों में खून में ये एमडी देने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, न बुजुर्गों को पेंशन ये दे रहे है, ये न विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, न विकलांगों को ये पेंशन दे रहे हैं और इनकी कथनी और करनी की जो बात है, ये लोग एससी, एसटी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आज उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम भी यह सरकार नहीं कर रही है। इसलिए यह पूरा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजनीति से ओत-प्रोत है। इस अभिभाषण का न कोई विजन है, न कोई इसका कोई महत्व है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं किशनगढ़ नगरी से आता है। किशनगढ़ में सम्भाग का दूसरे नम्बर का बड़ा हॉस्पिटल है, आज उस हॉस्पिटल में चिकित्सा मंत्री की बात नहीं मानी जा रही है। हमारे वहां रेडियालॉजिस्ट नहीं है, वर्षों से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आपने लगाया, लेकिन सरकार के मंत्री की अवहेलना भी उन अफसरशाही लोगों ने की है। वीडियो वायरल हो रहे हैं बजरी के, बजरी माफिया हावी हो गये हैं, शराब माफिया हावी हो गये हैं और जिस प्रकार से तांडव अजमेर जिले में है, मैं अजमेर जिले में विपक्ष का एकमात्र विधायक हूं और वहां के मंत्री और लोग कहते हैं कि हम +++ हैं, जितना लूटना है इस किशनगढ़ को, अजमेर को उतना लूट लो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर ही बात करिये। आप बजट पर ही बात करिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): जिस प्रकार का तांडव, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का तांडव अजमेर जिले में बना दिया है, अजमेर में पूरा भाजपा (..व्यवधान..)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अभी पता लग जायेगा। माननीय, या तो इसको प्रूफ कीजिये या डिलीट कीजिये, नहीं तो हम लगाते हैं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, +++ कौन हैं?

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): जनता देगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विधान सभा में जवाब देना पड़ेगा, लाइये विधान सभा में जवाब।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): हम कह रहे हैं। यह काम हो रहा है (..व्यवधान..)।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लाइये विधान सभा में जवाब, पटल पर लाइये, अभी मैं लाता हूं प्रस्ताव। अभी प्रस्ताव लाता हूं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): (..व्यवधान..) इस बाड़ को उखाड़ फेंकने का काम आने वाले समय में (..व्यवधान..)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): +++ मैं लाता हूं प्रस्ताव। ऐसे आपके कहने से होगा क्या?

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आपको रोकना है तो (..व्यवधान..)।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके कहने से क्या होगा (..व्यवधान..)।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आपको रोकना है तो शराब की जो दुकानें रात को खुली हैं (..व्यवधान..)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको जवाब देना पड़ेगा, +++ का जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो देख लेना।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आपको रोकना है तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकिये(..व्यवधान..)। रोकना है तो उन नौजवानों को जो सुसाइड कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): +++ का नाम बोलो, नाम बोलो +++ का।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): इसलिए यह पूरी तरह फेलियर सरकार है (..व्यवधान..)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, या तो डिलीट करवाये या प्रूफ लायें।

श्री सभापति: विराजिये। श्री महेन्द्रपाल मीणा। यह डिलीट किया जाये, जो बीच में गलत बोली है बात।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): एक साल में जनता ने आयना दिखा दिया। शिक्षा मंत्री जो एक बच्ची को पूछ रहा है, टेंथ और दसवीं क्या है। ऐसा शिक्षा मंत्री यदि इस प्रदेश के शासन में बैठा है तो इससे बुरा कुछ होने वाला नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री महेन्द्रपाल मीणा। आप कन्क्लूड करें।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): यह आवाज उस नौजवान की है, जो नौजवान सड़क पर लड़ता है, भिड़ता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, इसलिए ये लोग उस आवाज को दबाने का काम ज्यादा दिन तक करने वाले नहीं हैं। मैं इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की, जो राजनीति से ओत-प्रोत है, मैं निन्दा करता हूं।

जारी...

Bhs/Rtm/03.02.25/17.00/3e

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया।

सर्वप्रथम, लोकतंत्र के पवित्र मन्दिर में बैठे सभी माननीय सदस्यों का अभिवादन और सम्मान प्रकट करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है हम सब मिल कर अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कन्धे से कन्धा मिला कर गरीब को गणेश मान कर काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान के रचयिता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया वह हमें समानता का, न्याय का और विश्वास का संविधान दिया। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, विगत कई वर्षों से हमारे देश में यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने अद्भुत प्रगति और विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और वर्तमान में बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर हमारा देश सामने आया है। हमारे देश की कमान मजबूत हाथों में होने के फलस्वरूप भारत ने वर्तमान में बेहतर भविष्य को चुनौती देते हुए स्वयं को तैयार किया।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री और विकास पुरुष के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 350 मिलियन डालर तक ले जाने का लक्ष्य हमारे मुख्य मंत्री जी ने रखा है इसका उदाहरण राइजिंग राजस्थान सफल होना अपने आप में कारगर साबित हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन प्रदेश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास को नयी दिशा और गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं इस राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन और राजस्थान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी और राजस्थान के भागीरथ के रूप में राजस्थान के विकास को चार चांद लगाने वाले मुख्य मंत्री जी के लिए चार पंक्ति बोलना चाहूंगा कि 'कुछ ख्वाब अभी अधूरे हैं, कुछ अरमान अभी बाकी हैं, राहों में हैं मुश्किलें मगर कदमों में जान अभी बाकी है। हौंसलों की उड़ान कम नहीं होगी, सपनों का आसमान अभी बाकी है। थक कर कैसे बैठ जाऊं मैं मेरे राजस्थान के विकास की अभी कहानी बाकी है।'

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास पुरुष के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो वादे किये वो वादे ही नहीं बल्कि उन कामों को जमीन पर उतारने का काम किया है। इसका उदाहरण है ई.आर.सी.पी.। ई.आर.सी.पी. आज रामसेतु लिंक परियोजना के नाम से हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो रखा है, हमारी पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में

जो सरकार ने पहली बार इस महत्वाकांक्षी विजन को प्रस्तुत किया था लेकिन दुर्भाग्य है कि विगत सरकार ने अपने स्वार्थों के कारण एवं अदूरदर्शिता के कारण ऐसी महत्वपूर्ण योजना को लटकाया, भटकाया और तेरह जिलों के पेयजल और सिंचाई के सपने को साकार होने से रोका परन्तु मुझे सदन में यह कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों और राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए उस सपने को साकार किया और जिसमें पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों की चार लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और तीन करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के ई.आर.सी.पी. के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा।

मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को कि जमुआरामगढ़ का बांध जो जयपुर की आत्मा है जो जयपुर की लाइफ लाइन है उस जमवारामगढ़ बांध को ई.आर.सी.पी. के फर्स्ट फेज में जोड़ कर एक भागीरथी प्रयास किया और जमवारामगढ़ बांध जिसमें 1982 में एशियाड खेल हुए थे, उसके भरने से सम्पूर्ण जयपुर वासी राजस्थान की राजधानी को और लाखों जयपुरवासियों को लाभ मिलेगा और यह जयपुर राजस्थान की राजधानी की आत्मा में जो रामगढ़ बसा है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई का किसानों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकार का प्रयास हर ढाणी और गांव में लोगों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का है। माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री द्वारा चलाये गये जल जीवन मिशन को गत कांग्रेस सरकार में हर घर तक नल द्वारा पानी पहुंचाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था परन्तु दुर्भाग्य है कि गत सरकार ने इसमें अपना समय गंवाया और इसमें घोटाले किये जिससे पूरे देश, पूरे प्रदेश में राजस्थान की बदनामी हुई इस कारण यह योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी, जिससे गांव और ढाणियों में पेयजल संकट संकट बना हुआ है। अब हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है और घर-घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम यह राजस्थान की भजन लाल सरकार करके दिखायेगी।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाओं के बारे में तो आप भलीभांति वाकिफ हैं। गत सरकार में हुई पेपर लीक की घटनाओं से नौजवानों के सपने चकनाचूर हुए, उनके साथ विश्वासघात हुआ। नौजवानों का परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ गया। उस समय 17-17 बार पेपर आउट हुए लेकिन सभापति महादय, मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कठोर निर्णय लेकर पेपर लीक और नकलचियों पर ऐसा अंकुश लगाया कि वर्तमान सरकार में आयोजित एक भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए जिससे कोई भी परीक्षा स्थगित नहीं हुई और प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग सौ एफ.आई.आर. में लगभग 260 लोगों को गिरफ्तार किया। हमारी सरकार सख्त निर्णय की वजह से युवाओं के भविष्य पर खरी उतरी है।

माननीय सभापति महोदय, गत सरकार में न तो समय पर भर्ती परीक्षा आयोजित होती

थी और न ही चयनित युवाओं को नियुक्ति दी जाती थी जिससे कठिन परिश्रम करने वाले युवा हताश और निराश हो गये। हमारे राजस्थान की भजन लाल सरकार ने 2025 में 81 हजार पदों पर होने वाली भर्ती का परीक्षा कलेण्डर जारी कर दिया है और ठोस इरादों के साथ यह साबित किया है कि हम युवाओं के सपनों को पंख लगायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पांच वर्ष में चार लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है और अब तक एक लाख बहत्तर हजार नौ सौ नब्बे पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है और हमारी सरकार कहती है कि हम कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं करते। यही भजन लाल सरकार के विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने तीस लाख किसानों को खेतीबाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग सोलह हजार करोड़ ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया। पी.एम. सम्मान निधि योजना माननीय प्रधान मंत्री जी की अनूठी पहल है, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने भी किसानों के कल्याण को देखते हुए इस योजना के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जारी की, जिसमें किसानों को दो हजार रुपये अतिरिक्त दिये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, खेती के साथ-साथ किसान भाई पशुपालन पर निर्भर हैं, इसलिये हमारी सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जिसमें चौबीस हजार से अधिक परिवारों को एक लाख रुपये प्रति परिवार ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालकों की सबसे बड़ी पूंजी उसका पशुधन होता है इसलिये हमारी भजन लाल सरकार ने पशुओं को सम्बल देने के लिए चार सौ करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना शुरू की जिससे हमारे किसानों को और पशुपालकों को लाभ मिला।

अन्त में, मैं अपनी यह लाइन बोल कर विराम देना चाहूंगा। 'अभी तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है, अभी तो चले हैं एक नयी मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना ही था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।' धन्यवाद। जय श्री राम। राम-राम।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं विश्व वन्दनीय महाराणा प्रताप एवं उनके अनन्य सहयोगी भील राणा पूंजा की पावन धरती से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मेरी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अभिभाषण के दौरान जब सदन के एक माननीय सदस्य ने टोका-टोकी की कि आप जिले में जाकर बैठकें कर रहे हो तो राज्यपाल महोदय ने कहा था कि जनजाति हितों से

जुड़ी समिति मेरे विभाग में आती है और उसकी बैठक करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मैं हर जिले में जाऊंगा और वहां बैठक करूंगा। राज्यपाल महोदय ने जनजाति वर्ग के प्रति जिस जिम्मेदारी की बात कही है उससे माननीय सदस्य समझ गये होंगे जिन्होंने सरकार में रहते हुए जिम्मेदारियों को नहीं निभाया।

Kas/rtm/03.02.2025/17.10/3f

सभापति महोदय, जनजाति विभाग ने हमारे जनजाति परिवारों के लिये इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया और राज्यपाल महोदय कुछ करने की इच्छा करते हैं तो उसके ऊपर महामहिम महोदय के भाषण में टोका-टोकी करके यह क्या साबित करना चाहते हैं? आदिवासियों का भला करना चाहते हैं या उनको गर्त में डालना चाहते हैं? इससे साबित होता है कि उनकी मानसिकता क्या है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में मैं अपने विचार कविता के रूप में रख रहा हूं। भगवान कांग्रेस का भला कभी नहीं करेंगे, जिन्होंने नई पीढ़ी का हक मारा है। पेपर लीक करा करा कर किया पैसों का बटवारा है, करो घोटाले और लूट खाओ, इस कांग्रेस का भला भगवान कभी नहीं करेगा, जिन्होंने गरीबों का हक मारा है। भला हो हमारे भजन लाल जी का जिन्होंने 100 एफ.आई.आर. दर्ज करा कर लुटेरों को जेल तक पहुंचाया है। बाकी वो भी थरथर कांप रहे हैं, जिन्होंने नकल करा करा कर जिम्मेदारों को पास कराया है। इनके पाप का घड़ा भर आया, तब जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया।

सभापति महोदय, इनकों जनता ने वास्वत में वह सबक सिखाया है कि इनको सम्पट ही नहीं रहा। पांच साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया और चार साल बाद रेवड़ियां बाटने के बारे में जनता समझ चुकी थी कि इन्होंने चार साल कुछ नहीं किया, सत्ता में आने के लिये रेवड़ियां बांट रहे हैं।

जल जीवन मिशन की क्या बात करूं, कांग्रेस राज में घोटालों की कुछ ऐसी करामात हुई नल से जल तो निकला नहीं, पर जमकर धन की बरसात हुई। भजन लाल जी की भावना का मैं करता हूं सम्मान, घर-घर जल पहुंचा कर दिया जनता को वरदान। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। मेरी विधान सभा में शक्ल देख कर तिलक लगाते थे कि यहां पर हमारी पंचायत है, वहां पर वो काम नहीं करते थे और जहां वोट मिलते थे, वहां पर उन्होंने काम करवाया। लेकिन सरकार के इस असत्य वादे को जनता समझ चुकी थी और 2023 में इनको डेढ़ गुना वोटों से हरा कर बता दिया। कोयले की कमी बता कर कांग्रेस ने जनता को अंधेरे में सुलाया था। गांव, गरीब और किसानों को खूब सताया था। इसलिए जनता ने कांग्रेस को रसातल में पहुंचाया था। एक साल में भजन लाल सरकार ने नौकरियों की गंगा बहाई। 60 हजार बेरोजगारों को नौकरियां दिलाईं, पौने दो लाख की भर्ती जारी है, पांच साल में 4 लाख की इच्छा शक्ति दिखाई है।

सभापति महोदय, अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि पूर्व में इनकी सरकार ने हमारे

उद्योगों को बंद करने का मानस बनाया। हमारे राजस्थान में आधे से ज्यादा उद्योग बंद हो गये और हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। हमारे राजस्थान का क्रूड दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और जो राजस्थान में उनकी रॉयल्टी कट रही है, वही दूसरे प्रदेश में जा रही है। उसमें भी वही रॉयल्टी होने की वजह से, कच्चा माल दूसरे प्रदेशों में जाने से हमारा ग्रेडिंग यूनिट जो वास्तव में उद्योग है, कच्चे माल को पीस कर बेचते थे, उनकी रॉयल्टी बराबर होने की वजह से दूसरे प्रदेशों में कच्चा माल ले जाकर वहां ग्रेडिंग करवाने से हमारे हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं और उद्योगपतियों ने अपना कनेक्शन कटवा दिया और आधे से ज्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं। मैं हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी से और हमारी सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस जो राजस्थान में रॉयल्टी कट रही है, उससे चार गुना या पांच गुना दूसरे प्रदेश में अगर जाता है तो उसकी रॉयल्टी बढ़ाकर हमारे यहां पर राजस्व भी एकत्रित करें और हमारे उद्योगों को चलाने के लिये भी आपकी सहमति हो। पूर्व सरकार ने जो किया उससे हमारी आम जनता को वास्तव में राहत मिलेगी, यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हमारे मंत्री महोदय इस पर गहनता से छानबीन करके हमारे यहां के उद्योगों को बढ़ावा दें।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में पंचायती राज में शिक्षा को लागू किया था कि हमारा जनप्रतिनिधि शिक्षित हो ताकि यह घोटाले नहीं हों। कांग्रेस का घोटाला बंद हो गया, इन्होंने शिक्षा स्तर को खतम कर दिया और वापस अनपढ़, अंगूठा छाप, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो और चाहे जिला प्रमुख हो, उनको इन्होंने मान्यता दे दी। इससे इनका मंतव्य स्पष्ट जाहिर होता है और इन्होंने शिक्षा स्तर को ही खतम कर दिया। यहीं नहीं, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिये अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिये। वह खोल तो दिये लेकिन उनमें अध्यापक क्यों नहीं लगाये और वहां के हिन्दी मीडियम के छात्र कहां जायेंगे, इसके बारे में सोचा ही नहीं। हमारे आदिवासी ऐरिया में हिन्दी मीडियम वाले बच्चे भटकते फिरे और मैं यहां पर गिड़गिड़ाता रहा कि हमारे वहां के बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, 10-10 किलोमीटर दूर जाने के लिये उनके पास किराया नहीं है, आने-जाने का साधन नहीं है, किसी ने नहीं सुना। मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर ध्यान देते हुए हमारे हिन्दी मीडियम वाले छात्र-छात्राओं के बारे में भी सोच कर उनके साथ न्याय किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे घुमंतू, अर्ध घुमंतू, गाडिया लोहार एवं कालबेलिया समुदाय के लोगों को 609 भू-खण्ड देकर और उनको पट्टा देकर स्थापित करने का अगर किसी ने काम किया तो वह हमारे माननीय भजन लाल जी की सरकार ने किया। इसके अलावा जोधपुर में 78 पाक विस्थापित परिवारों को पट्टा देकर उनको भी राहत देने का काम किया तो वह भजन लाल जी की सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने इनके बारे में भी कभी नहीं सोचा।

आज बिजली की बात करें तो पूर्व सरकार में लोग हमको रात को सोने नहीं देते थे,

कहते थे कि हमारे यहां लाइट चली गई। किसान रात में पाणत करते हैं, जंगली जानवर उन पर हमला करते हैं। आज दिन तक हमारे पास एक भी भाई का फोन नहीं आया कि हमारे रात में बिजली आ रही है। इस बारे में भी हमारी सरकार ने सोचा। यही नहीं खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोलकर जो लोग वर्षों से खाद्य से वंचित थे, उनका भी सरकार ने ध्यान रख कर और जो हमारे आदिवासी लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको भी वास्तव में राहत देने का काम किया तो वह हमारे भजल लाल जी ने किया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने भेदभाव किया और डीएमएफटी फंड का पैसा जहां इनके विधायक थे वहां पर लगा दिया और जहां हमारे विधायक थे, वहां एक पैसा नहीं दिया। हमने कहा कि हमारे स्कूलों के जर्जर भवन पड़े हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग तक के पैसे नहीं दिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये हमारे जर्जर भवनों की रिपेयरिंग के लिये दिये।

Msk/rtm/03.02.25/1720/3g

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समय हो गया है, बैठिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं एक मिनट के लिए आपको बता चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हम सब कुछ करते हैं।

श्री सभापतिः आपके साढ़े ग्यारह मिनट हो गये हैं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): किसानों के लिए पिछली सरकार में पांच साल के अन्दर 19 हजार किसानों की जमीन नीलाम की, वह क्यों की? कांग्रेस सरकार के वक्ता बतायें कि 19 हजार लोगों की जमीन नीलाम कैसे की? सभापति महोदय, समय का अभाव है। आपने बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. शिखा मील बराला।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, आपका आभार कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे खुशी है कि इस अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को काफी बार याद किया गया और करना बनता भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार दे गयी, जिसके आगे आपके लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता है, आप सिर्फ नाम बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री का कई बार नाम मेंशन किया गया। थोड़ा-सा दुःख इसी बात का है कि जो हमारे मुख्य मंत्री महोदय हैं, काफी सज्जन एवं मेहनती व्यक्ति हैं, एक वाक्य तो उनकी तारीफ में लिखा जाता। युवाओं के प्रतिनिधित्व को देखकर खुशी हुई, राज्यपाल महोदय ने ऐसा कहा, पर आपकी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए क्या कर रही है? सिर्फ लुभावने, खोखले नौकरी के वादे दे रही है, पुरानी

विज्ञप्तियों पर नियुक्तियां दे रही है। आप जवाब दे सकते हैं कि मौजूदा सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार आखिर की स्टेजेज में छोड़कर गयी थी।

युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा विधान सभा क्षेत्र यहां से 30-35 किलोमीटर दूर है। पिछले एक साल में, जो क्षेत्र बहुत शांत कहा जाता था, वहां के युवा नशे, गुण्डागर्दी, साइबर क्राइम, मनी लॉड्रिंग की गिरफ्त में आ गये हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पॉक्सो के केसेज बढ़ रहे हैं। यह गृह विभाग की एक बड़ी विफलता दर्शाता है। राजनीतिक दबाव में निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं। धारा 151 में एकतरफा कार्यवाही की जा रही है। बहुत सारे प्रशासनिक और पुलिस कर्मचारी अपना कर्तव्य न निभाकर राजनीतिक एजेंट बन गये हैं और कोई एक दरबार में हाज़िरी लगाने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस इतना हावी हो गया है कि भू-माफिया वहां पर अनियंत्रित हो गया है। आदिवासियों, ओबीसी के लोगों की जमीन पर कब्जे किये जा रहे हैं। अगर मैं ताजा उदाहरण दूं, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि एक गुर्जर परिवार, एक पूर्व सैनिक के परिवार पर पिछले 10-15 दिन के अन्दर ही भू-माफियाओं ने हमला किया, बहुत-से लोगों को चोट आयी और एक व्यक्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। नशे के नुक्कड़-नुक्कड़ पर अड्डे हैं। एक नाबालिग बच्चे को भी पता है कि कहां पर ड्रग्स मिलेंगे, पर आश्चर्य यह है कि पुलिस को नहीं पता कि अड्डे कहां पर हैं?

पेपर लीक पर आप शिकंजा कसने की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो आप एसआई भर्ती पर मौन क्यों हैं, जिसे कोर्ट बार-बार बता चुका है कि वह फर्जी है। आप ही के एक मंत्री कहते हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उसे रद्द नहीं कर पा रहे हैं। समग्र विकास की बात करते हैं। समग्र विकास कैसे होगा? 500 से ज्यादा स्ट्रेंथ वाली बालिका विद्यालयों को बॉयज स्कूल्स में मर्ज कर दिया गया है। महात्मा गांधी स्कूलों को समीक्षा के नाम पर अटकाया जा रहा है। अभी तक सरकार का स्टैण्ड क्लीयर नहीं है, जबकि नया सत्र शुरू होने जा रहा है। अभिभावक कनफ्यूज्ड हैं, शिक्षक कनफ्यूज्ड हैं। शिक्षा के मंदिरों की बात करते हैं और वही शिक्षा के मन्दिर इस पूरे राज्य में और मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कितनी जर्जर अवस्था में हैं और मरम्मत की बांट जोह रहे हैं, पर सरकार के पास कोई भी कार्ययोजना नहीं है।

उच्च शिक्षा में विद्या संबल की बात करते हैं। 60 परसेंट से अधिक कोर्स अभी भी अधूरा है, पर सरकार ने 300 कॉलेजों से 2500 शिक्षक हटा दिये हैं। एनएलयू 2024 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के पद पर किसी को नहीं लिया। यह आरक्षण और संविधान की धज्जियां उड़ाता है। यह बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के संविधान और आरक्षण के प्रावधान का अपमान है। कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना में सत्र 2024-25 में 30 हजार स्कूटियों का वितरण किया गया, पर इसमें सभी वर्गों की तर्ज पर पृथक से ओबीसी वर्ग की

एक भी छात्रा को स्कूटी नहीं दी गयी। प्रदेश के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की हालत यह है कि वहां 50 परसेंट शिक्षक भी नहीं हैं, यू-ट्यूब से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वे बिना प्रैक्टिकल के पास होकर निकल रहे हैं। हम किस तरह के डॉक्टर इस समाज को दे रहे हैं। यह इस जनता के वोट के साथ खिलवाड़ है, इसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

सरकार सकारात्मकता की बात करती है। सकारात्मक का उदाहरण तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है, जिसने अपना बड़प्पन दिखाया और जनता द्वारा चुने गये, इस सदन में बैठे इधर-उधर के 200 सदस्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखायी, 2022 में एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें एश्योर किया गया कि कोई भी विधायक, सांसद, सरपंच, कोई भी जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन न हो, पर अभी आपकी सरकार की सोच की संकीर्णता देखिये। आपका हृदय इतना बड़ा नहीं कि आप उसको फोलो कर पायें। उद्घाटन समारोह, मीटिंगों में अधिकारी और कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई बार बहुत सारे सदस्यों ने सरकार और अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया, पर सरकार मौन रहती है। इसका ताजा उदाहरण विधान सभा डीग का ले लीजिये। यह दर्शाता है कि जब आग लगती है तो खुद का घर भी चपेट में आ सकता है।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

इस सरकार की भ्रष्टाचार पर लाचारी देखिये। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस पर उदासीनता देखिये। मैं एक बेहतरीन एक्जाम्पल मेरे विधान सभा क्षेत्र का देती हूं, जहां जो माननीय तहसीलदार महोदय हैं, उनका पहले ट्रांसफर किया गया, वे उसके खिलाफ स्टे लेकर आते हैं। जयपुर जिले में रहकर वे जोधपुर हाई कोर्ट से स्टे लेकर आते हैं, उसी बीच उन पर एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है और सरकार की लाचारी देखिये कि आज तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। यह मुद्दा सरकार के संज्ञान में है, फिर भी सरकार बिलकुल मौन है। ऐसी क्या लाचारी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप कर्मचारी, एक अधिकारी को एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उसे एपीओ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ और कोई कार्यवाही नहीं कर सकते? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि कार्यपालिका विधायिका पर हावी होती जा रही है और यह एक असंतुलन की स्थिति पैदा कर रही है। हमें संभलने की जरूरत है। यह मैं इन पंक्तियों के साथ व्यक्त करती हूं।

यह जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पायी।

राज्यपाल महोदय ने कहा कि यह सरकार वादों पर नहीं काम करने पर विश्वास रखती है। 13 महीनों में जनता को जो जनरल परसेप्शन इस सरकार के लिए है, वह है कि यह एक इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। यह योजना वही, नाम नया वाली सरकार है। यह एक नामकरण विशेषज्ञ सरकार है। ईआरसीपी का हजारों-करोड़ का काम कांग्रेस सरकार कर गयी, पर नाम

बदलकर आप वाहवाही लूट रहे हैं। ईआरसीपी मॉडिफाइड पीकेसी योजना में आपको राजस्थान पार्वती, कालीसिंध, चंबल जैसे नाम नहीं भाते। आप लोग कभी भी नहीं चूके हैं कि आप लोग ईश्वर को भी राजनीतिक तूल बनायें। उससे आप कभी नहीं चूकते। पर मुझे खुशी है कि अभी तक ऐसी कोई पर्ची नहीं आयी कि मेरे सामने बैठे हमारे साथी सदस्यों के नाम भी बदले जायें, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती, हमें नये नाम याद करने पड़ते।

चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे खेद है कि अपना काम सींसियरली कर रहे एक डॉक्टर को, बाड़मेर जिले में, ओपीडी में जाकर एक उप खण्ड अधिकारी अस्पताल में आकर अमर्यादित शब्द कहता है। दिन के 200-250 मरीजों को सुनना, उनका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है। क्या एक तहसीलदार या कोई एसडीएम दिन में 200-250 कंप्लेंट्स को सुनता है? लेकिन कोई भी नियम-कानून उनको यह हक नहीं देता है कि वह अभद्र भाषा का प्रयोग डॉक्टरों के खिलाफ करें या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ करें।

mdp/rtm/03.02.25/17:30/3h

सभापति महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को गंभीरता से इस विषय में संज्ञान लेने को कहूंगी और इसी वजह से सेपरेट मेडिकल केडर की भी मांग की जा रही है। मैं बात करूं मेरे चोमू की, वहां कालाडेरा में महीनों से स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। यह उस सीएचसी की बात है जहां पर महीने की पहले 100 डिलीवरियां हुआ करती थीं। प्रसूताओं को मां योजना में प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है। सृष्टि की जननी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों यह सरकार बार-बार कर रही है? क्यों इस बात को बार-बार बताने के बावजूद भी इस पर कोई विचार नहीं किया जाता?

अभी बिजली कटौती जो हो रही है, इस समय भी हो रही है, वह इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिजली का इतना संकट है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) पानी पर, जेजेएम में हमारे चोमू इलाके में 37 परसेंट कवरेज है, जो राज्य का न्यूनतम है। मैं एक मिनिट लूंगी, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः बारह सेकण्ड बाकी है, दो मिनट नहीं है। मैंने घंटी एक मिनट पहले बजाई है।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): राज्यपाल महोदय ने बात की राजकाज और ई-फाइलिंग की, यह व्यवस्था कांग्रेस राज में शुरू की गयी थी। आपने सिर्फ एक नया कॉलम एड किया एवरेज डिस्पोजल टाइम, जिससे अधिकारियों का ध्यान क्वालिटी से क्वांटिटि पर चला गया। हर कोई अपना एवरेज डिस्पोजल टाइम सुधारने में लग गया। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका एवरेज डिस्पोजल टाइम एक फाइल के लिए एक मिनट से भी कम है। यह दर्शाता है या तो लीपापोती है या वे लोग कोई सुपर पावर हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): हमारे सामोद रोप-वे के लिए मैं बार-बार कह रही हूं परंतु डबल इंजन की सरकार उसे चालू नहीं कर पा रही है। जनता की पुकार है कि इतना लाचारी में भी यह सरकार न चलाए कि ये पंक्तियां सिद्ध हो जाएं-

'शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं,

इतना समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं।

धन्यवाद, जय हिन्द। जय संविधान।'

श्री सभापति: अशोक कुमार जी कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय एवं माननीय सदन को नमन करते हुए राजस्थान की वीर मरुधरा को नमन करते हैं, जहां देश के महानायक वीर महाराणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर शासक हुए, जिन्होंने सत्य, न्याय, धर्म की स्थापना की तो दूसरी ओर रानी पद्मिनी, हाड़ा रानी, मां पन्नाधाय, मीरा बाई हुई, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। देश की आन-बान-शान के लिए अपने प्राण हंसते-हंसते दे दिए, उन सभी को शत-शत नमन।

हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार का एक वर्ष बहुत अच्छा रहा। बजट जुलाई में आया और 7 माह के अल्प समय में ही कई बड़ी उपलब्धियां रही। सबसे बड़ी उपलब्धि ईआरसीपी योजना, जिसे अब हम राम सेतु लिंक परियोजना के नाम से जानेंगे, उस पर कार्य शुरू होना। ये योजना पूरे प्रदेश के विकास का नया इतिहास लिखेगी और इसमें हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो भागीरथी कार्य किया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके साथ ही सरकार द्वारा हर वर्ग विशेष के लिए, चाहे युवाओं को रोजगार देने का एक लाख लोगों का लक्ष्य था तो 60 हजार लोगों को नियुक्तियां दे दी, बाकी को भी जल्दी मिल जाएगी। किसान भाईयों हेतु मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही बहनों और बेटियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्य मंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के साथ हर वर्ग विशेष का पूरा ध्यान रखा गया।

सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में ही राजस्थान राइजिंग को लाकर 33 लाख करोड़ के एमओयू होना भी कम बात नहीं। इससे प्रदेश के विकास को नये आयाम मिलेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प 2047 का विकसित भारत को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा को भी बीते एक वर्ष में बहुत कुछ प्रदान किया गया है। टैक्सटाइल पार्क के लिए भूमि आवंटित करना, नगर निगम की स्वीकृति प्रदान करना, बहुत बड़ा कार्य हुआ। नगर निगम बनने से भीलवाड़ा के विकास को गति मिलेगी। साथ ही हमें अमृत-2 योजना दी जो काफी समय की प्रतीक्षा के बादमिली, जिसमें शहर के सभी निजी कॉलोनियों को शुद्ध चम्बल का पेयजल मिलना भी भीलवाड़ा के लिए वरदान साबित होगा। माही डैम जल योजना, भीलवाड़ा-जयपुर ग्रीन कोरिडोर की घोषणा एवं 33, 132 केवी ग्रिड भी कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिले। हाई स्कूल की स्थापना के साथ ही कई योजना जैसे मानसरोवर झील, गांधी सागर तालाब, आधुनिक रोडवेज डिपो, पुरका हॉस्पिटल, आरके हॉल

निर्माण व आधुनिक कचरा संग्रहण जैसी कई सौगतें दीं। इसके लिए हम हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल का ह्रदय से आभार व्यक्त करते हैं।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर प्रदेश का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां टैक्सटाइल और माइनिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। टैक्सटाइल में तो राजस्थान का मैनचेस्टर है। जीडीपी में राजस्थान में तीसरा स्थान है, जहां 10 करोड़ मीटर प्रतिमाह कपड़ा बनता है। 31 हजार करोड़ का टर्नओवर है। इसमें 6 हजार करोड़ का निर्यात होता है। भीलवाड़ा की भूमि बहुत ही क्रियेटिव, एनर्जेटिक है। यहां के उद्यमी बहुत ही पुरुषार्थी हैं। भीलवाड़ा अपने आसपास के शहरों अजमेर, कोटा, उदयपुर से भी ज्यादा योग्यता रखता है, लेकिन भीलवाड़ा के विकास केलिए अभी तक कोई बड़े कार्य नहीं हुए। इस हेतु हम माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि भीलवाड़ा को डवलपमेंट के लिए बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करें। पूर्व में भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी राजस्थान में लेते हुए घोषणा की गयी, परंतु क्रियान्विति नहीं हो पायी। अतः भीलवाड़ा के विकास के लिए आप द्वार खोलें। हमें आप ऐलिवेटेड आरओबी, सुपर कोरिडोर, आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर, एयरकार्गो, कैंसर हॉस्पिटल, मल्टीपरपज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी, ईआरसीपी योजना, आधुनिक पशु चिकित्सालय प्रदान कर अनुगृहित करें। भीलवाड़ा की जनता आपके प्रति सदा कृतज्ञ रहेगी।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी द्वारा हर घर अब सूर्य योजना, न केवल प्रदेश को बिजली आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ाएगा, वरन पीएम कुसुम योजना से किसान भाईयों को दिन में बिजली उपलब्ध करायेगा। सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में एक भी मामला पेपर लीक का नहीं होना, निःसंदेह प्रशंसनीय और सरकार की पारदर्शिता को दिखाता है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष 25 लाख 51 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 6 लाख 84 हजार मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया। यह आंकड़ा राजस्थान के किसान का रासायनिक खाद के प्रति निर्भरता को दर्शाता है। आज कैंसर जैसी भयानक बीमारी के पीछे अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग होना मुख्य कारण है। रासायनिक खाद, कीटनाशक न केवल जमीन की उर्वरकता को खतम करते हैं, वरन इससे उत्पन्न उत्पादों के उपयोग से प्रदेशवासी बीमार होते जा रहे हैं। आज परम्परागत जैविक कृषि से उत्पादन करने वाले कृषकों की संख्या नगण्य रह गयी। इसी समस्या को देखते हुए समय-समय पर सहृदय प्रधान मंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को जैविक उत्पाद प्रयोग में लेने और देश के कृषकों को जैविक कृषि करने हेतु प्रेरित किया जाता रहा। राजस्थान में जैविक कृषि की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान मोटे अनाज में बेस्ट आर्गेनिक फूड बॉस्केट बन सकता है। इस हेतु प्रोत्साहन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे किसान भाई पूर्व के समान जैविक कृषि पर लौट सके।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप भी गौ भक्त हैं, परंतु अभी तक हमारी प्रदेश की गौ माता की पीड़ा का कोई समाधान नहीं हुआ। गौ माता अभी-भी रोड पर दर-दर भटकती हुई भूखी-प्यासी, सर्दी-गर्मी-बरसात की पीड़ा सहन करते हुए कत्लखाने

तक की असीम वेदना सहन कर रही है। गौ माता हमारे देश की संस्कृति का नहीं धरती माता का आधार स्तंभ है, जो ऋषियों का रिसर्च है, जिसमें 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं, जिसके गोबर एवं गो मूत्र तक उपयोगी है, उसकी आज ये दुर्दशा बहुत पीड़ा देती है। जब तक गौ माता सुखी नहीं, तब तक मानव जाति सुखी नहीं हो सकती। चाहे हम संसाधन कितने ही बढ़ा ले, विकास के नाम पर बहुत कुछ कर लें, ये गौ माता की पीड़ा हमारी नहीं वरन पूरे प्रदेशवासियों की पीड़ा है। हमारे पशुपालन मंत्री जोराराम जी भी एक गौ भक्त हैं, वह भी यही चाहते हैं। साथ ही प्रतिपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जी जूली भी गौ माता की पीड़ा के समाधान व अनुदान के लिए सदन में कई बार विचार रख चुके हैं। हम तो यह भी कहेंगे हमने कई माननीय सदस्यों से बात की, सभी गौ माता की पीड़ा का समाधान चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप द्वारा पिछले बजट में गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया गया, उसके लिए गौ भक्तों द्वारा हृदय से आपका आभार।

आपने कहा अगला बजट ग्रीन बजट आएगा, तो आपसे निवेदन करते हैं कि प्रदेश की गोचर व चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराएं। उस भूमि को चिह्नित करते हुए बाउंड्री बनवाने का बजट प्रदान करें। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 'कैच द रेन' के रूप में वर्षा जल के संचयन की अनूठी पहल की है परंतु वास्तविकता में हमारे चरागाह व गोचर भूमि ही हैं जो कैच द रेन'का कार्य करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो भूमि गौ माता के लिए प्रदान की है, वह भूमि गौ माता के लिए सुरक्षित हो, अतिक्रमण से मुक्त हो, गौ माता व गोचर, चरागाह भूमि के लिए कोई ठोस नीति बनाकर लागू होनी चाहिए। इसके पीछे केवल गौ वंश या गौ पालन को बढ़ावा देना ही नहीं अपितु इसके माध्यम से गांव के इकोलोजिकल बेलेंस को सही करना व जल भरण की क्षमता को बनाए रखना।

आज प्रदेश सबसे अधिक चरागाह भूमि वाला राज्य है, परंतु आज तक इन चरागाहों के समग्र विकास हेतु ध्यान नहीं दिया गया। सरकार द्वारा 1996 के 170/1 एवं 2017 के नियमानुसार प्रत्येक ग्राम स्तर पर चरागाह भूमि विकास समिति, जिला स्तर पर गठन के साथ ही समय-समय पर विभिन्न नियमावली तो बनाये गये, लेकिन आज भी चरागाह भूमि अतिक्रमण, अंग्रेजी बबूल, जंगली झाड़िया एवं अवैध खनन से प्रभावित है। नरेगा में गौ चर भूमि के कार्य कराये जाना अनुमत है, लेकिन अभी-भी स्थानीय स्तर पर चरागाह भूमि का विकास नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चरागाह विकास से गांव का पर्यावरण शुद्ध होगा, कुओं का जलस्तर बढ़ेगा जिससे गांव में किसान का पलायन रूकेगा एवं जैविक कृषि से स्वास्थ्य सुधरेगा और आपके ग्रीन बजट का संकल्प पूरा होगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया था कि गौ रक्षा का प्रश्न स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंदजी ने गौ वंश की आदरपूर्वक सेवा किए जाने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये बात कही थी। अभी कुछ समय पूर्व ही महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। इस हेतु हमारा भी आपसे निवेदन है कि प्रदेश की सरकार भी यह घोषणा करे।

माननीय सभापति महोदय, हमारा सरकार को एक सुझाव है कि विद्यालय तो बहुत सारे हैं, परंतु शिक्षा पद्धति व सिलेबस में कुछ रचनात्मक परिवर्तन कर हम भावी भारत का भविष्य और सुंदर बना सकते हैं। बालकों को शिक्षा बचपन से धन अर्जन की विधि, फास्ट मनी नहीं, राइट मनी कैसे कमाई जाए और जीवन के संघर्षों से कैसे अपने आप को संतुलित रखे और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के माध्यम से घर, समाज और देश के लिए उपयोगी बने।

इसके साथ ही बालिका को बचपन से सृजन की शिक्षा, स्वस्थ रहने का विज्ञान, धर्म व भावी जीवन को संस्कारित बनाने व विश्व को उच्च स्तरीय प्रतिभा देने की शिक्षा, यह सभी उनके सिलेबस में जोड़कर हम शिक्षा को वास्तविक शिक्षा में परिवर्तन कर सकेंगे या यूं कहें कि हम भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पुनर्स्थापना कर पाएंगे।

सभापति महोदय, अंत में हम सदन से निवेदन करना चाहते हैं कि राजनीति में आना हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहा, हम ऐसे ही प्रभु की योजना और गौ माता के आशीर्वाद से आ गये।

Ans/rtm 17.40 3j 03.02.2025

राजनीति में आने से पूर्व जो जाना वह आपसे निवेदन करेंगे कि राजनीति का अर्थ श्रेष्ठ नीति का निर्माण हो जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। विकास तो बाई प्रोडक्ट है, जो नीति धरती पर सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करे वह सभी के भीतर मित्रता, प्रेम व करुणा के भाव को बढ़ाये। राजनेता समाज का नेतृत्व करता है, वह नायक की भूमिका में होता है। राजा का दायित्व अदा करता है, राजा का अस्तित्व उसकी प्रजा से होता है। प्रजा के हित का हर श्रेष्ठ कार्य राजा को महान राजा बनाता है, वह ऐसा आदर्श हो जिससे जनता प्रेरणा ले। राजनेता का जीवन, उसके हर कार्य जैसे उसके विचार, भाव, धैर्यता, गंभीरता,पूर्ण ईमानदारी, न्याय प्रिय होना सभी गुण हो, जिसको जनता अपना आदर्श माने, जैसे राजा राम हुए। राजनेता का दायित्व है कि वह जनता के हितों का पूरा ध्यान रखे। जनता कैसे सुखी, स्वस्थ, शिक्षित,समृद्ध हो, उनमें प्रेम व करूणा का विकास हो, उनका जीवन सुंदर हो, सत्य, न्याय व धर्ममय हो। कर्ता भाव से मुक्त होकर कार्य करे, अगर ऐसा जीवन हो तो हमें प्रभु का प्रेम मिलता है, जीवन सफल होता है, धरती पर आना सार्थक हो जाता है। सौभाग्य से हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जो तपस्वी, साधक है, वह एक निष्काम कर्मयोगी हैं, हम सभी उनसे प्रेरणा लें। महान् संत श्री शरणानंद जी महाराज जिन्होंने देश की आजादी के संग्राम में भाग लिया था, उन्होंने राजनीति के बारे में कहा है कि सेवा करने वालों का चुना हुआ राष्ट्र हो, महान पुरुषों का बनाया हुआ विधान हो, तभी समाज में न्याय तथा शांति की स्थापना हो सकती है।

अभी कुछ समय पहले प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में विकास का ऐसा इतिहास लिखा जो पिछले 70 वर्षों में नहीं लिख पाए, उसके साथ ही कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो अपने देश को विश्व में

पांचवी अर्थव्यवस्था में महान शक्ति को बनाना और उसके साथ ही चन्द्रयान की सफल यात्रा, प्रभु श्री राम का मन्दिर, धारा 370 हटाना ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। साथ ही, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी एक वर्ष के भीतर जो निर्णय लिए वह कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ईआरसीपी की योजना के साथ-साथ उन्होंने जितने कमिटमेंट किये उन सबको पूरा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समय प्रदान किया उसके लिए आभार, धन्यवाद। जयहिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री राधेश्याम जी बैरवा।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय के साथ-साथ बारां-अटरू विधान सभा की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से इस विधान सभा में प्रतिनिधित्व कर पाया।

माननीय सभापति महोदय, यह अभिभाषण राजस्थान के समग्र विकास और लोक कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के विकास को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय संस्कृति में कुम्भ का विशेष महत्व है। राज्य सरकार ने राजस्थान में महाकुम्भ में शामिल हो रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष कैम्प स्थापित किए हैं जिसमें भोजन, चिकित्सा व्यवस्था एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वी राजस्थान के विकास के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का विजन प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर राम जल सेतु लिंक परियोजना की शुरुआत की है। बारां ज़िले को भी सिंचाई और पेयजल के क्षेत्र में इससे बहुत लाभ होगा।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान महत्वाकांक्षी परवन बृहद् सिंचाई परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से ही लंबित पड़ी हुई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसके लिए बजट मुहैया करवाए ताकि जल्दी से जल्दी इसका कार्य पूर्ण हो और किसानों को इसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि बारां ज़िले में जिन किसानों की फ़सलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवाज़े की राशि प्राप्त हो। इसके साथ ही, विधान सभा क्षेत्र में बची हुई सड़कों और ओवरब्रिज आदि का निर्माण पिछली सरकार की

तरह अटके नहीं रहे, समय पर पूर्ण हो।

माननीय सभापति महोदय, बीते एक वर्ष के दौरान पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज खोले गए है। बारां ज़िले में भी एक राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र में हमारी सरकार ने घुमन्तु, अर्ध घुमन्तु, गा़डिया लुहार, कालबेलिया समुदाय के लोगों के लिए 609 भूखण्ड आवंटित किए हैं। बारां ज़िले में बसने वाले इन समुदायों के जीवन स्तर में इससे सुधार होगा।

सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, इससे 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी गई है। आशा है कि बारां ज़िले में भी इसके माध्यम से नये उद्योगों के विकास को बल मिलेगा।

सभापति महोदय, सरकार ने केन्द्रीय योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पीएम कुसुम योजना, ग्राम सड़क योजना आदि को राज्य में उच्चतम स्तर पर क्रियान्वित किया है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

सभापति महोदय, जहां पिछली सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय किया था, वहीं वर्तमान सरकार ने समय पर तथा पारदर्शी तरीके से सारे एग्जाम करवाए हैं। प्रथम वर्ष में ही 59 हजार 236 पदों पर युवाओं को नियुक्ति प्रदान की है।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राजस्थान विशेष के विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान किया है। आज राजस्थान ना केवल बुनियादी ढांचे में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

अंत में मैं एक बार फिर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और सरकार को जनता की सेवा में तत्पर रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ राजस्थान विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, धन्यवाद। जयहिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान, जय श्री राम।

श्री सभापतिः श्री मनोज कुमार सादुलशहर।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): मेरा है।

श्री सभापतिः सादुलशहर लिख रखा है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मेरा नाम नहीं था आज का, सुजानगढ़ का होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): हमारे पास सूची में है मनोज कुमार सादुलशहर, 112 नम्बर।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): 112 नम्बर मेरा ही है, कांस्टीट्यूएंसी इनकी लग गई। मेरा ही 112 है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): तो आपके सचेतक ने गलत लिखा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): टीवी वाले भी सही दिखा रहे हैं। ऊपर सही चल रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): फिर आपके सचेतक ने गलत लिखा है।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): 112 मेरा ही है। सभापति महोदय, महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। अभिभाषण को सुनकर बहुत निराशा हुई। इस अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार का आगे चार साल का विजन क्या है या आगे एक साल में क्या करने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को फोबिया हो गया पिछली सरकार को कोसने का, वहीं उसमें झलक रहा है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष में एक फोबिया सा हो गया है पिछली सरकार को कोसने का। परन्तु आप अब क्या करने वाले हैं, वह नहीं बताया।

VPS-RTM-03.02.2025-17.50-3k

माननीय सभापति महोदय, आप भी सभापति पैनल पर बैठे हुए हैं। आपने भी अभी एक बात कही है कि 19 हजार कुर्की, नीलामी हुई है। सभापतिजी जब बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि हुई है पिछली बार और आज ही मेरा जो 15 नम्बर क्वेश्चन लगा था और उसके जवाब में उत्तर दिया है कि 2021 से नीलामी बंद है और उक्त में से किसी भी काश्तकार की जमीन कुर्की की कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यह 15 नम्बर क्वेश्चन के जवाब में दिया है और आपने यह कहा है कि 19 हजार नीलामी किसानों की हुई है, तो आप यह कहां से आकड़ा लाये हैं? कहां से यह फोबिया लाये हैं या मंत्रीजी ने यह मुझको जो जवाब दिया, यह गलत है? यह आज का ही जवाब है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): 2021 में बंद हो गयी थी, उससे पहले हुई थी।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): यह आज के प्रश्न का ही जवाब है।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): आप बात कर रहे थे कि आगे विजन क्या है? 168 पैरा का यह अभिभाषण पढ़वाया और इस अभिभाषण में अनुसूचित जाति, एस.सी. के लिए एक शब्द भी कहीं पर लिखा हुआ हो तो आप मेरे को बता दो, मैंने दो बार पढ़ा है। 168 पैरा में एक भी पैरा या एक भी शब्द नहीं लिखा है एस.सी. का, अनुसूचित जाति का, यह शर्म की बात है। यह पूरा मंत्रिमंडल ने तैयार किया है। 168 पैरा में से एक पैरा भी नहीं मिला, एक शब्द भी नहीं लिखा है। एस.सी. का कहीं पर लिखा हो तो आप मुझे बता देना। इससे यह जाहिर होता कि किस तरह की असंवेदनशील सरकार, जो अनुसूचित जाति प्रदेश में 17 परसेंट है, उसके प्रति यह सरकार है। क्या विजन है आने वाले चार साल में इस सरकार का, उस वर्ग के प्रति जो पूरी तरह से सरकार की तरफ देखता है कि सरकार आने वाले समय में

उनके हक के लिए क्या करेगी, उनके उत्थान के लिए क्या करेगी और उस वर्ग के लिए आपको एक शब्द भी लिखने को नहीं मिला। 168 पैरा में एक पैरा नहीं मिला।

आप बात कर रहे थे बिजली की, बखान कर रहे थे कि बिजली का यह किया। बहुत कोसते थे पिछली सरकार को आप लोग कि बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा और आप ही ने इसमें एक पैरा में यह लिखा है कि 26,325 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता प्रदेश में है, तो कहां से पैदा हो गयी अगर उस कांग्रेस के राज में अगर यह नहीं होता तो यह कहां से हो गयी? जब पिछली बार लिखा जा रहा था तो सब यह कह रहे थे कि कहां है बिजली, कहां पैदा हुई, एक यूनिट पैदा नहीं हुई और आज आपने ही इसी में यह लिखवाया है कि 26,325 मेगावाट बिजली राजस्थान उत्पादन कर रहा है। जो कांग्रेस ने काम किये, उसको कोसने का काम आप जरूर करोगे पर जो किया है वास्तव में वह समझ में नहीं आता।

आपने यह लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं, आई.पी.डी. टावर, एक पैरा में यह लिखा है। रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग, मेट्रो, सिविल लाईन्स फ्लाईओवर, यह निर्माण कर रहे हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट वे हैं जो तीन साल, चार साल से चल रहे हैं। आप सबको पता है कि आई.पी.डी. टावर का प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? सिविल लाईन्स फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? मेट्रो का प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? अब आप आज लिख रहे हैं और अपनी उपलब्धियां महामहिम के मुख से बता रहे हैं।

अमृत 2.0 में आपने लिखा है कि 5 हजार 123 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। यह तो 2022-2023 में ही स्वीकृत हो गये थे। आप लोग पिछले आठ-नौ महीनों से इसको रोककर बैठे हैं। बहुत से टेंडर हो गये, टेंडर निकाल रहे हैं या टेंडर हो गये तो उनको भी आप रोककर रख रहे हैं। ये सारे के सारे स्वीकृत हुए हुए हैं, उनकी स्वीकृतियां निकालनी हैं या जो कार्यादेश दिये गये हैं उनको रोक रखा है, उनको कार्यादेश देने हैं और आप उनकी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं।

आप यह बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने पट्टे दिये हैं। घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू, गाड़िया लोहार, कालबेलिया है और संख्या सबकी मिलाकर कितनी है? 609 है। वह फिगर लिखा है उसमें कि 609 पट्टे दिये हैं। इतनी सारी जातियां, घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू, गाड़िया लुहार, कालबेलिया आदि हैं।

साइकिल हमने 2 लाख 75 हजार बांटी है। पेपर में यह आ रहा था कि हजारों साइकिलें, वह फोटो भी थी कि वे कबाड़ पड़ी हैं। किसलिए वे जंग खा रही है? उनका रंग काला है। काला, सफेद, गुलाबी, केसरिया से क्या होता है? साइकिल तो साइकिल होती है, काली साइकिल तो लोग बहुत चाहकर चलाते हैं और इस केसरिया साइकिल के बजाए तो काली साइकिल ज्यादा पसंद करते हैं कि कहीं पर जायेंगे तो पता ही नहीं चले कि कौनसी साइकिल है। वह कबाड़ हो रही है, उनको आप बांट दो। काली नहीं बांटो तो केसरिया करके ही बांट दो, गुलाबी करके ही बांट दो। जैसे यह कार्पेट गुलाबी कर दिया पर आप कबाड़ मत

बनाओ। यह सरकार का पैसा है। सरकार का वह पैसा है। यह उस आम आदमी का पैसा है जिसके टैक्स से वह खरीद की गयी है, यह बहुत ही सोचने वाली बात है।

आप माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि हमारी यह उपलब्धियां हैं। यह बताया कि पांच साल में कांग्रेस के राज में जो फोबिया है उनको कोसने का कि 2 लाख 75 हजार करोड़ से 5 लाख करोड़ का राजस्थान में कर्जा बढ़ा दिया, पर आपने एक साल में कितना बढ़ाया है, यह भी आप साथ में बताते कि इस एक साल में कितना कर्जा बढ़ाया है? हमने पांच साल में जी.डी.पी., विकास दर, पूरे देश में राजस्थान दूसरे नम्बर पर था और नोर्थ इंडिया में पहले नम्बर पर था, 11.04 परसेंट विकास दर थी पर आज कहां पर है और कहां पर ले जाएंगे, आप यह बताइये। यह आकड़े हैं, जब कांग्रेस सरकार ने छोड़ा है तो 11.04 परसेंट विकास दर छोड़कर गयी थी और आज सरकार कहां पर डटी हुई है? यह आप लोग बताइये।

आज ये अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे। जो हजारों-हजारों ही नहीं, लाखों विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़ रहे हैं प्रदेश में। जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो एडमिशन हो रखे हैं, उनका भविष्य कहां पर जाएगा? यह भी बता देते। आपने यह लाइन लिखी है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे, तो यह कोई छोटी-मोटी संख्या नहीं है, यह लाखों की संख्या में है,ध्ख पर आपने यह जो खेल किया है ट्रांसफर्स का पंचायती राज में डेपुटेशन के माध्यम से, यह आज तक नहीं हुआ। तीन-तीन हजार, ढाई-ढाई हजार डेपुटेशन के माध्यम से यह ट्रांसफर हो रहे हैं। यह कौनसी नई प्रथा शुरू कर दी प्रदेश में? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अधिकारियों को आपने ट्रांसफर करके हटा दिये और वापस किसी को लगाया नहीं जा रहा है। हालात यह है कि तहसील का नायब तहसीलदार भी नहीं दे रहे हो और दूसरी तहसील के नायब तहसीलदार को उसका चार्ज दिया जा रहा है, क्या ऐसे ही काम होगा प्रदेश में?

श्री सभापतिः प्लीज, मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, बातचीत नहीं करें। आप बोलिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): बिजली का, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्दियों में किसानों को बिजली पूरे छह घंटे भी नहीं मिल रही थी, पहली बार ऐसा हो रहा है और निजीकरण का जो यह बीकानेर डिवीजन में खेल चला रहे हैं।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): पहले तो मिलती ही नहीं थी।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ): बिलकुल मिल रही थी।

श्री सभापतिः आप बोलिये। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। ठेकों पर जी.एस.एस. को देने की बात चल रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वैसे ही बिजली की समस्या बनी हुई है और आप समस्या किसानों के लिए पैदा करने जा रहे हैं। कौन आपको राय दे रहा है?

किसान निधि छह हजार रुपये से बारह हजार रुपये कर रहे हैं तो वह कब करोगे? एक

साल तो निकल गया। एम.एस.पी. गेहूं की बात थी, 2400 से 2700 करने का आपका जो वादा था, आपने केवल 125 रुपये जोड़े हैं, उसके बाद में आपने आगे की कोई बात नहीं की। उसकी जगह पर बाजरा था, उसको आपने निकाल दिया, हमारे रेगिस्तान की फसल ही बाजरा है। कहां से आप किसानों की भलाई की बात करोगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या करोगे? आप पेपर लीक की बात कर रहे थे। एस.आई. भर्ती का क्या हुआ?

श्री सभापतिः श्री लालाराम जी बैरवा।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): जितने थानेदार, जो एस.आई. भर्ती हुए हैं या जिनको रोक लिया था, पुनः आप उनको थानों में भेजने का काम कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री लालाराम जी बैरवा। प्लीज। प्लीज। श्री लालाराम जी बैरवा।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या पेपर लीक हुआ है तो आप भर्ती निरस्त नहीं कर सकते? क्या स्वार्थ है सरकार का जो आप इस भर्ती को नहीं रोक पा रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की धरा, ऐतिहासिक विरासत, महापुरुषों के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है जो राजस्थान की जनता के प्रति उनके निश्चल प्रेम को दिखाता है।

ssy/rtm/03.02.2025/18.00/3l

बहुत लंबे काल खंड में हमें ऐसा अभिभाषण सुनने को मिला है जो राजस्थान के समग्र विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसके समर्थन में अपने मंतव्य को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इसमें एक संकल्पना को साकार करने के लिए जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर विकसित राजस्थान द्वारा विकसित भारत का निर्माण कैसे किया जाए को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है।

भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने विकसित भारत निर्माण के लिए अमृत काल के आगामी 25 वर्षों तक का यह विजन, संकल्प हम सबके सामने रखा है। उसको पूर्ण करने के लिए राजस्थान को बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार होना होगा। इसी कड़ी में राजस्थान की जनता, जन प्रतिनिधि हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में अग्रसर हैं। जिसका संकेत उक्त अभिभाषण से स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है।

आदरणीय सभापति महोदय, हम सबको विदित है कि स्वराज्य प्राप्ति एवं राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात जिस विजन, गति, दिशा में राजस्थान के मूलभूत ढांचे का विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। इसका मूल कारण रहा कि बीच-बीच में ऐसी सरकारों का आना

जिसका मूल लक्ष्य राजस्थान का विकास नहीं बल्कि अपना स्वयं का विकास करना था। लेकिन अब राजस्थान की सरकार इस अवधारणा से बाहर निकलकर केवल एक ही बात को लेकर आगे बढ़ रही है, वह है विकसित राजस्थान, विकसित राजस्थान और विकसित राजस्थान।

आदरणीय सभापति महोदय, हम सबने कवि रहीम के इस दोहे को सुना है, सुना भी है और पढ़ा भी है, 'रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये ना ऊबरे मोती, मानुष, चून'। यही बात राजस्थान पर भी लागू होती है। जो जल संकट से बहुत अधिक जूझता रहा। लेकिन आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में आज प्रदेश की जीवनदायिनी नदियां चाहे वह पार्वती, काली सिंध और चंबल के पवित्र जल को राम जल सेतु के कलश से प्रवाहित किया गया है। इस परियोजना के साकार होने से समृद्धि एवं खुशहाली के नये युग की शुरूआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरुरतों को पूरा किया जायेगा। जो इस क्षेत्र के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा अभूतपूर्व एवं जनहितकारी कार्य सिद्ध होने वाला है।

इसी तरह से वंचित रह गये राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की दूर दृष्टि एवं कल्याणकारी परियोजनाओं का भविष्य में निर्माण किया जाता है तो राजस्थान उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर सकता है। जैसे मेवाड़, भीलवाड़ा क्षेत्र में नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत एक विशेष परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। जिसमें उस क्षेत्र में बहने वाली कोठारी, मानसी, खारी नदियां जो मैदानी क्षेत्र में बहती हैं और जिसके अंतर्गत मांडल, आसींद, हुरड़ा, गुलाबपुरा, शाहपुरा एवं फुलिया कलां तहसीलों सहित सैकड़ों गांवों के किसानों की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी इस ओर निश्चित ही अपना कदम बढ़ायेंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, इसी कड़ी में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'कैच दी रेन' के रूप में वर्षा जल के संचयन के जिस अनूठे अभियान का आरंभ किया, जिससे प्रेरणा लेकर हम सब भी अपने-अपने क्षेत्र में इसको लागू करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हम सबको पता है कि इसे आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार कर्म भूमि, मातृ भूमि अभियान के माध्यम से राजस्थान को जल उपलब्धता में संपन्न बनाने के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली है। मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी है कि आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध जल पर ही होगा। इसलिए जल संरक्षण का यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद आशीर्वाद बन सकता है।

आदरणीय सभापति महोदय, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र विकसित राजस्थान के लिए है, वह ऊर्जा का क्षेत्र है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में वर्ष 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने की प्रतिबद्धता को राजस्थान की जनता के समक्ष प्रकट किया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए पी.एम. सूर्य घर योजना को जमीनी स्तर पर जिस प्रकार बढ़ाया जा रहा है, वह सरकार का एक सराहनीय

कदम है। आज जब विधान सभा में घूमता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर बन रहा है। यह योजना आने वाले समय में निश्चित ही विकसित राजस्थान एवं भारत की नींव का एक बहुमूल्य पत्थर साबित होने वाला है।

आदरणीय सभापति महोदय, जब हम राजस्थान के युवाओं की ओर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि गत सरकार ने अपने कार्यकाल में अपने चहेते लोगों का चयन करने के लिए लाखों निर्दोष परिश्रमी और गरीब युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया था। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने दृढ़ संकल्प के साथ युवाओं को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास प्रारंभ किया है। वर्ष 2025 के दौरान 81 हजार पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कलैंडर जारी करना उनके ठोस इरादों को परिलक्षित करता है। इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए और वह आप में है।

आदरणीय सभापति महोदय, हम सबको यह अनुभूति है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी, बलिदानी देशभक्त हम सभी के लिए श्रद्धेय हैं। उनके जीवन से हमारे बच्चे देशभक्ति की प्रेरणा ग्रहण करें, इसके लिए राज्य सरकार ने 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण अमर बलिदानियों के नाम पर किया है। इसी कड़ी में शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवखेड़ा का नामकरण भी अमर क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारहठ के नाम से किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को शाहपुरा की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देवखेड़ा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस गांव को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने की महती कृपा करें।

आदरणीय सभापति महोदय, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार के विजन की बात करते हैं तो मेरा स्वयं का अनुभव है कि आज पी.एम. श्री योजना विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं विकसित करने का सफल माध्यम बनी है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को एवं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों के लगभग 3 लाख 15 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र के विद्यालयों का अवलोकन करते हुए स्वयं अनुभव किया है कि इन विद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं एक सच्चा नागरिक बनाने की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त करें।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): मैंने देखा है कि इन विद्यालयों में सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, गार्डन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण एवं 21वीं शताब्दी के कौशल एवं संवैधानिक मूल्यों के साथ स्वास्थ्य, योग एवं व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार

अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी और सामुदायिक गतिशीलता का संकेत देती है।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त करें।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): अंत में समय के अभाव के कारण मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सभी साथी गण कर्मठता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करुंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, आंधी क्या तूफान मिले चाहे जितने व्यवधान मिलें, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम। विकसित राजस्थान, विकसित भारत। जय हिन्द।

Spp/rtm/03.02.2025/18.10/3m

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। मैं सबसे पहले मेरी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय से सरकार ने जो अभिभाषण पढ़वाया, उसमें पिछले एक साल में ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं बता पाये जिससे माताओं, बहिनों, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, कर्मचारियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, स्पेशल पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक और नौजवान किसी भी वर्ग का किसी भी तरह का भला आप नहीं कर पाये। आज पूरे प्रदेश के अन्दर त्राहि-त्राहि मची हुई है और आपने पढ़वा दिया कि हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 26 और 27 में आपने ऊर्जा, कोयला उत्पादन, वितरण की स्थिति को बेहतर होना बताया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि राजस्थान प्रदेश के अन्दर कोयले के उत्पादन की स्थिति बेहतर है तो छबड़ा पॉवर प्लांट को ज्वाइंट वेंचर के नाम से NTPC को क्यों सौंपा जा रहा है? और इसी तरह से राजस्थान के अन्दर और जो थर्मल पॉवर प्लांट हैं, उनके भी चुपके-चुपके इस तरह के समझौते राजस्थान की सरकार क्यों कर रही है? पूरे राजस्थान के उत्पादक के जो कर्मचारी हैं, वह धरना-हड़ताल पर हैं। वह धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और अब सरकार किसी भी तरह से कुछ भी बताने के लिये तैयार नहीं है और उसके बाद ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से NTPC को यह पॉवर प्लांट सौंपे जाने के बाद जो कर्मचारी-अधिकारी हैं, उन कर्मचारी-अधिकारियों की क्या स्थिति होगी और उसके बाद उनमें आरक्षण की क्या स्थिति होगी, जो ST,SC, OBC और MBC कर्मचारी हैं, उनके लिये आरक्षण की स्थिति क्या होगी? यह भी आप पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसी तरह से 2013 से 2018 तक सरकारी स्कूलों को PPP मोड पर देने का काम आप लोगों ने शुरू किया। हर जिले के अन्दर चार-चार स्कूल देने तय किये। इसमें दो शहर के थे और दो ग्रामीण के थे। गंगानगर जिले के अन्दर दो शहर के जो स्कूल थे, वह दोनों मेरे सूरतगढ़ के स्कूल थे। दोनों ऐसे

स्कूल थे जो दोनों टॉप के स्कूल हैं, जिनके अन्दर 600-700 की स्ट्रेंथ हैं यानी आप जो इकाइयां सौंप रहे हैं, वह अच्छी इकाइयां हैं। इसी तरह से आप लोगों ने हॉस्पिटल भी PPP मॉडल पर 2013 से 2108 में दिये तो वह इकाइयां आप लोग सौंपने का काम कर रहे हैं जो सबसे अच्छी चल रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान प्रदेश के अन्दर सबसे कम लागत में बिजली का उत्पादन कोई इकाई कर रही है तो वह छबड़ा की इकाई कर रही है और उसके बावजूद भी छबड़ा इकाई को आप देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों को छह घंटे बिजली आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के किसानों को बिजली देने के लिये आपके पास एल टी लाइन नहीं है। ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिये एक-एक महीने तक किसान है, वह इंतजार करता रहता है। क्या आपके अधिकारियों को, जो एक्स.ईएन. है, ए.ईएन. है, जे.ईएन. है, उनको जो सरकारी फोन आप लोगों ने दे रखे हैं, क्या उनके सरकारी फोन आप चैक करेंगे कि उनके फोन पर कितने कॉल्स आयी हैं और उन्होंने कितनी कॉल्स किसानों की और आम लोगों की नहीं उठायी है? क्या यह आप लोग बता पायेंगे? आप लोग यह बताने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या इसकी आप लोग जांच कर सकते हैं? यदि उन्होंने रात को, जब किसान पानी लगाता है, उसको कम वोल्टेज मिलती है, उसकी मोटर जल रही है। एक-एक महीने के अन्दर दो-दो बार किसानों की मोटरें जल रही हैं और यह खामियाजा किसानों को कम वोल्टेज की वजह से भुगतना पड़ रहा है। आप राजस्थान में दो घंटे भी पूरी बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप मेरा एक प्रश्न लगा था, जो 22वें नंबर पर था, आज सदन में आया नहीं। उसके अन्दर आपने बताया है कि सिर्फ सूरतगढ़ तहसील के अन्दर 7 हजार 269 घरेलू कनेक्शन बिजली के ऐसे हैं, जिनके मीटर जले हुए हैं या खराब हैं। 1828 कृषि के मीटर ऐसे हैं जो जले हुए हैं या खराब हैं तो यह लगभग 10 हजार हो गये। सूरतगढ़ तहसील के अन्दर 10 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं कृषि और घरेलू के, जिनको आप 200 यूनिट जो बिजली फ्री मिलनी चाहिये एक महीने की, वह नहीं दे रहे हैं। 2 हजार यूनिट फ्री बिजली किसानों को मिलनी चाहिये थी, वह आप नहीं दे रहे हैं और इस तरह से लगभग एक हजार ट्रांसफार्मर है, वह पूरे सूरतगढ़ के अन्दर लगाना बकाया पड़े हैं। आपको मैं बिल दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो बिल निकाले हैं, यह बिल, माननीय सभापति महोदय, यह एक बिल है जो 53 हजार रुपये का घरेलू उपभोक्ता का बिल आया है। एक बिल है जो 15 हजार रुपये का घरेलू बिल आया है। एक बिल है वह 21 हजार रुपये का घरेलू बिल आया है। एक बिल 22 हजार का घरेलू बिल आया है। कांग्रेस के राज में जिनके जीरो के बिल आते थे, उनको आप 22-22 हजार के, 25-25 हजार के, 50-50 हजार के घरेलू बिल आप दे रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति आप लोगों ने पैदा कर रखी है।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 60 पर आप लोगों ने सोसायटी का जिक्र किया है। 30 लाख किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने के लिये आप लोगों ने कहा है। लेकिन आपने

यह नहीं बताया कि नये सिरे से सोसायटी में हिस्सा राशि जमा करवाकर आप लोगों ने कितने किसानों को ऋण दिया है। पिछले एक साल में आप एक भी किसान को नये सिरे से ऋण नहीं दे पाये हैं। वह सिर्फ ब्याज जमा कराते हैं, आगे उसकी काउंटिंग हो जाती है। इस तरह से आप लोग काम करते हैं। सूरतगढ़ तहसील के अन्दर तीन जी.बी. का जो मिनि बैंक है, वह 9 करोड़ रुपये का घोटाला करके बैठा है। लगभग 50 दिन से वहां इस बात के लिये धरना चल रहा है और 9 करोड़ रुपये जो खा गये, जिन्होंने घोटाला किया है और विभाग ने जो जांच की, उस जांच के अन्दर 17 लोगों को दोषी पाया गया, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जांच में 17 लोगों को दोषी पाया लेकिन एफ आई आर मात्र तीन लोगों के खिलाफ हुई। जिनमें से एक बीमार है, एक की मृत्यु हो गयी और तीसरा वह है जिसने इस घोटाले का उजागर किया। जिसने अधिकारियों को बताया कि 9 करोड़ का घोटाला हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके अन्दर उन लोगों के पैसे हैं जो बहुत गरीब और निर्धन हैं। एक विधवा महिला ने अपने पति के एक्सीडेंट का पैसा जमा करवा दिया। चार बच्चियां उनके पास हैं और बैंक घोटाला कर गया। अब वह विधवा महिला कहां जाये? एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर बैंक के अन्दर पैसा जमा करवा दिया। आगे नई जमीन खरीदने के लिये उसने साई के पैसे दे दिये, अब बैंक घोटाला कर गया। अब वह किसान जमीन कहां से खरीदे? उसकी साई के पैसे भी डूब गये और वह पैसा भी नहीं दे पा रहा है। यह हालात इस तरह के हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने किसानों के बारे में, यूरिया का जिक्र आप लोगों ने किया, लेकिन यूरिया की किस तरह से पिछले सीजन के अन्दर कालाबाजारी हुई और किस तरह से किसानों को यूरिया के लिये भटकना पडा। यह बात भी आप पूरी तरह से समझ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, चकबंदी आप लोग कर नहीं रहे हैं। पिछले एक साल से चकबंदी पर कोई काम नहीं हुआ। पिछले एक साल से खातेदारी पर कोई काम नहीं हुआ। जब किसान खातेदारी के लिये जाता है तो कहा जाता है मुख जुबानी कि खातेदारी ऊपर से आदेश आया हुआ है कि आपके खातेदारी ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय, चैम्बर में जाकर चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। ..(व्यवधान).. माननीय मंत्री महोदय, अपने चैम्बर में जाकर चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा।

एक माननीय सदस्यः यह डोटासरा जी मंत्रीजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैरा नंबर 16, 17, 18 में आपने सिंचाई का जिक्र किया है। लेकिन क्या सरकार बताएगी कि 5 फरवरी के बाद किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा? क्या सरकार जवाब देने के लिये तैयार है? सिंचाई के लिये कोई पानी नहीं है। आप लोगों ने अशोक जी गहलोत ने जो खाले बनाये थे और जो आगे बनने थे, उस काम को आपने रोक दिया और उन्हीं पैसों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके आप लोगों ने एक तरह से सब्ज-बाग़ दिखाने का काम किया है।

राजस्थान प्रदेश के अन्दर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के हालात क्या है? रबी 2023-2024 का जो बीमा मिल जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं मिला है। यानी बहुत-से पटवार मंडल ऐसे हैं जहां के बीमा को केलकुलेट तक नहीं किया गया है। बहुत-से पटवार मंडल ऐसे हैं जहां आपत्तियां लगा दीं। DGRC की मीटिंग के अन्दर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मीटिंग करके आपत्ति लगाकर जो बीमा उनको मिलना चाहिये था, उस बीमे का निस्तारण करने के बजाय आगे खिसकाने का काम सरकार ने किया है और फसल बीमा को आप लोगों ने पूरी तरह से मजाक बनाकर छोड़ दिया है। JJM की योजना का जिक्र बार-बार कर रहे हैं। लेकिन क्या JJM योजना के अन्दर आप लोग पिछले एक साल से ठेकेदारों को पैसा दे पा रहे हैं? ठेकेदार इसीलिये काम नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है और कर्मचारी इसलिये काम नहीं कर रहे हैं कि उनके पास कम्पोनेंट नहीं है।

jyg/rtm/03.02.25/18.20/3n

कर्मचारी यह कहते हैं कि हमारे पास लीकेज निकालने के लिए शॉकर तक नहीं है और एक महीने तक खराब पड़ी हुई आपकी मोटर, वो मोटर बाइंडिंग करने वाले के पास पड़ी रहती है इसलिए कि उसको आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये हालात आपके इस बारे में है।

महिला सुरक्षा, बेटी पढाओ, बेटी बचाओ का तो सत्यानाश आप लोगों ने कर ही दिया, न तो आप लोग बेटी को पढ़ाने का काम कर पा रहे हैं और न आप बेटी को बचाने का काम कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले अभिभाषण में विश्वास दिलाया था कि राज्यपाल महोदय से आपने यह कहलवाया था कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खेजड़ी के पेड़ जो दादी ने लगाये थे वो तो आप काट रहे हैं। राजस्थान में धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं और आप पेड़ है मां के नाम लगाने की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शुक्र है कि आपने अपने पूरे के पूरे अभिभाषण में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया है लेकिन महात्मा गांधी ने जिस तरह से सामाजिक सौहार्द बनाकर पूरे देश में बनाया था, उस सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान देने का काम किया उस संविधान को खत्म करने का काम भी आप कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉ. विश्वनाथ मेघवाल।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारा देश ने अद्भुत प्रगति अर्जित की है। मजबूत हाथों में कमान होने से भारत में अपना वर्तमान, बहुत बेहतर किया और भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार किया है। अभी जैसे हमारा बजट आया, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जिस तरीके का बजट दिया है, मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए 12 लाख रुपये तक की इनकम पर इनकम टैक्स में छूट देना, केसीसी में 3 लाख से 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी करना, ये हमारे आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, श्री भजन लाल जी शर्मा ने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में समग्र विकास के दूरगामी निर्णय किये हैं। जिनसे हमारी माताओ-बहनों और किसान भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था उसको 50 परसेंट से अधिक लागू कर दिया गया है और समय-समय पर इसकी पूरी मोनिटरिंग भी की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में आयोजित कर 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रेरणादायी सानिध्य भी हमें मिला है। समिट में 32 देशों ने हिस्सा लिया जिसमें से 16 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभायी। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई नीति 2024 लागू की गयी है जिससे रोजगार के सुअवसर मिलेंगे, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निवेश प्रस्तावों को शीघ्र लागू करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस पर उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। सरकार के आने के प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है उसको समय-समय पर समीक्षा कर इसको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, नदियों को जोड़ने का कार्य हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने नदियों को जोड़ने का काम हाथ में लिया है। पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी के समय में जिस तरीके से ईआरसीपी योजना का महत्वाकांक्षी का विजन प्रस्तुत किया था उसको विगत सरकार ने जिस तरीके से परियोजना को अटकाया, माननीय हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने संशोधित पार्वती लिंक चम्बल परियोजना जिसे राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियांवित करने की दिशा में मजबूत पहल की है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में अभी बता रहे थे कि राम के नाम पर है, यह एक संयोग है कि राजस्थान के नाम से 'रा' लिया गया है और मध्य प्रदेश के नाम से 'म' लिया गया है, यह संयोग से 'राम' का नाम हो गया है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि

ऐसी बड़ी परियोजना लाकर राजस्थान के 17 जिलों को इसमें बेनिफिट मिलेगा और करीब 4 लाख सिंचित क्षेत्र और 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी।

आईजीएनपी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 करोड़ 2816 करोड़ रुपये का बजट देकर 14 हजार 517 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी है जिसके तहत मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में भी अनूपगढ़ ब्रांच और कंवरसेन लिफ्ट के तहत करीब 100 करोड़ रुपये अनूपगढ़ ब्रांच के खाळों के सुदृढीकरण करने के काम के लिए बजट दिया है। कंवरसेन लिफ्ट के लिए 185 करोड़ रुपये देकर हमारे जितने भी खाळे जो जर्जर हालत में हैं उनको सुदृढ़ करने का काम हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इतना बजट देकर किया है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की अगर बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से हर घर जल नल से पहुंचाने का जो उनको बड़ा अवसर मिला था लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारम्भ करने में कीमती समय जाया किया, जब कार्य प्रारम्भ किया तो इसमें कई घोटाले हुए और पूरे देश में हमारी बदनामी हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हमारी सरकार ने 6091 करोड़ रुपये खर्च कर 11 लाख 17 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी से धन्यवाद देना चाहूंगा। अमृत जल 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों की पेयजल योजना में सुधार के लिए 5123 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। इसके तहत मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 25 करोड़ रुपये देकर खाजूवाला की पेयजल व्यवस्था थी उसको सुधारने का काम किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से हमारे विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं, पेपर लीक और नकल की घटनाओं पर जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी, भजन लाल जी ने अंकुश लगाया है, वह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, मैं इसके लिए उन्होंने जो मजबूत इरादों के साथ जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 100 से अधिक एफआईआर एसओजी थाने में दर्ज करवायी, 260 लोगों को गिरफ्तार किया और गत सरकार के समय में जो कठोर परिश्रम और योग्यता के बावजूद नियुक्तियां नहीं मिलने से युवाओं में निराशा हुई थी उसको आज माननीय मुख्य मंत्रीजी पर इन अभ्यर्थियों का भरोसा हुआ और परीक्षा प्रणाली में जो सुधार किया है उसके लिए मैं उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के सख्त निर्णयों से भर्ती संस्थाओं और गरिमा, विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुई है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक भी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई। युवाओं में विश्वास जगा है। एक वर्ष में भी 59,236 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है जो बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। चतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भी माननीय

मुख्य मंत्रीजी ने खोली है उसमें हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह खुली है, इस मौके पर मैं हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, उनमें अनुसूचित जाति का भी कोटा है, इससे अनुसूचित जाति के भाइयों का भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इससे उनको बेनिफिट ही मिलने वाला है। करीब 17 परसेंट कोटा अनुसूचित जाति का होता है उनको भी इसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, नई मेडिकल कॉलेजेज जिनमें 50 एमबीबीएस की सीट है, उसमें भी अनुसूचित जाति का कोटा होता है और सुपर स्पेशलिटी और जो भी हमारी पीजी की सीटें बढ़ी है उनमें भी उनको फायदा मिलेगा। मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सोलर प्लांट की स्थापना हो रही है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन कंवर्जन करवाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उस नियम में कंवर्जन करने में सरलीकरण करने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को भी इससे सोलर प्लांट में काम करने का मौका मिलेगा, उनको भी इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा।

MLS/RTM/03.02.2025/18:30/3o

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि चिकित्सा व्यवस्था को गांव-ढाणियों में सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की जा रही है। आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत राज्य में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलैस उपचार का भी लाभ दिया जा रहा है। मुख्य मंत्री निरोगी राजस्थान योजना के तहत भी दवा सूची का विस्तार किया गया है। वाजिब दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्रों की स्थापना में बढ़ोतरी की है। राज्य में 236 नये जन औषधि केन्द्र खोले गये हैं। राज्य में अब कुल 437 जन औषधि केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिससे कि आम गरीब आदमी को उचित मूल्य पर दवाइयों का वितरण किया जायेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया गया है, इसलिए मैं इस मौके पर उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार में हमारे थर्मल प्लांट्स कोयले की कमी से जूझते रहे। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय कर कोल ब्लॉक्स से कोयले का खनन पुन: प्रारम्भ किया, जिससे हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है। हमारी सरकार ने कुसुम योजना लागू कर किसानों को फायदा दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 4 हजार मेगावाट सोलर संयंत्र स्थापना का जो काम हुआ है, वह सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में भी किसानों को, वहां की जनता

को इसका बैनिफिट मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रकार प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा विकसित राजस्थान के संकल्प के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां कागजी जी।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): सभापति महोदय, महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मुझे समय दिया, उसके लिए मैं अपने नेतृत्व और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अभिभाषण से पहले जब सरकार सत्ता में आयी तो पहले एक अन्तरिम बजट लाये। उसके बाद में पूरा बजट आया। मुझे लगता है कि 168 पॉइंट्स का जो अभिभाषण पढ़ा गया है, उसमें उस बजट को लेकर सरकार जो अपनी मंशा रखती थी पिछले बजटों को लेकर, उसमें और इस अभिभाषण में बहुत जगह दुराभाव है। कहीं कुछ आंकड़े हैं, कहीं कुछ आंकड़े हैं, कहीं कुछ आंकडे हैं।

मैं अपनी शुरुआत खासतौर से चिकित्सा व्यवस्था को लेकर करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जिस नीयत के साथ चिरंजीवी योजना की घोषणा की थी, जिसमें लाखों लोगों को 25 लाख रुपये का इलाज मुफ्त मिल रहा था, उसे इस सरकार ने आते ही बन्द कर दिया और इस नीयत से बन्द कर दिया कि यह हमारी सरकार द्वारा लायी हुई योजना थी। इस बात का विवेक इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि जो इंश्योरेंस कम्पनीज उसका इलाज कर रही थीं फ्री में, उनको हमारी सरकार ने लास्ट ईयर में 1140 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया था। इनकी मंशा दिखाती है कि ये लोगों की चिकित्सा सेवाओं को लेकर गम्भीर नहीं हैं।

जितने भी मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किये थे, उन्हें बन्द कर दिया, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल चले जाएं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सा का केन्द्र है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आज आईसीयू नहीं मिल रहे। मरीज इधर से उधर दौड़ता रहता है, टैस्ट्स नहीं हो रहे। इसी तरीके से हमारे आरयूएचएस में चले जाएं, आप आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल हो, चाहे आरयूएचएस हो, चाहे जयपुर का महावीर हॉस्पिलटल हो, यहां पर डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। और तो और दवाइयां भी नहीं हैं। सरकार ने पिछले साल जितनी बातें कीं, आप आंकड़े उठाकर देख लें। दवाइयां नहीं खरीद पा रही सरकार, इलाज तो बहुत दूर की बात है। जब मरीज जाता है, डॉक्टर दवाई लिख देता है, दवाई नहीं है मेडिकल स्टोर्स पर। इनके ड्रग स्टोर्स जो हैं, जहां दवाइयां मिलती हैं, वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं।

सारे सैटेलाइट हॉस्पिटल्स, जितने भी मेरे इलाके में हैं और जितने भी जयपुर में हॉस्पिटल्स हैं, उनमें दवाइयों की कमी है। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार ने किसी भी

भावना से काम किया हो, आरजीएचएस की क्या हालत है आज? अब आप ही बताइये, इनसे पूछिये, इतने सीनियर लोग बैठे हैं, आरजीएचएस आपने बन्द कर दी। एक रिटायर्ड आदमी, जो घर से बाहर नहीं जा सकता, बेड पर है, उसको बायोमीट्रिक से दवाइयां कैसे मिलेंगी? आप खुद अपना विवेक इस्तेमाल करिये। किस तरीके से वह जाकर अपनी दवाइयां लेकर आयेगा? आपने सारे सप्लीमेंट्स उसके बन्द कर दिये। 65 साल की उम्र के बाद तो सप्लीमेंट्स भी चाहिये रिटायर्ड आदमी को। वे भी बन्द कर दिये आपने। आरजीएचएस का भट्ठा बुलवा दिया। दवाइयां नहीं हैं।

उसी तरीके से, चाहे कितनी ही बातें कर लें, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, कई सारे मेडिकल कॉलेज बन्द कर दिये। अखबारों में रोजाना पढ़ रहे हैं कि उनमें से कई जगह निर्माण शुरू हो गया था, पैसा लग गया था, बिल्डिंग्स शुरू हो गईं, वे मेडिकल कॉलेज बन्द कर दिये। इसका क्या तुक है? सरकार को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहिये। यह देखकर काम नहीं करें कि पिछली सरकार ने कोई अच्छा काम किया था तो हम उसे कंटीन्यू नहीं कर सकते। यह क्या बात है? अच्छी स्कीम्स को भी बन्द कर रहे हैं? सारी वैलफेयर स्कीम्स को बन्द कर दिया। आज किसी परिवार में दुर्घटना हो जाये तो दुर्घटना बीमा टाइम पर नहीं मिल रहा है। सारी स्कीम्स बन्द कर दीं।

राज्य सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर रही है। रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, इस राइजिंग राजस्थान में आपने 35 लाख करोड़ के एग्रीमेंट्स की बात की, उनमें से 80 प्रतिशत एग्रीमेंट्स सोलर के हैं। सोलर का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, ये हमारे राजस्थान के नहीं हैं। ये बड़ी-बड़ी बाहर की कम्पनियां आ रही हैं। बाहर की कम्पनियां यहां आकर जमीन का काम करना चाहती हैं। यह जमीन की लूट है। जमीन पर नजर है। यहां जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा, उसकी एक भी यूनिट का फायदा राजस्थान के निवासियों को नहीं होने जा रहा है। यह सारी की सारी बिजली एनटीपीसी बाहर ले जायेगी और यह सारी बिजली दूसरे स्टेट्स को जायेगी। अगर आपको यह करना है तो राजस्थान सरकार अपना खुद का उत्पादन करे, जिस तरीके से बिजली बनाती है, सोलर के प्लांट्स भी खुद लगाये। खुद की जमीन पर लगाये। खुद का उत्पादन हो। इंडस्ट्री को बिजली सस्ती कर दीजिये आप।

आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली अगर कोई इंडस्ट्रीज की महंगी है तो राजस्थान में है। हम बिजली उत्पादन का इतना बड़ा भू-भाग दूसरों के लिए समर्पित कर रहे हैं, लेकिन एक पैसा यूनिट राजस्थान के लोगों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। कुसुम योजना में हमने बहुत सारी बातें करीं। अभिभाषण में बताया गया कि कुसुम योजना में जो लोग घरों पर और बिजली के प्लांट्स जो खुद लगा रहे हैं 1 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाट, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, इसकी आप जांच करा लें। मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराएं।

इंडस्ट्रियल एरियाज की बात की। ये जो 11-12 इंडस्ट्रियल एरियाज की आप बात कर रहे हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हमारी सरकार में ओपन हो चुके थे। हमने बिडिंग करके शुरू

कर दिया था इनको, उद्योगपतियों को आवण्टन शुरू कर दिया था, ऑलरेडी फैक्टरीज लगना शुरू हो गयी थीं और आज इसके अन्दर वर्णन कर दिया कि हम 11 इंडस्ट्रियल एरियाज नये लेकर आ रहे हैं। नया इंडस्ट्रियल एरिया एक भी नहीं बनाया। हमारी नीयत थी। हमारी सरकार ने हर तहसील में एक इंडस्ट्रियल एरिया की बात की थी। उसी पर हम अमलीजामा पहना रहे थे। उसी में से 11-12 इंडस्ट्रियल एरियाज की आपने बात की है।

चाहे आप महिला सशक्तीकरण की बात करें, राजस्थान में अभी जितना भी डेटा आ रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी बहन-बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। एक बात और गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हमारा ध्यान नहीं है। जो लोग आज गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उनको मिल ही नहीं रहे खोने वाले लोग। किसी के परिवार से यदि कोई बहन, बेटी, बच्चा गायब हो जाये तो सरकार उसका पता नहीं कर पा रही। इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। इसकी गहराई में जाना पड़ेगा।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): इतना असत्य बोल रहे हैं विधान सभा में। अपराध बहुत कम हो गये हैं। कांग्रेस के राज में अपराध थे।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): आप बैठिये, आप डेटा देखिये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कांग्रेस के राज में अपराध थे। भट्टी में झोंक देते थे जिन्दा।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आपको चुभ क्यों रही है, यह बताइये।

mkd/rtm/03.02.2025/18:40/3p

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापतिः आप आसन को सम्बोधित करें। आप इधर बोलिये। माननीय, सदस्य आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी बात अगर कोई सदन में रख रहा है तो उसको एप्रिसिएट करिये। हम आपके खिलाफ नहीं हैं। हम आपको राह दिखाना चाह रहे हैं। सत्य बोल रहा हूं। आपकी चर्चा तो बाहर होती हैं। आप कितना सत्य बोलते हैं। आप बैठियें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): राजस्थान उड़ता पंजाब बन रहा है। इनके कहां हैं, देखने वाले। जयपुर में ड्रग्स पूरे हरियाणा से लगता हुआ इलाका, पूरे पंजाब से लगता हुआ इलाका भरभर कर ड्रग्स की ट्रेनें आ रही हैं। आप लोग उस पर कोई ध्यान दे रहे हैं? आपका विषय नहीं है यह। आप बैठिये।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी बात

कड़वी जरूर होती है, लेकिन सुनने की झमता होनी चाहिए। मैं आपसे ही आग्रह कर रहा हूं। सभापति जी, इनसे यह पूछिये कि कितना ड्रग्स का काम हो रहा है। ड्रग्स के जितने भी लोग हैं।

श्री सभापतिः वे जवाब दे देंगे, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): पहले ड्रग्स का काम जयपुर में होता था, जयपुर से सौ किलोमीटर के एरिये में ड्रग्स बिकने लग गई। इनको किसी को इस बात का पता नहीं है। ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी नस्लें खराब हो रही हैं।

श्री सभापतिः प्लीज-प्लीज माननीय सदस्य।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): अच्छा आपको बुरा लग रहा है। मैं बदल देता हूं, मौंजू। आप बैठिये। अब यूडीएच की बात कर लें। यूडीएच मंत्री जी यहां से चले गये।

श्री सभापतिः प्लीज, आपका नम्बर आये, तब बोल देना। अपना नम्बर आये, जब बोल लेना, उनको बोलने दो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनसे कहो कि सच बोलें।

श्री सभापतिः आप आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूडीएच मंत्री अभी यहां थे, वे चले गये। सरकारी नौकरियां, सफाई कर्मचारियों की नौकरियां इन्होंने क्यों रोकी? वादा करके क्यों रोकी? घोषणा हमने की थी, उसके बाद रद्दोबदल इन्होंने कायदे में कर दिया तो करते उसको।

श्री सभापतिः आप अपनी बात कीजिये। समय कम है।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): समय है।

श्री सभापतिः नहीं है, 10 मिनट 18 सैकेंड हो गये हैं।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): मैं अपनी दो बात कहकर खत्म करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने यहां पर आश्वासन दिया था, अगर सदन का नेता, अगर पूरे हाउस को कोई आश्वासन दे तो आप यह बताइये कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मेरा नाम भजन लाल है, मैं यहां कहना चाहता हूं कि बाजरे की खरीद एमएसपी पर होगी, हुई क्या एमएसपी पर? की क्या आपने? आपने की क्या? दूसरी बात सुनिये, ये यूडीएच मंत्री जी, जिन्होंने यहां पर घोषणा की थी कि मैं रामबाग गोल्फ क्लब की एसओजी से जांच करवाऊंगा, इन्होंने की क्या? की क्या इन्होंने? आप सदन को असत्य बोलते हैं, आप पूरे राजस्थान की अवाम को गुमराह करते हैं, आपको भविष्य माफ नहीं करेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सुभाष जी मील। श्री सुभाष जी मील। श्री थावरचंद जी। एक मिनट, आ गये।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का समय देने के लिए बहुत-बहुत आभार। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण जो सदन में पढ़ा गया, यह केवल एक अभिभाषण नहीं था, वरन एक साल

का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो सरकार की गौरव यात्रा थी, उसके बारे में बताया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि हाल की सरकारों में, चाहे वह किसी पार्टी की सरकार पहले रही हो, लेकिन हाल के वर्षों में यह पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी रही है, जिसने जो पहला बजट प्रस्तुत किया, इस सदन में, उसका 95 परसेंट तक धरातल पर उतारा गया, यह पहला ऐसा बजट है। मैं भी पूरे दिन से वाद-विवाद, जो विपक्ष के सदस्य रख रहे थे, जो तथ्य रख रहे थे, उनको पूरे ध्यान से सुन रहा था। एक भी ऐसा आरोप, उन्होंने इधर-उधर की बातें कीं, लेकिन एक भी ऐसा आरोप वो नहीं लगाये पाये कि आपकी सरकार ने बजट में यह काम दिया था, लेकिन वह काम आपने पूरा नहीं किया। वे एक भी काम गिनाने का काम नहीं कर सके। यह बात हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर अगर सबसे बड़ी कोई जन समस्या है तो वह पानी की समस्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी गम्भीरता को समझते हुए, सबसे पहले अगर किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया तो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए काम किया। चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे इन्दिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं हों, इनके लिए मुख्य मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाने का काम किया है।

अभी एक वरिष्ठ विपक्ष के सदस्य कह रहे थे, हमारे जिले से आते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया कि एक लोटा जल पानी का नहीं आयेगा। हमें शर्म आनी चाहिए यह कहते हुए, अभी तो आपको सत्ता से गये 12 महीने का समय निकला है। सभापति महोदय, मैं माननीय विपक्ष के सदस्य को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक इच्छाशक्ति दिखाई है। हमारी सरकार ने पानी पर काम करना शुरू किया है, धोरे में भी पानी आने में समय लगता है।

सभापति महोदय, यह तो यमुना का पानी है, थोड़ा आने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश की पानी की समस्या का कोई हल करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नेतृत्व वाली सरकार करेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई मंत्री हो, आज प्रदेश की युवाओं से आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है। उसको नजरें नीची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 महीने में जो भी भर्तियां सरकार ने आयोजित कराई हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी माननीय विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि कितनी भर्तियां हुई हैं, कितनी नियुक्तियां हुई हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं सदन के माध्यम से उनसे कहना

चाहता हूं कि माननीय एक साल में 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं और 1 लाख 72 हजार 990 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिसमें से 81 हजार पदों का भर्ती कलेंडर जारी किया जा चुका है, कई बार समझ में नहीं आता, जब आपको यह अहसास ही नहीं होता कि हम सत्ता से दूर गये हैं। आपको सत्ता से गये माननीय 14 महीने का समय हो चुका है, आंखें खोलकर देखिये, राजस्थान प्रदेश निरन्तर आगे से आगे प्रगति करता जा रहा है। इन 14 महीनों में, मैं सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को और हमारी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि चाहे विपक्ष कितनी भी बड़ी बातें लगाये, आरोप लगाने में विपक्ष अपने आप में माहिर है, हमारे एक भी मंत्री पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने में अभी विपक्ष समक्ष नहीं हुआ, एक भी जगह से आपने आवाज इस सदन में नहीं सुनी कि हमारा कोई मंत्री कोई गड़बड़ में शामिल हो जाये।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, पूरे वक्ता कह रहे थे।

Bhs/Rtm/03.02.25/18.50/3q

सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में कह रहे थे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ में होगी, किसी भी तरह की गड़बड़ सफाई कर्मचारियों की भर्ती में नहीं होगी चाहे दो दिन का समय लग जाये क्योंकि हमारी सरकार की यह मंशा है कि कोई भी गलत अभ्यर्थी भर्ती में शामिल न हो पाये इसलिये मैं सदन को कहना चाहता हूं कि प्रदेश में किसी विभाग की भर्ती हो चाहे, पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां होंगी और गिनते जाइये, मैं कहना चाहता हूं अभी जो कह रहे थे उँगली उठा कर आरोप लगा रहे थे, गिनते जाइये अभी गिनती शुरू हुई है, चार लाख भर्तियों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है, एक भी भर्ती पांच साल में कम नहीं होगी, इस बात का मैं सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं और यह करके दिखाया है।

माननीय सभापति महोदय, थोड़े दिनों पहले जब प्रदेश में उपचुनाव हुए तो प्रदेश के युवाओं ने इस सरकार में भरोसा जता कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया है और इनकी जो पार्टी है विपक्षी दल की, इनकी तीन-चार जगह जमानत जब्त कराने का काम किया है क्योंकि प्रदेश का युवा जानता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व की सरकार है जो युवा इसमें मेहनत करेगा, निश्चित रूप से उसको सरकारी नौकरी मिलेगी यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब चार साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुबारा चुनकर जब सत्ता में आयेगी तो इन लोगों को एहसास होगा कि जब कोई सरकार पूरी

निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से युवाओं के हितों में फैसला लेती है तो वह युवा दुबारा उस सरकार को लाने का काम करते हैं, इनकी समझ में आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि सरकार के पहले साल में इतने अच्छे तरीके से एक बृहद् स्तर पर राइजिंग राजस्थान, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया और केवल आयोजन ही नहीं किया बल्कि हर महीने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की समीक्षा हो रही है और हर महीने हजारों-करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. रोजाना हर महीने यहां पर प्रदेश में हो रहे हैं जो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के लिए प्रगति के द्वारा खोलने का काम करने वाले हैं।

मैं विपक्ष के सदस्यों को सुन रहा था। पूरा दिन निकल गया इनके बड़े-बड़े वक्ता बोल गये लेकिन राइजिंग राजस्थान पर एक शब्द ये नहीं बोले। लास्ट में एक महोदय खड़े हुए और उन्होंने यह कहा कि सरकार की जमीन पर नजर है। शर्म आनी चाहिये, जब कोई सरकार चाहे किसी की हो, चाहे हमारी पार्टी की हो, कोई अन्य पार्टी की हो, जब सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश में रोजगारों का सृजन करने के लिए अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कराती है, इस तरह से युवाओं को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त करने का काम करती है तो उस पर किसी को उँगली नहीं उठानी चाहिये, यह मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इनके एक वरिष्ठ साथी जो मेरे ही जिले से आते हैं वो कह रहे थे जो केन्द्र का आम बजट अभी पेश हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि राजस्थान को कुछ नहीं मिला।

(समय : बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि यह आम बजट केवल विपक्ष के लिए निराशा का बजट है पूरे देश में आम बजट के लिए तालियों की गूंज सुनायी दे रही है यह मैं आपको कहना चाहता हूं और अगर देश के इस आम बजट से किसी प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वह प्रदेश राजस्थान है क्योंकि राजस्थान ....।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

साहब, दो मिनट प्लीज। अभी मेरा समय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः हो गया आपका। अभी एक सज्जन और हैं सात बजे तक का टाइम है।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं सात मिनट का समय हुआ है। राजस्थान उद्योगों के क्षेत्र में...। माननीय सदस्य, एक बार आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्षः बैठिये। श्री थावर चन्द।

श्री सुभाष मील (खंडेला): साहब, मुझे दो मिनट का समय दीजिये। मैं दो मिनट का समय और लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः दस मिनट हो गये आपको। अब दो मिनट नहीं।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में केवल यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः हो गया। अब अंकित नहीं होगा।

श्री सुभाष मील (खंडेला): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आप बोलें।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया, मैं आज एक अत्यंत अति संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे आदिवासी समाज के अस्तित्व, अधिकारों और न्याय से जुड़े हुए मामले की ओर। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से जिसे संविधान ने आदिवासी समाज की संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के लिए आरक्षित किया है वहां आज तक बड़ा अन्याय हो रहा है। वनाधिकार अधिनियम, 2006 और संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिवासी को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिये गये हैं। ये वो आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, अपने पुरखों की विरासत को बचा कर रखते हैं और आज तक उनके साथ में रहते आये हुए पेड़ों को पूजते हैं पर्वतों को भगवान मानते हैं ऐसे में उन आदिवासियों के साथ में सबसे बड़ा संवैधानिक धोखा हो रहा है। खनन के नाम पर गैर आदिवासी को और गैर सरकारी संस्थाओं को वहां पर पट्टे दिये जाते हैं, यहां पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि सवाल यह उठता है कि एक देश, एक राज्य, एक संविधान है तो आदिवासियों के साथ में दोहरा व्यवहार क्यों? जब खनन कम्पनी को जंगल की भूमि देने की अनुमति दी जा सकती है तो आदिवासी को वनाधिकार के पट्टे क्यों नहीं दिये जा सकते हैं? जब गैर आदिवासी पूंजीपति को खनिज दोहन की छूट दी जा सकती है तो वनों के असली रक्षक आदिवासी को जंगल से बाहर क्यों निकाला जाता है? मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल ही में कई ऐसी कम्पनियां हैं जिनको जैसे अडानी ग्रुप के नाम पर जो सोने की खाने निकाली जायेंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राटड़ी, डगोसा, आमलवास गांव हैं जहां पर सोने की खान के नाम पर अवाप्त करने की बात चल रही है। दूसरी ओर, बांसवाड़ा के अन्दर पॉवर प्लान्ट के नाम पर जमीन छीनने की बात की जा रही है। आखिर हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा द्वेषतापूर्ण अन्याय क्यों? एक पेड़ मां के नाम दूसरी ओर आदिवासियों के जंगल अडानी और वेदान्ता के नाम।

अनूसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों का त्वरित वितरण किया जाये यह हम आपको कहना चाहेंगे। आदिवासी भूमि पर बाहरी कम्पनियों द्वारा खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाये। मैं साथ-साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में जंगल सदियों से वहां निवास करने वाले आदिवासी आजीविका चलाते हैं, यह उनके सांस्कृतिक परम्पराओं का अभिन्न अंग है परन्तु वन भूमि के प्रशासनिक नियंत्रण और बाहरी दखलंदाजी के कारण ये जंगल धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे हैं।

मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि यह जंगल जो वन समितियां हैं सीधे उनके द्वारा संचालित हो और वन समिति को दिया जाये और आप यदि दस साल के लिए वन समिति के नाम पर इन आदिवासियों को अगर जंगल की सुरक्षा देते हो, हम गारंटी लेते हैं कि दस साल के अन्दर सारे जंगलों को हरा-भरा कर देंगे और दस साल में यदि हरा-भरा नहीं होता है तो आप यह जंगल वापस ले लीजिये। यह आपको कहना चाह रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जल विविधता संरक्षण को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा साथ ही इनसे वन संसाधनों के अवैध दोहन और अतिक्रमण पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। मैं साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जरूरी बात करना चाहूंगा कि हमारे एक महत्वपूर्ण आस्था से जुडी हुई मांग को उठाना चाहता हूं। यह मांग केवल भूमि से जुडी हुई नहीं है बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, परम्पराओं और आध्यात्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल बेण का टापू है जहां हजारों साल से आदिवासी समुदाय के लोग माघ पूर्णिमा को अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने आते हैं। साथ-साथ में फूल चढ़ाने, बाल, नाखून, हड्डी, राख विसर्जन करने आते हैं। वहां पर आदिवासियों के नाम पर सब कुछ नहीं है। वहां पर अन्य लोगों के नाम पर जमीनें दी जाती हैं, जमीनें अलॉट कर दी जाती हैं तो आदिवासी आस्था के साथ में बड़ी गहरी चोट है और मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी इस सदन के माध्यम से मांग है कि जो हमारा आस्था का केन्द्र है बेण का टापू इसमें अस्सी प्रतिशत जमीन आदिवासियों को प्रकृति पूजा स्थल विकसित करने के नाम पर दी जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सांस्कृतिक केन्द्र, पूजा स्थल, पारम्परिक वन संरक्षण क्षेत्र और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए स्थान विकसित किये जायें। गैर आदिवासियों को बेण का टापू में दी गई भूमि की पुन: समीक्षा की जाये और यदि कोई भूमि अतिक्रमण में पायी जाती है तो उसे मुक्त करा कर आदिवासी समाज को सौंपा जाये।

मैं इस दौरान यह भी कहूंगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2024 की बजट घोषणा में यह बात भी कही थी कि प्रदेश में तीन नवीन महिला बटालियन खोली जानी प्रस्तावित हैं। यदि ऐसा है तो भील काली बाई कलासुआ का सम्बन्ध दक्षिणी राजस्थान से है। दक्षिणी राजस्थान की कानून-व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आपसे विशेष अनुरोध कि भील काली बाई कलासुआ के नाम से दक्षिणी राजस्थान में बटालियन खोली जाये, जिससे अनुशासन बढ़ेगा, कानून-व्यवस्था बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, टाइम हो गया।

श्री थावर चन्द (धरियावद): मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा कि हाल ही में हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक चर्चित नाम आता है सुशीला पारगी क्रिकेट खिलाड़ी का और वह

भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी ने भी उसको ट्विट किया था तो मैंने विधान सभा में...।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दिनांक 5 फरवरी, 2025 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

****